[Shri Parimal Ghosh]

other three after admission in hospital, thus bringing the total number of dead to 12. Of the remaining 42 injured persons, the injuries of seven persons are reported to be of a serious nature.

Immediately on receipt of the information, the Divisional Medical Officer, Bitragunta rushed to the site of the accident in the medical van. Medical relief vans from Madras and Gudur with railway and private doctors were also rushed to the site. The injured passengers were brought in requisitioned lorries for admission in the hospitals at Nellore and Gudur. Thirteen persons, four with serious injuries are in Nellore hospital and fourteen persons, three with serious injuries are in Nellore hospital and fourteen persons, three with serious injuries are in Gudur hospital. The rest have been discharged.

The Chief Operating Superintendent and the Chief Medical Officer of the South Central Railway left for the site of the accident by road. The Divisional Officer from Bezwada also has proceeded to the site of the accident.

Ex-gratia payment has been arranged to the injured and the next of kin of those who have died.

An Administrative Officer's inquiry has been ordered, which will begin on 12-3-68. The cause of the accident is under investigation.

श्री रवि राय (पुरी) : 12 मर चुके हैं और मंत्री महोदय कहते हैं कि 7 मरे हैं।

SHRI SEZHIYAN (Kumbakonam) : This is a serious matter.....

MR. SPEAKER : On Minister's statements questions are not asked. Let us not create any new precedent.

12.36 Hrs.

GENERAL BUDGET—GENERAL DISCUSSION—*contd.*

MR. SPEAKER : The House will now take up further discussion of the General budget, for which 20 hours have been allotted. We have already taken 1 hour and 45 minutes. Shri K. N. Pandey will continue his speech. He has already taken 17 minutes.

श्री काशी नाथ पाण्डेय (पदरौना) : अध्यक्ष महोदय मैं ने उस दिन बोलते हुए यह कहा था कि कोई भी देश केवल खेती पर निर्भर रह कर उन्नति नहीं कर सकता। आर्थिक रूप से उन्नति के लिये उसमें औद्योगीकरण होना ही चाहिये। लेकिन औद्योगीकरण के लिये भी आवश्यक है कि वहां पर सुव्यवस्था हो, ला ऐंड आर्डर हो। लेकिन आज कल देश की जो हालत है उसको देख कर चिन्ता होती है। जो भी इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं उनमें शांति नहीं है। किसी न किसी कारण से वहां झगड़े होते रहते हैं, और मुझे यह कहने में भी कोई हिचक नहीं है कि बहुत से लोग प्रजातंत्र की वजह से उन्नति के रास्ते पर तो आते हैं मगर चूंकि उसमें उनकी आस्था नहीं है इसलिये वह प्रजातंत्र के दिये हुए अधिकार तो लेते हैं, मगर उन के जो कर्तव्य हैं उनको वह बिल्कुल भूल जाते हैं। यही कारण है कि आज देश में औद्योगिक अशांति है। हालांकि यह विषय वित्त मंत्री जी का सीधे तौर से नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी चूंकि सभी विभाग वित्त विभाग पर आश्रित हैं तो उनको देखना पड़ेगा कि देश के खेती पर पूरी तरह से निर्भर रह कर हम आर्थिक रूप से उन्नति नहीं कर सकते और यदि देश की उन्नति होनी है तो उसका औद्योगीकरण करना होगा, दूसरी बात यह है कि देश में औद्योगिक शांति रहे।

अब प्रश्न यह उठता है कि यहां पर छोटे उद्योग लगाये जायें या बड़े उद्योग। इस सम्बन्ध में मैं एक बात बतलाना चाहता हूं कि पहले इस देश में फैली हुई बेकारी की समस्या को हल करना है और यह छोटे उद्योगों से ही हो सकता है तो इसके लिये कोशिश की जानी चाहिये। लेकिन केवल इस लिये कि छोटे उद्योग वर्त्तमान दशा में उन्नति नहीं कर रहे हैं इस लिये बड़े उद्योगों पर पाबन्दी लगादी जाय किसी न किसी तरह से, तो मेरे खयाल में देश के हित में यह उचित बात न होगी। आप ने यहां जो एक इंडस्ट्रियल पालिसी रेजोल्यूशन पास किया है, उस प्रस्ताव के

मुताबिक आप लोगों को लाइसेंस भी देते रहे और उद्योग लगते रहे। इसके बाद शायद आप का खयाल हुआ कि इस इंडिस्ट्रियलाइजेशन में सोशलिज्म कुछ पीछे पड़ गया, इस लिये आपने एक कमेटी बिठलाई। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी। उस पर यहां जो बहस हुई, में समझता हूं कि वह समय एक प्रकार से बेकार गया। उस से कुछ लाभ होता अगर हम किसी तरह से कोई समाधान पाते। यहां तो केवल यही बात होती रही कि यह इंडस्ट्री यहां नहीं लगनी चाहिये, वहां नहीं लगनी चाहिये, यह अमुख के घर में नहीं जाना चाहिये।

मैं तो कह रहा हूं कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप कोई स्कीम बनाइये। छोटे छोटे उद्योग लगने हैं तो कोआपरेटिव बना उन्हें ही लाइये। पर आज छोटे उद्योगों पर ज्यादा रिसेशन है, बड़े उद्योगों पर उसका प्रभाव जरा कम है। आज बड़े उद्योगों में क्षमता है उसको बर्दाश्त करने की। आज इस चीज को हमें देखना पड़ेगा नहीं तो रिपोर्टों पर जो बहसें होती हैं वह केवल समय की बरबादी है और उनसे कोई लाभ होने वाला नहीं है।

दूसरी चीज में यह कहना चाहता हूं कि हमारे देश को अगर किसी से शिक्षा प्राप्त हो सकती है इन मामलों में तो वह इंग्लैंड और अमरीका से नहीं हो सकती है, वह जर्मनी या जापान से हो सकती है। जर्मनी और जापान दोनों ही क्षतिग्रस्त देश थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने काफी तरक्की की है क्योंकि वह राष्ट्र को उन्नत बनाना चाहते थे।

आज कम्युनलिज्म, रिजनलिज्म, कास्टिज्म आदि चीजों का तथा दूसरी स्वार्थ की चीजों का बाहुल्य है, इनका बोल-बाला है। इन सब को देखते हुए मेरी समझ में नहीं आता है कि हम सोशलिज्म की तरफ जा रहे हैं या सोशलिज्म के खिलाफ जा रहे हैं। ये चीजें ऐसी हैं, जिनकी तरफ ध्यान हमारे देश को देना चाहिये।

यहां बड़ी चर्चा होती है कि मोटर के कारखाने लगने चाहियें। मगर इसमें मेरी दिलचस्पी नहीं है। मैं समझता हूं कि आज देश को जरूरत है ट्रैक्टरों की ताकि देश की कृषि को उन्नत किया जा सके। आज देश को लग्जरी का सामान जैसे मोटर आदि बनाने के लिए कारखाने स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आम तौर पर देखन में यही आता है कि इस पर ही ज्यादा जोर दिया जाता है। आप इस पर चर्चा क्यों नहीं करते हैं कि देश में ट्रैक्टर की फैक्ट्रियां लगें, यहां पर सस्ते दामों में ट्रैक्टर बनें ताकि किसानों को उनको उपलब्ध किया जा सके और खेती की उन्नति हो सके। मैं चाहता हूं कि इस ओर आप ध्यान दें।

मैं इस दलील को मानता हूं कि दूसरे देशों में पोस्ट कार्डों और लिफाफों तथा दूसरी चीजों के दाम अधिक हैं। हमारे यहां ये कम हैं। लेकिन आप देखें कि ये दाम वहां आज ज्यादा नहीं हुए हैं। पहले से ही ज्यादा चले आ रहे हैं। आप ने तो पांच पैसे की वृद्धि हर चीज पर कर दी है। उसका नतीजा यह हुआ है कि लोगों को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। मैं वित्त मंत्री से अपील करता हूं कि अगर आपको इनके दाम बढ़ाना ही है तो दो-दो पैसे सब पर आप बढ़ा दें। पांच पैसे इस वक्त बढ़ाना न केवल आर्थिक दृष्टि से बल्कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी ठीक नहीं होगा। इसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं आशा करता हूं कि मेरे इस सुझाव पर वित्त मंत्री जी विचार करेंगे।

जो लोग तम्बाकू पीते हैं, उनके साथ मेरी कोई सहानुभूति नहीं है इसलिए कि मैं तम्बाकू नहीं पीता हूं। इस वास्ते में इसके बारे में कुछ विचार प्रकट करना नहीं चाहता हूं।

मैं इस बात को मानता हूं कि सरकारी खर्चे में इकोनोमी करने की जरूरत है जहां हम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडीचर में कमी करने की बात पर जोर देते हैं वहां हम उससे भी ज्यादा जोर जो बड़ी-बड़ी प्राजेक्टस हैं वहां

[श्री काशी नाथ पाण्डेय]

पर इकोनोमी करने पर देना चाहिये। वित्त मंत्री जी ने एक ही चीज की है और वह यह कि जो इंसीडेंटल चार्ज दिया जाता है, टी० ए० के साथ उसको उन्होंने घटा दिया है। इसका परिणाम यह हुआ है कि जो छोटे-छोटे अफसर हैं वे जब कभी कहीं बाहर जाते हैं, इंसीडेंटल चार्ज घट जाने से उनको खाने के लिए मुश्किल होती है। आप अगर इकोनोमी करना चाहते हैं तो उसका काफी स्कोप बड़ी-बड़ी प्राजैक्ट्स में है। वहां पर रुपया उसी तरह से बह रहा है जैसे गन्दी नाली में चीजें बह रही होती हैं। वहां पर तो खर्च पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं वहां पर तो कोई इकोनोमी मैशर्ज एडाप्ट नहीं किये जाते हैं लेकिन यहां किये जाते हैं। सीधे-सीधे जिनका एडमिनिस्ट्रेशन आपके हाथ में है वहां आप इकोनोमी कीजिये। लेकिन इन छोटे लोगों की कीमत पर आप न करें।

एक बात मैं अपने क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूं। मैं ईस्टर्न यू०पी० से आता हूं। वहां पर अधिकतर लोग खेती पर ही निर्भर करते हैं। एक वर्ग मील पर लोगों की आबादी भी वहां बहुत ज्यादा है। वहां पर गरीबी बहुत ज्यादा है। इसको दूर करने के लिए प्लानिंग कमीशन ने एक पटेल कमेटी बिठाई थी। उसने यह सिफारिश की थी कि इस इलाके की उन्नति केवल खेती पर निर्भर रह कर नहीं हो सकती है। यहां पर छोटे-छोटे उद्योग धंधे भी लगने चाहियें। उसकी रिपोर्ट के मुताबिक साल भर तो वहां काम होता रहा। लेकिन अब वह ठप्प कर दिया गया है। मैं अपील करना चाहता हूं कि वित्त मंत्री जी से उधर भी वह ध्यान दें। अगर ऐसा नहीं किया गया तो गरीब गरीब ही रह जायेंगे। यहां पर अकसर चर्चा होती है कि एक सूबा दूसरे से पिछड़ा हुआ है, एक भाग दूसरे भाग से पिछड़ा हुआ है एक रिजन दूसरे रिजन से पिछड़ा हुआ है। मैं चाहता हूं कि यह जो पिछड़ापन है इसको दूर किया जाए और ईस्टर्न यू०पी० के लिए आपने जो कार्यक्रम अपनाया था उसको आप जारी रखें।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस सरकार की लगातार बीस साल की गलत नीतियों ही के कारण आज देश की अर्थ व्यवस्था टूट रही है। इस बजट के जरिये से क्या इसमें कुछ सुधार आएगा, यह एक सवाल है जिसका हमें जवाब ढूंढना है।

आज कीमतें बढ़ रही हैं। इंडस्ट्री में रिसैशन है। एडवर्स बैलेंस आफ ट्रेड है। एक्सपोर्टस हमारी कम हो रही हैं। लोग भूखे मर रहे हैं। देश की इस हालत को सामने रखते हुए वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है क्या उससे इसमें कोई सुधार हो सकेगा, यह सोचने वाली बात है। मेरा खयाल है कि यह एक रुटीन टाइप का बजट है। स्टेटस को बजट है। इसमें कोई बहुत क्रांतिकारी कदम उठाया गया हो, ऐसा मैं नहीं कह सकता हूं जिस तरह की अवस्था आज देश की है, विशेषतः आर्थिक, उसके अन्दर जब तक कोई डिनामिक एप्रोच बजट में नहीं होगी तब तक देश की अर्थ व्यवस्था ठीक नहीं होगी। मुझे दुख है कि यह रूटीन टाइप का, टेम, स्टेटस को और लीगल जो फार्मेलटीज हैं उनको केवल मात्र पूरा करने के लिए बजट तैयार किया गया है और हमारे सामने पेश किया गया है। इसके आगे इसके अन्दर कुछ नहीं है। हो सकता है कि कुछ लोग इसको अच्छा बजट कहें क्योंकि इसमें कम टैक्स लगाये गए हैं। इसमें जो एनुटी डिपाजिट को खत्म किया गया है, सर टैक्स में कुछ कंसेशन दिया गया है, डिवेलेपमेन्ट टैक्स में कंसेशन दिया गया है, वे अच्छी चीजें हैं और उनका मैं स्वागत करता हूं। लेकिन मौलिक रूप से क्या देश की अर्थ व्यवस्था इससे ठीक होगी यह एक सवाल है जिसका उत्तर हमें ढूंढना है।

हमारे वित्त मंत्री जी ने पिछले साल एक भीष्म प्रतिज्ञा की थी कि डिफिसिट फाइनेंसिंग

वह नहीं करेंगे। मैं मानता हूं कि डिफिसिट फाइनेंसिंग भी कई बार जरूरी होता है और उसका लाभ भी होता है। लेकिन इस भीष्म प्रतिज्ञा को करने के बाद मंत्री महोदय ने जो एक दम समर साल्ट किया है, इसका क्या कारण है, समझ में नहीं आया है। मैं समझता हूं कि अच्छे सेल्जमैन की तरह उन्होंने यह बतलाने की कोशिश की है कि इस डिफिसिट फाइनेंसिंग से डिमांड बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी, कीमतें नहीं बढ़ेंगी और देश का कल्याण होगा। एक अच्छे सेल्ज मैन की हैसियत से उन्होंने यह काम किया है। लेकिन यह उनकी पायस होप ही सिद्ध होगी। पिछले साल भी उन्होंने डिफिसिट फाइनेंस किया था जोकि 290 करोड़ का था और इस साल उन्होंने 300 करोड़ का किया है। इस तरह से दो सालों का कुल डिफिसिट फाइनेंसिंग 590 करोड़ होता है। इस से क्या इनफ्लेशन नहीं होगा, यह सवाल हमारे सामने है।

मैं समझता हूं कि डिफिसिट फाइनेंस ने देश की इकोनोमी को धक्का पहुंचा है। जो छोटा आदमी है, जो सर्व साधारण आदमी है, जो पहले ही बोझ से दबा हुआ है उसकी कमर तो इससे बिल्कुल टूट जाएगी। तीसरे प्लान में हमने डिफिसिट फाइनेंसिंग को खतरनाक बताया था और उसकी सीलिंग 550 करोड़ पर निश्चित की थी। लेकिन इन सालों में इससे हम कई गुना ज्यादा आगे चले गए हैं। मेरी समझ में नहीं आया है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी? अभी कुछ दिन पहले पी एल 480 की भी कुछ ट्रांजैक्शंज सरकार ने की हैं। उससे डिफिसिट फाइनेंसिंग और बढ़ जाएगा। मैं समझता हूं कि इस तरह से कीमतें रुकने वाली नहीं हैं।

सरकार यह कह सकती है कि यह एक आल्टरनेटिव है टैक्सेशन का। अगर डिफिसिट फाइनेंसिंग न किया जाता तो शायद टैक्स ज्यादा लगाने पड़ते। इस सम्बन्ध में मेरा कहना यह है कि :

It is not an alternative to taxation, but it is an additional taxation of the most cruel type on fixed salaried people, on common men.

इससे कीमतें बढ़ेंगी। जो फिकस्ड सैलरी वाले हैं उन बेचारों की तनख्वाहें तो बढ़ने वाली नहीं हैं लेकिन कीमतों के बढ़ने से उनके ऊपर टैक्स लगेगा। गरीब आदमियों के ऊपर टैक्स लगेगा, मध्यम वर्ग के लोगों पर लगेगा, लोअर मिडल क्लास के जो लोग हैं उन पर लगेगा क्योंकि कीमतें बढ़ जाएंगी। यही हमारा तजुर्बा भी पुराना कहता है। यह कहना कि टैक्स नहीं लगेगा ठीक नहीं है।

जहां तक प्लानिंग का सम्बन्ध है, आपको ओवर एम्बीशस प्लान बनाने की क्या जरूरत है। हमारी पार्टी प्लानिंग के खिलाफ नहीं है। मौलिक रूप से हम चाहते हैं कि प्लानिंग हो लेकिन रीयलिस्टिक प्लानिंग होना चाहिये, व्यावहारिक प्लानिंग होना चाहिये, ऐसा होना चाहिये जो भारत की परिस्थितियों और उसकी अवस्था के अनुकूल हो। मुझे दुख है कि जो तीन प्लान बने हैं वे इस सिद्धांत के बिल्कुल परे रहे हैं। मालूम ऐसा होता है कि कागजों पर ही उनको बैठ कर बना दिया गया था।

जहां तक फूड जोंज का सम्बन्ध है, मैं कहना चाहता हूं कि यह सांप कांग्रेस का पैदा किया हुआ है। अब तो उसके बहुत से बच्चे भी पैदा हो गए हैं। पहले तो हिन्दुस्तान को तीन चार जोंज में ही बांटा गया था अब हर एक प्रांत का अलग-अलग जोन बन गया है। इतना ही नहीं अब तो जिले-जिले का, तहसील-तहसील का जोन बन गया है। उस सांप के इतने बच्चे पैदा हो गए हैं कि वे सरकार को ही खाना चाहते हैं। मैं मानता हूं कि सरकार फूड जोंज को हटाना चाहती है। लेकिन जो सांप आपने पैदा किया है वह सांप अब डंक मारने के लिए तैयार बैठा है। आपको जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है वह फूड जोंज हटाने नहीं देगी। जो कुरप्ट पालिटिक्स में काम करने वाले लोग हैं, जो पालिटिशियन हैं वे आपको फूड जोंज को खत्म नहीं करने देंगे क्योंकि उनकी चांदी होती है।

[श्री कंवर लाल गुप्त]

और सफरर कौन है? कनज्यूमर, छोटा आदमी और खेत में काम करने वाला किसान, जिस को अपनी पैदावार की ठीक कीमत नहीं मिलती है। मैं चाहता हूं कि चीफ मिनिस्टर्ज की कांफरेंस में सरकार इस बारे में मजबूती. से कदम उठाए और जिस सांप को उसने पैदा किया था, उसको अपने हाथ से ही खत्म कर दे।

इस बजट को चाहे और कुछ भी कहा जाये, लेकिन इसको जनता का बजट नहीं कहा जा सकता है। मैं माननीय मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि आजादी मिलने के बाद इन बीस सालों में देश की बागडोर लगातार उनके दल के हाथ में रही है और इस अवधि में 35,000 करोड़ रुपया देश पर खर्च किया गया है, लेकिन क्या वह आज भी लोगों को यह विश्वास दिला सकते हैं कि भारत में हर एक व्यक्ति को पेट-भर खाना, कपड़ा, रहने के लिए मकान और शुद्ध जल मिलेगा। मैं दवा-दारू, एजूकेशन और दूसरी सुविधाओं की बात नहीं करता, लेकिन अगर यह सरकार बीस सालों के बाद ये बुनियादी सुविधायें भी नहीं दे सकती है, तो फिर यह बजट जनता का नहीं हो सकता है, और किसी का हो सकता है। इस बजट को जनता का बजट बनाने के लिए यह जरूरी है यह कि सरकार लोगों को इस बात की गारन्टी दे कि उनकी बुनियादी जरूरतें पूरी की जायेंगी।

पिछले बीस वालों में यह सरकार सोती रही और उसकी नीतियां गलत रहीं। आज इस देश मे दस करोड़ इंसान ऐसे हैं, जिन की आमदनी पांच, छः आने रोजाना है, जिनका पेट नहीं भरता है, जो अन्डर नरिश्ड और इल-क्लैड हैं, जिन को रोटी, कपड़ा और मकान नहीं मिलता है। सरकार कहती है कि हम तरक्की कर रहे हैं। मैं इस से इन्कार नहीं करता, लेकिन उस तरक्की की रफ्तार क्या है? आज जब कि यह कहा जा रहा है कि जेट पुराने हो गए हैं, इसलिए और ज्यादा तेज रफ्तार के हवाई जहाज लेने चाहिए, श्री मोरारजी देसाई की सरकार बैलगाड़ी में चल रही है। जिस रफ्तार से उसको चलना चाहिए, क्या वह उस रफ्तार से चल रही है? मैंने यू०एन०ओ० के आंकड़े देखे हैं। क्या इंडोनेशिया को छोड़कर दुनिया में कोई ऐसा देश है, जिसने हमसे कम तरक्की की हो? हम सब से पीछे हैं। हमने सब से ज्यादा खर्च किया है, लेकिन आज भी हम अपने लोगों के लिए रोटी, कपड़े और मकान की गारन्टी कर सकते हैं।

इस सरकार का चार साल का टैन्योर अभी बाकी है। मैं मांग करना चाहता हूं कि वह इन चार सालों के लिए फ़ेज्ड प्रोग्राम बनाए कि वह पहले दो सालों में लोगों के लिए खाने और पीने के पानी की व्यवस्था करेगी, उसके बाद एक साल में वह कपड़े और उससे अगले साल वह मकान की व्यवस्था करेगी—मकान से मेरा मतलब कोई पैलेशल बिल्डिंग से नहीं, बल्कि सिर ढंकने के लिए शेल्टर से है। अगर यह सरकार इस तरह का फ़ेज्ड प्रोग्राम बना कर लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकती है, तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। इस बारे में इकानोमिस्टस् क्या कहते हैं, इंडस्ट्रिलिस्ट्स क्या कहते हैं और मिनिस्टर क्या कहते हैं, इन लम्बी-चौड़ी बातों से मुझे कोई मतलब नहीं है। यह बजट उस दिन जनता का बजट होगा, जब श्री मोरारजी देसाई एक डायनामिक एपरोच के साथ कहेंगे कि वह इस बात की गारन्टी देते हैं कि दो साल के बाद जनता की एलिमेन्टरी सुविधायें, बेसिक नीड्ज, पूरी होंगी, अन्यथा वह जनता का बजट नहीं ला सकते हैं।

मंत्री महोदय कह सकते है कि यह पैसा कहां से आयेगा, सरकार के पास इतना पैसा नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार ने पब्लिक सेक्टर में करीब 2400 करोड़ रुपया लगाया हुआ है। इसके अलावा रेलवेज, डिफेंस और पोस्ट्स एन्ड टैलिग्राफ्स के अन्तर्गत भी कुछ कारखाने चलते हैं। इन कारखानों की हालत क्या है? बड़ी खस्ता हालत है। आप

इन कारखानों के आंकड़े देखे जिस मिनिस्टर ने किसी कारखाने को चलाया, उस के या सेक्रेटरी के रिश्तेदार और उसकी बिरादरी के लोग उसमें घुसे होंगे।

उपप्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : यह ठीक नहीं है।

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं मंत्री महोदय को लिस्ट दे सकता हूं।

श्री मोरारजी देसाई : जरूर दीजिए।

श्री कंवर लाल गुप्त : ये कारखाने करप्शन और फैवरिटिज्म के अड्डे बन गए हैं और अगर कोई किन्हीं इनएफिशेंट लोगों का फेवर करना चाहता है, तो उनको वहां धकेल दिया जाता है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि सरकार मशीनरी को टाइटन करे। अगर प्राईवेट सैक्टर बारह या पन्द्रह नफा कमा सकता है। तो पब्लिक सैक्टर भी दस परसेंट नफ़ा तो जरूर कमा सकता है। कई कारखानों में, जैसे डिफेंस के कारखानों में, अनयूटिलाइज्ड कैपेसिटी पड़ी हुई है। जो चीजें डिफेंस के लिए बहुत जरूरी नहीं हैं, वे प्राईवेट सैक्टर को दे देनी चाहिए। प्राईवेट सैक्टर और पब्लिक सैक्टर एक दूसरे के सप्लीमेंन्टरी और काम्प्लीमेन्टरी होने चाहिए। मेरे लिए और मेरी पार्टी के लिए पब्लिक सैक्टर कोई टैबू नहीं है। मैं समझता हूं कि अगर देश को आगे ले जाना है, तो पब्लिक सैक्टर भी जरूरी है। लेकिन जिस तरह से पब्लिक सैक्टर हमारे देश में बिहेव कर रहा है, वह ठीक नहीं है। उसको और ज्यादा एफिशेंट होना चाहिए। अगर हम रेलवेज, डिफेंस, पोस्ट्स एन्ड टैलिग्राफस, स्टील प्लांट्स वगैरह पब्लिक सैक्टर के सब कारखाने को ज्यादा एफिशेंसी के साथ चलायें, तो हम 300 करोड़ रुपये बचा सकते हैं।

जहां तक रीकवरी आफ टैक्सिज का सवाल है, मैंने एक सवाल पूछा था कि पिछले पांच सालों में जिन लोगों की एक लाख रुपये से ज्यादा डिमांड को राइट आफ कर दिया गया है, उनके नाम बताय जायें। मंत्री महोदय ने छः महीने के बाद जवाब दिया और 93 नाम बताए। उनमें से किसी के बारे में कहा गया कि ट्रेसेबल नहीं है, किसी के बारे में कहा गया कि वह पैसा नहीं दे सकता है, वगैरह। जो पैसा नहीं दे सकता है, उनमें सर आगाखां है, कानपुर के रामरत्न गुप्ता हैं, जिनके मामले को यहां पर शोर मचने पर दोबारा खोला गया था।

दिल्ली के एक माननीय नेता हैं। वह आनरेरी मैजिस्ट्रेट हैं। उन की लड़की की शादी पर मैं भी गया था। उस शादी में बारात हवाई जहाज के जरिये से आई थी और अशोका होटल में ठहरी थी। मुझे उन के बारे में फिगर मालूम नहीं हैं, लेकिन उनका नाम भी एक लाख रुपये से ऊपर की लिस्ट में था।

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : जिस की मिठाई खाई, उसी के बारे में यहां कह रहे हैं?

श्री कंवर लाल गुप्त : जिस ने राइट आफ किया होगा, उसने मिठाई नहीं, पता नहीं क्या-क्या खाया होगा।

मंत्री महोदय समझ लें कि इस में जरूर गड़बड़ है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वह इस सारी लिस्ट को रिवाइज करें। वह एक कमेटी बिठायें, जिसमें पार्लियामेन्ट के भी कुछ मेम्बर हों। वह कमेटी स्क्रूटिनाइज करे कि कौन सा केस जायज है और कौन सा नाजायज है। इस लिस्ट में बहुत से इंडस्ट्रिय-लिस्ट्स हैं। अगर मशीनरी को टाइट न किया जाय, तो जो 500 करोड़ रुपया एरियर्ज में पड़ा हुआ है, वह वसूल हो सकता है।

मैं यह भी सुझाव देना चाहता हूं कि जिसकी आय छः हजार रुपये से कम हो, उसको इनकम टैक्स से मुक्त कर दिया जाये। ऐसा करने से पच्चीस लाख में से एक-तिहाई एसेसीज निकल जाते हैं। उसके बाद जिन लोगों की

[श्री कंवर लाल गुप्त]

आमदनी पांच लाख या उस से ऊपर है, सरकार उन पर अपना जोर लगाए, कानसेंट्रेट करे और इस काम के लिए आनेस्ट और एफिशेंट आफिसर लगाए। रीकवरी टेक्सेशन और एक्स्ट्रा इनकम टैक्स डिमांड, अगर ये सब काम ठीक तरह से किये जायें, तो 150 करोड़ रुपया और ज्यादा मिल सकता है। इस में झुनझुन वाले भी हैं। मुझे मालूम नहीं वह कौन हैं। मैं इंडस्ट्रिअलिस्ट्स को ज्यादा जानता नहीं। मैं रणधीर सिंह जी को वह लिस्ट दे दूंगा।

दूसरी चीज, एक मैं और सजेशन देना चाहता हूं। गवर्नमेन्ट एक्सपेंडीचर हमारा 1964-65 में 2939 करोड़ था।....

13.01 Hrs.

The Lok Sabha adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

The Lok Sabha reassembled after Lunch at Fourteen of the Clock.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

GENERAL BUDGET—GENERAL DISCUSSION—*contd.*

श्री कंवर लाल गुप्त : उपाध्यक्ष जी, मैं यह कह रहा था कि डवेलपमेन्ट एक्सपेंडिचर पिछले चार सालों में करीब 30 प्रतिशत बढ़ा और नान-डवेलपमेन्टल एक्सपेंडिचर पिछले चार सालों में 50 प्रतिशत बढ़ा है। 1964-65 में डवेलपमेन्टल एक्सपेंडिचर 2939 करोड़ रुपये था और अब 1967-68 में 3829 करोड़ रुपये हुआ और नान-डवेलपमेन्टल एक्सपेंडिचर 1964-65 के 1815 करोड़ रुपये के मुकाबले 2714 करोड़ रुपये हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये माननीय वित्त मंत्री जी को याद दिलाऊं कि जब वह कामराज प्लान में मिनिस्टर नहीं रहे, तो उन्होंने आल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सामने अपनी एक 13 सूत्री योजना रखी थी और यह कहा था कि अगर उस पर अमल कर के 10 प्रतिशत खर्च सरकार का कम कर दिया जाय, तो 300 करोड़ रुपये की बचत होगी। मैं आपके जरिये से माननीय वित्त मंत्री जी से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस प्रकार का जो नान-डवेलपमेन्ट एक्सपेंडिचर दिन पर दिन बढ़ रहा है, उसमें कम से कम 10 प्रतिशत की कटौती करके 270 रुपये की बचत करनी चाहिये। इसी प्रकार एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर भी बढ़ता जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर, 1956-57 में 38 करोड़ रुपये था, लेकिन 1967-68 में 140 करोड़ रुपये हो गया। भारत सेवक समाज, भारत साधु समाज, कम्युनिटी डवेलपमेन्ट, ये सब बन्द कर देनी चाहिये, ये जितनी भी पोलिटिकल लक्जरीज हैं, ये सब बन्द होनी चाहियें।

इसी तरीके से मिनिस्टरों की संख्या जो अब 60 है, मेरे ख्याल से 30 कर देनी चाहिये, ताकि लोगों को यह लगे कि अब सही मायनों में सरकार खर्च में कटौती करना चाहती है। इसी तरीके से नेहरू-एक्जीबीशन के बारे में कहना चाहता हूं। विदेशों में नेहरू एक्जीबीशन्ज हो रही हैं, इस पर करीब 32 लाख रुपया खर्च हो चुका है और इस 32 लाख में से 24 लाख रुपया फौरन-एक्सचेंज है। मैं नेहरू जी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जब देश भूखा मर रहा हो, इस प्रकार की वेस्टेज अच्छी नहीं लगती है। विदेशों में नेहरू जी की इज्जत तब ज्यादा बढ़ेगी, जब दुनिया के लोग यह देखेंगे कि नेहरू जी जिस देश के प्रधान मंत्री थे, वहां के लोगों के पेट भरे हुए हैं।

इसी तरह से कस्टम और एक्साइज की मशीनरी को टाइटन किया जाय, तो 50 करोड़ रुपये की बचत हो सकती है। मैंने, उपाध्यक्ष जी, यह कहा था कि हर एक को रोटी, कपड़ा और मकान की गारन्टी यह सरकार दे। इसके लिये अगर आपको लेवी भी लगानी पड़े—मान लीजिये होलसेल फूड-ग्रेन पर या किसी और चीज पर 200–300

करोड़ रुपया आप लगाते हैं, जो केवल इसी काम के लिये खर्च होगा, और किसी काम के लिये खर्च नहीं होगा-हर एक को रोटी, कपड़ा, पानी और मकान मिलेगा, तो मैं उस के लिये भी तैयार हूं। इस तरीके से 1 हजार 70 करोड़ रुपये की आमदनी होती है-अब अगर डाइनैमिक एप्रोच हो तो यह किस चीज पर खर्च हो सकता है-मैं उसका जिक्र करना चाहता हूं। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यह सरकार एक तरीके से नहीं चलती है। हर एक मिनिस्टर के मुंह अलग अलग हैं हर एक डिपार्टमेन्ट का मिनिस्टर अपने आपको एक अलग एम्पायर समझता है। हमारे डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्ज को ही ले लीजिए, वहां लिखा हुआ है कि प्रोहिबिशन होना चाहिये-लेकिन आपके यहां एक मिनिस्टर कहता है कि प्रोहिबिशन होना चाहिये, तो दूसरा कहता है-पीयो, दबा कर। एक स्टेट प्रोहिबिशन करती है तो दूसरी उसको हटाती है। एक कहती है कि हिन्दी लिंक लैंग्वेज होनी चाहिये, तो दूसरी कहती है कि अंग्रेजी राष्ट्रभाषा है। हमारे डाइरैक्टिव प्रिंसिपल्ज में कहा गया है कि 19 साल में 14 साल की उम्र तक के बच्चों के लिये मुफ्त शिक्षा होनी चाहिये, एक जगह पर वैल्थ जमा नहीं होनी चाहिये, लेकिन यहां सोशलिज्म की बात तो कही जाती है, परन्तु हजारी कमेटी की रिपोर्ट हमारे सामने है। हजारी कमेटी की रिपोर्ट के बाद भी सन 1966-67 में सरकारी आंकड़े बता रहे हैं-केवल 10 फर्मों को एक साल में 133 करोड़ के लाइसेन्स दिये गये। हजारी कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद केवल 10 फर्मों को। यहां एक तरफ सोशलिज्म चल रहा है, तो दूसरी तरफ कैपिटलिज्म भी चल रहा है। प्रोहिबिशन भी चल रहा है और नहीं भी चल रहा है। एक मैड-हाउस बना हुआ है जहां कोई निश्चित पालिसी नहीं है।

मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि एक दिशा निश्चित कीजिये, सरकार किधर जाना चाहती है, क्या डेस्टीनेशन है, आप गल्तियां कीजिये, लेकिन दिशा तो निश्चित होनी चाहिये। इस समय यह सारा देश दिशाहीन हो गया है, कोई डाइरेक्शन नहीं है। ये सब स्टेप्स आप तब ले सकते हैं जब एक होकर चलें। मैं जानता हूं आपने कहा था कि एक्सपेंडिचर में कटौती करेंगे, लेकिन आप कर नहीं पायेंगे, क्योंकि आपके साथ चलने को कोई तैयार नहीं है। "नहीं, नहीं, मोरारजी भाई, यह नहीं करना, नहीं तो वोट नहीं मिलेंगे।" यह चीज बन्द होनी चाहिये। जो भी चीज नैशनल इन्टरेस्ट में है, उसे सरकार को अवश्य करना चाहिये।

श्री क० ना० तिवारी (बेतिया) : आपकी सलाह क्या है, क्या होनी चाहिये?

श्री कंवर लाल गुप्त : अभी बताता हूं आपने पोस्टल रेट्स बढ़ा दिये हैं, यह नहीं होनी चाहिए था। आपको मालूम है कि 1879 ई० में पोस्ट-कार्ड की कीमत एक पैसा थी, उसके 43 साल के बाद एक पैसा बढ़ी, उसके 22 साल के बाद फिर एक पैसा बढ़ी उस समय पोस्ट कार्ड की कीमत बढ़ने पर मैंने श्री भूलाभाई देसाई की स्पीच को पढ़ा उस समय उन्होंने कहा था कि यह एन्टी पियुपिल है, लोग इससे मर जायेंगे-लेकिन हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने तो एक कलम से उसकी कीमत डबल कर दी-6 पैसे के जगह 10 पैसे कर दिये-क्या यह एन्टी-पियुपिल नहीं ? यह बजट एन्टी पियुपिल होगा, जब तक आप लोगों को इन की भावनाओं के अनुसार हर एक को मिनिमम-बेअर-नेसेसिटीज-आफ-लाइफ नहीं देंगे।

दूसरी चीज इस 1 हजार 70 करोड़ में से आप माइनर इरिगेशन, एग्रीकल्चरल इम्पलीमेन्ट्स बीच, फर्टीलाइजर पर 100 करोड़ रुपया और खर्च कीजिये।

इसी तरह से मिनिमम गारन्टी देने वाली बात है कि जिसकी आमदनी 3600 रु० से कम है, चाहे वह मजदूर हो या गांवों में काम करने वाला खेतिहर

[श्री कंवर लाल गुप्त]

मजदूर हो, उसको सब्सिडाइज्ड फूड, क्लोदिंग और सब कुछ देना चाहिए। इस के लिए मैंने 250 करोड़ रुपया लगाया है। इसी तरह से स्माल स्केल इंडस्ट्रीज, मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज और कुछ और इंडस्ट्रीज हैं जिनको 55 करोड़ की रिलीफ दी जाय ताकि कैपिटल फार्मेशन हो सके। इसी प्रकार से मजदूरों के लिए क्वार्टर्स बनाने की बात ही है। केवल दिल्ली के अन्दर 75 हजार क्वार्टर्स बनाने की आवश्यकता है। अभी तक केवल 3 हजार क्वार्टर्स ही बने हैं। तो सारे देश में मजदूरों के लिए क्वार्टर्स बनाने के लिए 100 करोड़ रुपया होना चाहिए। इस सम्बन्ध में एक कानून भी बनाया जाना चाहिये जिसके द्वारा मालिकों को मजबूर किया जा सके कि वे अपने नफे का कुछ हिस्सा इस कार्य में अवश्य लगायें। इसी तरह से मिनिमम वेज को भी थोड़ा बढ़ाया जाना चाहिए। पानी पीने के कुओं के लिए 50 करोड़ रुपया लगाया जाना चाहिए। आखिर में मैं यह कहूंगा कि जो लैंडलेस लेबर हैं, हरिजन हैं उनके लिए 50 करोड़ और 290 का डेफिसिट मिलाकर यह बराबर का बजट हो जाता है।

मैं ज्यादा लम्बी चौड़ी चीजों में नहीं जाना चाहता, बल्कि मैं यही कहना चाहता हूं कि यह एक डायनेमिक एप्रोच होनी चाहिए। जब तक डायनेमिक एप्रोच नहीं होगी तब तक कोई चीज होने वाली नहीं है।

मैं एक दूसरी चीज की तरफ भी आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। जैसा कि गृह मंत्री जी ने कई बार कहा है कि चुनाव के दिनों में विदेशी पैसा आता है। उन्होंने इंक्वायरी भी करवाई। उन्होंने कहा कि इंक्वायरी में यह पता लगा है कि विदेशी पैसा आता है। उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी देश के लिए यह बड़ी खतरनाक चीज है। हम तो मांग करते हैं कि इसके लिए एक हाई पावर कमीशन बिठाया जाना चाहिए और इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि किन लोगों ने पैसा दिया है, किन देशों ने पैसा दिया है। यह चीज जनता के सामने आनी चाहिए क्योंकि यह बड़ी खतरनाक चीज है, इसके बिना हमारा डिफेंस और हमारे देश की सिक्योरिटी नहीं रह सकती है। यह सही है कि हम अमरीका से दोस्ती चाहते हैं, हम रूस से भी दोस्ती चाहते हैं, चीन और पाकिस्तान से भी दोस्ती चाहते हैं, हरएक से हम दोस्ती चाहते हैं लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि मास्को, वाशिंगटन या बाहर कहीं और से लोग हिन्दुस्तान में आकर इस प्रकार के गलत कार्य करें। मैं जानता हूं कि यहां पर अमरीका के 1500 पीस कोर वालंटियर्स हैं, टेक्निशियन्स, एजूकेशनिस्ट्स और फारेन एक्सपर्टस हैं जिनमें से कुछ लोग स्पाई का काम करते हैं। फारेन कोलाबोरेशन इतना ज्यादा है, हालत यह हो गई है कि हिन्दुस्तान में कई आर्गेनाइजेशन्स ऐसे हैं जो केवल अमरीका के पैसे से चलते हैं। सी० आई० ए० इतना ऐक्टिव है कि लेने वालों को भी कई बार पता नहीं चलता कि यह सी० आई० ए० का पैसा है। हमारी लाइफ के अन्दर अमेरिकन इन्फिल्ट्रेशन आहिस्ता आहिस्ता जहर की तरह से आ रहा है। इसको रोकना पड़ेगा।

इसी प्रकार से मास्को के बारे में भी कहूंगा कि वह भी यही कर रहा है। इस सम्बन्ध में मैं एक उदाहरण भी देना चाहता हूं। रायसेना पब्लिकेशन्स की तरफ से "पैट्रियाट" और दूसरी एक कनसर्न से "लिंक" निकलते हैं। मेरी निश्चित सूचना यह है कि पिछले 5 सालों में 50 लाख रुपया इन दोनों कन्सर्न्स के लिए रूस से आया है। मैं इसको साबित कर सकता हूं।.... (**व्यवधान**) ....

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि पिछले सालों में इन दोनों कन्सर्न्स को हर साल 15 लाख रुपये का घाटा हो रहा है। यह रुपया किस तरह से आता है? इनका शुरू का क्या कैपिटल था, वह भी देख लीजिए। सन् 1958 में जब लिंक बिल्डिंग बनी और लिंक का अखबार चला तो इनका कैपिटल केवल दो लाख रुपया था। इसी प्रकार से रायसेना

पब्लिकेशन्स का जो दूसरा कन्सर्न है उसका भी शुरू में थोड़ा सा कैपिटल था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब 60 लाख रुपये का कैपिटल बन गया है। यह कहां से आता है?

एक माननीय सदस्य: आप यह बात बाहर भी कहने को तैयार हैं? ···व्यवधान···

MR. DEPUTY-SPEAKER : I will caution him about it. He is involving others by inference. After all, it is an inference. If there is proof, then that is a different matter.

SHRI PILOO MODY (Godhra): Even if he has not even so, he can speak.

श्री कंवर लाल गुप्त : उपाध्यक्ष जी, मैं यह कह रहा था कि वह किस तरीके से काम करते हैं। मैं उसका मोडस आपरेन्डी बताना चाहता हूं।

SHRI MORARJI DESAI: May I make a request that if the House tolerates allegations against some people, let it tolerate it against any other people as well. Why should people get excited about it?

MR. DEPUTY-SPEAKER: When wild allegations are made, it is the duty of the Chair to stop him or ask for proof.

SHRI S. KANDAPPAN (Mettur): If the hon. Member is prepared to substantiate his case, he should be permitted to narrate it.

श्री कंवर लाल गुप्त : 'पैट्रियाट' 63 में शुरू हुआ। 13 लाख के कैपिटल से वह शुरू हुआ था लेकिन इन दोनों कन्सर्न्स ने 60 लाख रुपए खर्च किए। 15 लाख रु० सालाना इन दोनों कन्सर्न्स को घाटा हो रहा है। यह आता कहां से है? उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी मजेदार बात तो यह है कि हर साल 15 लाख का घाटा होने के बावजूद शेयर होल्डर्स की संख्या बढ़ रही है। मोडस आपरेन्डी क्या है? वह यह है कि डोनेशन के नाम से रुपया लिया जाता है। अरुणा आसफ अली जी के शुरू में 2 लाख रुपये जमा थे, अब 7 लाख रुपये जमा हैं। श्री इ० नारायणन जो कि इसके डाइरेक्टर और एडिटर हैं उनका डेढ़ लाख रुपया जमा है।

SHRI MORARJI DESAI : May I know how this is relevant to the debate?

MR. DEPUTY-SPEAKER : That is what I also feel. When we are discussing the budget, he can bring in many other matters in a general discussion on the budget....

SHRI KANWAR LAL GUPTA : I can discuss anything.

MR. DEPUTY-SPEAKER : He is mentioning a particular concern and he is giving figures. If he feels that they are getting money from sources which are not Indian, then it is for him to approach the Government. As the Deputy Prime Minister has stated, it is absolutely irrelevant here.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : I will conclude in five minutes.

अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह था कि इस प्रकार डोनेशन के नाम से, शेयर होल्डर्स के नाम से, लोन्स के नाम से—काफी बोगस रुपया, जोकि रूस का है, अलग अलग नामों से जमा है। मेरा इतना ही कहना है कि इसको रोका जाना चाहिए। यहां पर 5 लाख रुपए की प्रिंटिंग मशीनरी रूस से आई है। मैं नाम भी बता सकता हूं। सरकार को भी इन्फार्मेशन है कि रूस से रुपया आ रहा है। हम चाहते हैं कि सी० बी० आई० के जरिए से इसकी इंक्वायरी हो क्योंकि कोई भी दूसरी एजेंसी इस चीज को नहीं निकाल सकती है। फेलो ट्रेवेलर्स भी इन कन्सर्नस के हैं जैसे केशव देव मालवीय। और भी दूसरे लोग हैं। ···(व्यवधान)···

MR. DEPUTY-SPEAKER : Please resume your seat. If you have certain information in your possession, as I have already observed it would be fair to all concerned if you pass on that information to the Government, to the concern-

[Mr. Deputy-Speaker]

ed department, because you are trying to probe into the proprietorship of newspapers. He cannot make inferences. Now he is making many allegations, positive allegations and he is mentioning the names of persons who are not here to defend themselves. It is totally irrelevant.

SHRI PILOO MODY : What is wrong with it ?

श्री कंवर लाल गुप्त : श्री उपाध्यक्ष जी, मैंने सरकार को भी इसकी इंफार्मेशन दी है। इसके अन्दर बीजू पटनायक और उनकी धर्म पत्नी ज्ञान पटनायक भी शामिल हैं। और भी बहुत से फेलो ट्रेवेलर्स इसके अन्दर हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मेरे पास लिस्ट है। अगर आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि क्या हो रहा है हमारे देश में। जब श्री के० डी० मालवीय यहां मंत्री पद पर थे तो साढ़े तीन लाख रुपये का रेन्ट एडवांस लिंक बिल्डिंग के लिए दिया गया।···
·(**व्यवधान**)···· एक जर्मनी औरत है मिस्सेज एल० घोष ····(**व्यवधान**)····।

श्री अमृत नाहाटा (बाडमेर) : पूना के उस अग्रणी अखबार का सम्पादक महात्मा गांधी का हत्यारा गोडसे था। महात्मा गांधी की हत्या के एक महीने पहले बिड़ला ने 20,000 रुपया उस अग्रणी के अखबार को दिया था यह मैं चुनौती के तौर पर कहना चाहता हूं ····(**व्यवधान**)····

श्री कंवर लाल गुप्त : आप बिड़ला जी को कहिये हमें कोई ऐतराज नहीं है आप के पास बैठे हुए लोग नाराज हो जायेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि मैने बड़ा कंजरवेटिव एस्टिमेट दिया है ..(**व्यवधान**)

MR. DEPUTY-SPEAKER : Do you want this allegation and counter allegation ? This is not fair.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : Why should I counter it ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : Do you want this type of debate to continue ? I do not want that. Please stop here.

श्री कंवर लाल गुप्त : यह फैक्ट्स हैं डिफेमेशन नहीं है। डाक्टर बालिगा के नाम से भी रुपया जमा है।

श्री हुकम चन्द कछवाय (उज्जैन) : सरकार को पहले बतला दिया है और उस पर इंक्वायरी की जा रही है ····(**व्यवधान**)

SHRI TULSHIDAS JADHAV (Baramati) : On a point of order, Sir.

Rule 353 says :

"No allegation of a defamatory or incriminatory nature shall be made by a member against any person unless the member has given previous intimation to the Speaker.. ....".

What I want to know is whether he has given any intimation to you.

MR. DEPUTY-SPEAKER : No.

SHRI TULSHIDAS JADHAV : Then, he is not entitled to make any allegation against Mrs. Aruna Asaf Ali....
(*Interruption*)

MR. DEPUTY-SPEAKER : He has named certain persons who are not here to defend themselves. This point of order is very valid.

SHRI PILOO MODY : I want to know, in this House, if the Speaker or the Deputy-Speaker did anything to defend Mr. Bajaj.

MR. DEPUTY-SPEAKER : It is not a question of defence. That matter came up in the form of privilege motion before the House.

SHRI PILOO MODY : Mr. Bajaj was mentioned here in much the same way.

I want to know if the Chair did anything to protect Mr. Bajaj.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I am not protecting anyone.

SHRI PILOO MODY : We want to expose all of them. (*Interruption*)

MR. DEPUTY-SPEAKER : Order, order. I have to conduct the debate in

a dignified manner. The names should not be mentioned of those who are not present here. If their names are mentioned without any positive proof or anything else, it is not in order. He mentioned the name of Mrs. Aruna Asaf Ali; then, he mentioned the name of Mr. Malaviya. So far as this House is concerned, about those persons who are not present here, who formerly were holding some positions, if you make certain allegations, I am not going to permit them. I must keep the dignity of the debate.

SHRI TULSHIDAS JADHAV : Sir, you have got the right. It says :

> "Provided that the Speaker may at any time prohibit any member from making any such allegation if he is of opinion that such allegation is derogatory to the dignity of the House....".

SHRI PILOO MODY : How is it derogatory to the dignity of the House?

SHRI TULSHIDAS JADHAV : Without giving notice to the Speaker, you cannot say like that.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Please don't mention the names of persons who are not here to defend themselves. I gave you some latitude; you stop here.

SHRI P. K. GHOSH (Ranchi) : This may be deleted from the records.... (*Interruption*)

श्री कंवर लाल गुप्त : अगर इस तरह से ज्यादा बोलेंगे तो मैं सब चीजें स्पष्ट करूंगा ।

SHRI N.K.P. SALVE (Betul) : Sir, time and again, this question has arisen. I beg of you to give a ruling determining the precise scope of protection against defamatory allegations which people will enjoy who are not here in the House to defend themselves. You said that either the Member should have proof or he should give prior intimation. I submit there is no provision in this rule that if Members have any proof, they should be allowed to make an allegation. Therefore, I submit that it is exceedingly important that the precise scope of protection to those people who are not here to defend themselves may kindly be determined.

MR. DEPUTY-SPEAKER : He has raised an important point. Mr. Tulshidas Jadhav raised this point under rule 353. When I said, 'some proof', I did not mean 'with some proof in his pocket which is not verified'. These are allegations ....(*Interruptions*). The important aspect of this matter is that, if the name of a member or a person who is not in a position to defend himself, whether he belongs to bureaucracy or was formerly a Member of this House, is dragged in with all sorts of allegations, I think, it is deragatory to the dignity of the House and is unfair to the Member whose name is dragged in.

SHRI N. K. P. SALVE : In view of this ruling, I submit that the allegations made by the hon. Member regarding some of eminent public men may be expunged.

SHRI PILOO MODY : I seriously suggest to you that you do not take any particular stand on this subject and reconsider it and, if necessary, you may, even have a joint meeting....(*Interruption*). Let me finish. Today I find all of a sudden, because people of a particular hue are being named, all that hue and cry is being made in the House. Umpteen people have been named in this House before, who have not been.. ....

AN HON. MEMBER : Is he discussing your ruling, Sir ?

SHRI PILOO MODY : I am on his point of order. The names of umpteen people, who did not have an opportunity to defend themselves—members of the bureaucracy, for instance—have been mentioned before on the floor of this House....*Mr. Deputy-Speaker* : I have always protected....)Speakership is an entity whoever may be in the Chair at a particular moment....

MR. DEPUTY-SPEAKER : The names of members of services have been

[Mr. Deputy-Speaker]

mentioned, but we have always taken exception to it. When I said just now that this is the general practice here and the rule..... (*Interruptions*)

SHRI PILOO MODY : The rules of service do not permit them to defend themselves....

MR. DEPUTY-SPEAKER : I am talking of even those who are not present here.....

SHRI PILOO MODY : That means, the rest of the country.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Let this House remember once and for all that we cannot use the position of privilege to attack those who are not in a position to defend themselves here. It is not correct to do it...

SHRI PILOO MODY : That means that only Ministers can be attacked personally. If that is the directive from you, then we shall be happy to follow it...

MR. DEPUTY-SPEAKER : Only if there is justification and not attack for attack sake. So far as the others are concerned, my ruling stands.

श्री कंवर लाल गुप्त : आपने कहा कि कोई एथैंटिक फैक्ट्स होने चाहिएं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि 11 दिसम्बर सन् 1967 को मैंने सदन में एक सवाल पूछा था कि यह प्रिंटिंग पेपर सोवियट इम्बैसी कितने का इम्पोर्ट करती है जिसके कि जवाब में यहां पर बतलाया गया था कि सन् 1966 में 34,85,814 रुपये का पेपर इम्पोर्ट किया गया। इसमें दिसम्बर की फीगर्स इनक्लूडेड नहीं हैं। लगभग 36-37 लाख रुपये का या मोट तौर से समझ लीजिये कोई 38,00,000 रुपये का प्रिंटिंग पेपर रशियन इम्बैसी ने 1966-67 में इम्पोर्ट किया और मेरी इनफौरमेशन यह है कि अब की वह 40 लाख रुपये के ऊपर है। और आवश्यकता केवल पांच लाख की है। मोडस औपरेन्डी उपाध्यक्ष महोदय यह है कि यह लोग करते यह हैं कि मान लीजिये इन्हें श्री कोसीगिन की स्पीच यहां प्रेस में छपवानी है तो वह उस प्रेस को उस स्पीच की कापियां छापने के लिए प्रिंटिंग पेपर एक लाख कापियों के लिये देंगे हांलाकि दरअसल छपवायेंगे उससे केवल उसकी 5000 ही कापियां और प्रिंटिंग चार्जेज भी वह उस प्रेस को एक लाख कापियों के ही देंगे। इस तरीके से वह रुपये से भी उसे सबसिडाइज करेंगे और कागज से भी। आप दिल्ली के बाजारों में जाकर देखिये रशियन पेपर खरीद सकते हैं तो आखिर यह आता कहां से है? यहां कोई रशियन पेपर इम्पोर्ट नहीं किया जाता लेकिन बाजार में वह खरीदा जा सकता है। मैं मंत्री महोदय से चाहूंगा कि इसकी इनक्वायरी की जाय कि यह रशियन पेपर आता कहां से है? मैं रशियन पेपर्स का नाम भी लेता हूं। यह "लिंक" और "पैट्रियट" से भी आता है। इसके अलावा और दो तीन जगहें हैं, अगर मंत्री महोदय कहेंगे तो मैं उनके नाम भी उनको बतला दूंगा और मैंने बतलाया भी है। मेरा कहना यह है कि मैं किसी के ऊपर बेसलेस चार्जेज लगाने के हक में नहीं हूं, मगर यह कोई कांग्रेस या जनसंघ की बात नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टी या दूसरी पार्टी का सवाल नहीं है। अगर मेरी पार्टी के अन्दर ऐसी बात हो तो उसे भी पूछा जाना चाहिये। कोई भी पार्टी हो, उसकी बात सामने आनी चाहिये क्योंकि यह देश का सवाल है।

मैं मानता हूं कि हम रूस से भी मित्रता चाहते हैं, मुझे मालूम है कि रूस ने काश्मीर के विषय में और दूसरी बातों में हमारा काफी साथ दिया है,

We crave for the friendship of Russia.

और उतने ही उत्सुक हैं जितने हमारे फेलो ट्रैवेलर्स हैं। लेकिन सवाल यह है कि हमारी सरकार क्या करती है। उसको मालूम है कि यहां जो हो रहा है, और सभी जगह होता है, फिर मुझे नहीं मालूम कि वह क्यों बच जाते हैं। मेरा तो कहना यह है कि जो हमारे देश के रहने वाले लोग हैं उनके

खिलाफ सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती। वह आरोपों की इनक्वायरी कराये और अगर यह साबित हो जाय कि वह पैसा लेते हैं और इस तरह से दूसरे देश हमारे निजी मामलों में दखल दे कर हमारी पालिटिक्स को प्रभावित करना चाहते हैं, तो जो लोग पैसा लेते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और जो देते हैं, चाहे वह रूस हो या अमरीका हो, चाहे चीन हो या पाकिस्तान, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिये। आपने क्या किया इस केस में आप ने माइल्ड प्रोटेस्ट नोट भेज दिया। इस तरह से कुछ होने वाला नहीं है। आपको लगता है कि कल रूस नाराज हो गया तो क्या होगा, अमरीका नाराज हो गया तो क्या होगा। मैं कहना चाहता हूं कि यह एक ऐसी चीज है जो देश को आगे नहीं ले जाने देती। हमें हथियार मिलें या न मिलें, हमें अनाज मिले या न मिले अमरीका से, लेकिन अगर एक विल-पावर सामने बैठे हुए लोगों में हो तो हमारा काम चल सकता है। वह आह्वान करें कि अगर अमरीका हमारी इज्जत खरीद कर हमको पैसा देना चाहता है तो हम नहीं लेंगे। मेरा तो कहना यह है कि हम भूखे रह सकते हैं, हम नंगे रह सकते हैं, हम लाठियों से मुकाबला कर सकते हैं अगर हमारे पास हवाई जहाज नहीं हैं, लेकिन अपनी इज्जत बेच कर हम कुछ नहीं लेंगे। हो सकता है कि मेरे ऐसा कहने में आपको हंसी लगे, लेकिन जब तक यह विल-पावर आप लोगों में नहीं आती तब तक हमारा काम नहीं चलेगा। हम अपनी इज्जत के साथ सौदा नहीं करेंगे।

मैं कहता हूं कि जो पैसा बाहर से आ रहा है, वह कहीं से भी आये, उसको रोकने के लिये कानून बनाया जाये, उसके लिये हाई पावर कमीशन बिठलाया जाये और उसकी एन्क्वायरी की जाये। जो भी इस तरह के लोग हों, चाहे वह हमारी तरफ के हों या सामने की तरफ के, उनको एक्सपोज किया जाय और जो भी बाहर की सरकारें इस तरह से काम करती हैं उनको भी वार्निंग दी जाये कि हमें इस तरह की दोस्ती नहीं चाहिये।

इन शब्दों के साथ जो यह ऐन्टी पीपल बजट है, मैं उसकी मुखालिफत करता हूं।

SHRIMATI SUCHETA KRIPALANI (Gonda): The task before our Finance Minister in framing this budget was a very difficult one. He had to frame his budget against the background of recession in industry, growing deficit, unemployment and other economic difficulties. Therefore, the choice before him was very hard. It was in fact a dilemma. On the one side there was the need to balance the budget, and on the other side he was expected to give some impetus to the economic activity in an effort to revive our economy which has been dragging very badly of late. Two ways were open to him. One was the taking of very drastic steps, even revolutionary steps by which he could cut a new path, reorient the entire policy after taking into consideration the present situation and then go ahead with it. Or, to take a more conservative attitude, that is to devise some corrective measures to check the adverse trends in our economy, to check the imbalances and to suggest some remedial measures. The Finance Minister has taken the second course.

He has been able to provide some stimulus to industrial and agricultural production. He has given certain tax concessions, for instance, the discontinuance of the dividend tax, reduction of surtax and other marginal concessions. This he has done in an effort to give some kind of fillip to our lagging industry.

I am also very glad to note that of late there has been more and more realisation that food production is of prime importance, and we should do everything in our power to increase it. He has told us in his speech that they are taking steps to improve the fertiliser position and better the irrigation position. He has also tried to give some incentives to agro-based industries so that they can carry on research and with the help of the results thereof improve

[Shrimati Sucheta Kripalani]

agricultural production, both food crops as well as commercial crops.

The other step he has taken is to give support to export promotion. He hopes that by these measures our export industry will pick up and we will be able to find a bigger foreign market for our goods and will secure a better foothold for our products abroad.

As far as this goes, this is a good budget and we have nothing to criticise. It will help to create a good psychological climate. But the assessment of people who know about it better than myself is that all these measures will only have marginal benefit, not a substantial one, and that we will really not be able to pull out our economy from the depressed condition in which it is formed today. To the extent it is a revival-oriented budget, it deserves all our support.

The second problem before the Finance Minister was how to balance the budget. I am very glad to see that he has not gone out to tax on a high level. He has himself said that he has avoided major operations and contented himself only with minor ones. Not only that. The budget expresses an anxiety on his part to see that the incidence of tax does not fall on the common man except for two taxes which have to be criticised, the general tax on tobacco and the rise in the postal rates.

As far as the postal rates are concerned, the reason given is that there is a deficit of Rs. 22 crores and that our rates are comparatively less than those in other countries. This is his justification to raise the rates. It may be true that our postal rates compare well with other countries', say, UK, USA and USSR. But we have also to take into account what is the *per capita* income and economic conditions in those countries. In the conditions of our country, to raise even the price of the postcard will be to impose a levy impinging on the poor people. Therefore, may I appeal to the Finance Minister to reconsider this levy and and give some relief to the taxpayer ?

I am rather surprised to learn that there is a deficit of Rs. 22 crores in the postal department. This department is a commercial department. I appreciate that of late the pressure for giving more DA and higher salaries has been there. In spite of that, I am quite sure that if an effort is made to plug all loopholes, this 22-crore deficit could to a great extent be made up and perhaps the people will not have to be taxed to find this additional income.

Then I come to the most vexed and difficult problem of the gap of Rs. 290 crores. We all know the aversion of the Finance Minister to deficit financing. He has time and again given expression to it. But today he has not been able to cover this gap. The reason given is the impossibility of imposing a very heavy cut in governmental expenditure, particularly in view of the recessionary condition in our trade. If government orders are also cut, then industry will not be able to revise. That is the justification adduced.

Secondly, it is also said that we cannot cut our defence expenditure. I generally accept the argument, but while accepting the argument, I would like to say that in a budget of Rs. 4,000 crores, is it not possible to introduce some kind of saving of one or two per cent? If a saving of one or two per cent can be effected, certainly we can cover a certain amount of the gap. I know the Finance Minister is trying his level best to plug the loopholes. His name is not very popular with most of the departments at the moment for this very reason. But we have got so much used to wasteful expenditure. Take for instance, the vehicles attached to every department. I am more than sure they are misused, not always used for Government purposes. That is one area where we can certainly bring about economy. Like that there are several othre areas. If the Finance Minister gives full attention to it, this can be done. I am only sorry that efforts to cut wasteful expenditure has not been highlighted in the budget.

These are the few remarks that I want to make on the budget proper, but I would like to take this opportunity to draw the attention of the House and all leaders of the people to more basic and

fundamental issues that are before us. Twenty years have passed since we gained independence. In these twenty years we have made superhuman efforts to build up our economy. Therefore this is a proper time for an assessment and review of our grains and losses. I know that in these 20 years there has been considerable development. I do not want to go into the figures, everybody knows it, but at this moment of time our position is rather difficult. Our picture is one of marked deterioration not only in one aspect of life, but in various aspects of life to which I wish to draw your attention. The situation is such that it is causing concern to all people, not only those who are responsible for the Government, but also those in the opposition, and all right-thinking people who are concerned about the country. Therefore, it is time that we put our heads together and see in what way we can drag the country out of the morass in which it is landed.

Economically, where are we ? Our economy is suffering from acute recession. I will only quote a few figures from the *Economic Survey*. The *Economic Survey* says that all the industries are not suffering from recession, though the situation varies from industry to industry, but what is the over-all position ? The over-all position is that the rate of growth has been coming down systematically. In 1960 it was 8%, in 1965 it came down to 5 6%, in 1966 to 2.6% and in 1967 to 1.4%. It is a matter of great concern that our rate of growth, instead of being accelerated, is dwindling day by day.

I am more concerned about the symptoms that we see in our economic situation today. We devalued a few years back. What was the economic position, what was the situation then which made us take this drastic step ? There were high prices, there was deficit and we had to subsidise our imports. I am afraid the very same conditions are obtaining now. Therefore, I would like to know if a second devaluation is round the corner ? If a second devaluation is not round the corner, what steps are we taking ? I do not want to go into that devaluation, whether it was right or wrong, but we did not take the necessary follow-up steps, we shilly-shallied, we hesitated, we fumbled, and as a result, we did not take advantage of devaluation. Neither did our imports go down, nor did our exports increase. So, as a result, we did not gain anything.

Now, I would like to compare our steps after devaluation with those of England. England is one of the developed countries, one of the foremost countries in the world. It devalued, and what steps did they take in the wake of devaluation ? They cancelled important defence orders, they have withdrawn their army from various parts of the world, they have even gone to the length of suspending many of the health schemes initiated by the Labour Government itself. The Labour Government stands to lose by these measures, but they realised that the economic position was such that they had to take drastic steps, and they were not afraid of taking them. We did not do so.

We are suffering from chronic inflation. The inflation that is obtaining in the country is cost push, not demand push inflation. Cost is spiralling and is always going beyond the reach of the people. The remedy that lies with us is to check this cost inflation. The cost inflation must be arrested. This cannot be arrested by merely controlling money economy. So, what is to be done ? That is the trouble, disease and malady with our industries ? They are suffering from high cost of production, unsatisfied demand and sluggish exports. So, the greatest need of the hour is to examine the cost structure of the entire industrial economy, curb and control all purposeless and avoidable expenditure. All the other remedies that we may think of will only be palliatives and will not cure the disease. Our economy should be production-oriented. I cannot go into great details but I shall draw your attention to a few salient points. We have huge public sector factories and they have surplus capacity. At the moment our steel mills are working at fifty per cent of their capacity. Yet we are putting up another steel factory at a huge cost; all the other three factories do not cost as much as the estimated cost of this steel factory. To the extent

[Shrimati Sucheta Kripalani]

there is unutilised capacity of our capital is locked up. We are not getting any return on that capital. Similarly, there is the Bhopal Heavy Electricals. We are not getting returns from it for years together. What is the impact of that on the cost structure ? Units with heavy idle capacity mean high depreciation element in the cost. Cost can never come down unless our factories work to their full capacity. Therefore, we should not go for huge and gigantic schemes; we should go in for more modest schemes yielding quick returns.

The other difficulty in our industry is low productivity of the labour. We have followed a liberal policy towards labour. I want the labour to get its due. But we must recognise that in a planned economy there are certain implications; it presupposes regimentation and control, both in production and distribution. We cannot allow this kind of low productivity to continue. There is dissatisfaction among labour—strike, discontent and trouble all the time. I am all for giving incentives to labour but we must find out ways by which labour can give full work so that our production can go up. Of late, the cost of transport and fuel had also increased steadily and all that has fallen on the cost of production. The credit policy was also wrong. We were trying to squeeze credit for industry but at the same time we were unable to control the black money that was in circulation. We did not, therefore, get much benefit out of our credit squeeze policy.

I have to race against time. I now come to a very important matter—foreign aid. What is its significance ? Tied foreign aid does not mean aid. We can as well change its nomenclature and call it foreign purchases; that is to say, we purchase foreign goods. We have no freedom to buy goods in cheap markets; we cannot purchase goods from any market we like. As a result we have to pay heavy cost which also falls on the cost of the product. We are paying a very heavily cost for foreign technical know-how. Secondly, we also acquire foreign know-how when we need not so, because in many cases we could with some search have found people in India who had this know-how. Of course we have progressed by these means but perhaps we have paid much more than we should have ordinarily paid and the burden has fallen on the cost.

Today we do not know how to meet our debt obligations. In a recent book published by Shri Manubhai Shah, he gives the quantum of debt which we have to pay :

> "An important factor responsible for pressure on the balance of payments of the developing countries has been the heavy debt servicing obligations incurred on account of the terms on which foreign assistance is being given to these countries. For example, during the five years of India's Third Five Year Plan, interest payments and capital repayments which India has to make on account of external debts have been estimated at Rs. 573 crores. (During the Fourth Five Year Plan of India, these debt obligations are expected to rise to Rs. 1,450 crores.) It is estimated that after devaluation of the rupee, the total credits outstanding up to March 31, 1967, in terms of rupee will be Rs. 71 billion and will need to be repaid in a period of 20 years."

How are we to develop ? The UNCTAD Secretariat has brought out a document on debt servicing and they say that by 1975 the condition will be such that whatever foreign aid we get, the entire amount will have to be repaid by way of debt servicing. I shall quote only one line from that paper :

> "Assuming a continuation of lending on present average terms it has been estimated that if the volume of gross lending to developing countries were maintained constant at its current level, net lending would fall nearly to zero by 1975 and turn negative thereafter."

What are we to do ? We can repay debts in goods and that will give a fillip to our industry and also help us meet our debt servicing obligations as we received debt in goods it is but fair that we pay back in goods.

I am glad that at last we have recognised the importance of agricultural production. I should also like to warn that every year will not be a good year. This year we expect a 20 per cent increase in production. That is really the resaon for looking forward to better times. In India every other year had been a bad year. If the next year is a bad year, what is the outlook ? Therefore, we should concentrate our energies on agricultural production. I wish we had realised this fifteen years ago so that by this time we were free of this trouble of food problem.

The national income has increased but the *per capita* income has increased marginally, hardly, any. Our policy, our objective about distribution of wealth has not been fulfilled. There is concentration of wealth. We are having a separate debate on that. I do not therefore wish to touch upon it now. In the field of education, indiscipline and chaotic conditions prevail. Why ? Because these boys who are getting education today do not know what their future is. Without any healthy outlook for the future, there is discontent among them and that finds expression on all kinds of indesirable activities. It leads to lawlessness. The law and order situation has certainly deteriorated. Our weakness is taken advantage of by our neighbours. Small incidents are taking place. Cylon is coming in, Burma is sometimes threatening and Pakistan is sometimes threatening. It is because the Centre is weak. When there is a weak centre they can afford to come and grab areas that lie near them. Worst of all, the political situation is bad. We were perhaps the only country in this part of the world where we have been maintaining democratic traditions and we felt that our democracy had a certain amount of vitality. But after the last general elections, we see democracy tottering. The politicians are showing such cynical disregard for all democratic principles and parliamentary conventions that one does not know where this will all lead to. These things are done by those who are responsible for maintaining parliamentary democracy. The custodian of Parliamentary democracy are subverting the parliamentary institution. I refer the latest incidents in Bengal and Punjab.

After twenty years of independence, in spite of certain progress, these are the various difficulties in which we find ourselves. I expected that our budget will not be merely an exercise in finance and money but that our Finance Minister would give new direction to our policies. We are passing through a severe crisis and I thought that the President's speech and the Finance Minister's budget speech would give purposeful direction to the country. There are forces of disintegration and disruption and lawlessness and economic recession and unemployment. The entire situation looks bad and complicated. In this situation, we need leadership to give direction and implement policies with a firm hand. Unpleasant decisions do not matter in the present situation. In this situation of crisis, unpleasant decisions have to be accepted and we must all honestly implement them. I do no find this in the Budget. The budget is good enough but the situation is exceedingly difficult and much more complex and at such a time a small gesture was not adequate; we expected a real policy direction.

This morning, Sir, a note of warning has come. I read in the newspapers a report by Mr. Gunnar Myrdal. He is not only a noted world economist but also a great friend of India. What he has said in this report is that he feels that Indian economy as well as Asian economy has come into a position of stagnation, and stagnation of a more permanent nature. He then goes into the details of it. I would urge upon the leadership today to note carefully what he says and to take time to think of giving a new direction to take the country out of the sorry state of affairs so that we can get out of it and really march towards progress and prosperity.

श्री भोगेन्द्र झा (जयनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, जिस परिस्थिति में यह बजट हमारे

[श्री भोगेन्द्र झा]

सामने रखा गया है और जिस के बारे में पिछले बरस से शोक की गाथा गई जाती रही है, मैं चाहता हूं कि हम उस परिस्थिति पर थोड़ा विचार करें। वित्त मंत्री ने पिछले साल बजट पेश करते हुए जिन सवालो का जिक्र किया था, इस साल भी उनका जिक्र किया है। इस लिए हम में से बहुत से सदस्य सहानुभूति के आंसू बहाते हैं कि हमारा देश दोहरे रोग से ग्रस्त है। एक तरफ सुस्ती का रोग और दूसरी तरफ मुद्रा-वृद्धि का रोग। यह जाहिर करने का प्रयत्न किया जाता है कि जैसे ये दो अलग अलग तरह की बीमारियां हैं और जैसे दोनों आसमान से टपक पड़ी हैं।

जब वेतन-भोगी कर्मचारियों पर चोट करने की जरूरत पड़ती है, तब सरकार की ओर से मुद्रा-वृद्धि का नारा दे दिया जाता है और जब करोड़पतियों को सहूलियत देने की जरूरत होती है, तो सुस्ती का तर्क बताया जाता है। मैं समझ ता हूं कि सदन को इस सवाल पर विचार करने की जरूरत है। उनसे कुछ आशा करना तो शायद फिजूल मालूम होता है, लेकिन मैं अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे वित्त मंत्री जरा सोचें कि क्या यह बजट उन दोनों बीमारियों में से किसी को पहचान पाता है—इलाज की बात तो बहुत दूर की है, लेकिन क्या बीमारी की पहचान भी हो पाई है, क्या यह पता चला है कि किस वजह से बीमारी पैदा हुई।

हमारे यहां यह स्थिति है कि चूंकि सामान की कमी है, खरीदने वाले ज्यादा हैं, रुपया ज्यादा है, इसलिए कीमतें बढ़ रही हैं, मंहगाई हो रही है, यह गाना लगातार पन्द्रह बरसों से इस सरकार के लोग, मंत्री लोग, गाते आए हैं। यही गाना देश के अखबार गाते आ रहे हैं और आकाशवाणी गाती आ रही है। सुस्ती के बारे में आज यह कहा जा रहा है कि सामान बढ़ गया है, बहुत सा सामान फाजिल हो गया है, उपभोक्ता कम है, खरीदने वाले की क्रय-शक्ति नहीं है, इस लिए सुस्ती आ गई है, चार सौ के करीब कारखाने बन्द हो गए हैं, चरा लाख के करीब श्रमिक बेकार हो गए हैं।

14.57 hrs.

[SHRI G.S. DHILLON *in the Chair*]

आम तौर से पूंजीवादी अर्थतंत्र की स्थिति यह रही है कि सामान ज्यादा हो, खरीदने वाले कम हों, तो सामान सस्ता हो जाता है, लेकिन हमारे यहां जो सुस्ती है, उसमें यह बात नहीं है। यहां पर सामान ज्यादा हो गया है—सरकार की तरफ से भी कहा गया है कि सामान ज्यादा हो गया है, खरीदने वाले कम हैं, कारखाने बन्द हो रहे हैं, श्रमिक बेकार हो रहे हैं, लेकिन उस सामान के दाम बढ़ते जा रहे हैं, उसके दाम नहीं घटते हैं। इसके साथ ही जब दूसरी तरफ सामान का दाम बढ़ा, तो चीजों की कमी और लोगों की क्रय-शक्ति में वृद्धि की बात भी कही गई है।

पिछले साल वित्त मंत्री ने कहा था कि हम किसी को मंहगाई भत्ता नहीं देंगे। इस बार भी जब वह पूरा मंहगाई भत्ता नहीं रोक सके, तो उन्होंने आरजू-मिन्नत की है कि केन्द्रीय कर्मचारियों का जो बकाया है, उसको वे न लें और वे उसको उनके जिम्मे छोड़ दें। मैं चाहता हूं कि हम समझें कि यह रोग क्या है और उसकी वजह क्या है। वित्त मंत्री एडम स्मिथ, मार्शल और केंज को पढ़ते होंगे, लेकिन भारत के अर्थ-तंत्र का रोग उससे आगे चला गया है; उनसे उसका इलाज नहीं हो सकता है। वह रोग क्या है? विकासशील देश, पिछड़ा देश जहां पूरा उद्योग बढ़ नहीं पाया है, पिछड़ी अवस्था में है, उसी अवस्था में यहां इजारेदारी कायम हो गई। लगभग सभी उद्योगों में, लगभग सभी सामानों के उत्पादन में एकाधिपत्य कायम हो गया है एकाध परिवार का या कुछ गिरोहों का एकाधिपत्य कायम कर के वह नया कारखाना उस उद्योग में खुलने नहीं देते। अगर कोई नया हिम्मत करता है तो उसे वह दिवालिया बना देते हैं कुछ वर्षों के अन्दर और

कीमतों को एक हिसाब से वह तय करते हैं। उसमें कोई कारखानेदार अगर चाहे भी कि मुनाफा ज्यादा होता है और वह कीमत को कम करे तो यह इजारेदारों का गिरोह उसे होने नहीं देता। इस तरह से कृत्रिम ढंग से वह कीमतों को ऊंचा रखते हैं, नये कारखाने को आने नहीं देते हैं। इस सरकार की भी हिम्मत नहीं है कि वह उन उद्योगों में कारखाना खोले जिन उद्योगों में वह इजारेदार नहीं चाहते। हम सभी जानते हैं कि बिरला चूंकि हिन्दुस्तान मोटर्स के मालिक हैं इसलिए सरकार की शक्ति के बाहर बात हो गई कि वह नया मोटर का कारखाना खोले। दस वर्षों से यह योजना पड़ी हुई है। 46 टैंडर्स पड़े हुए हैं। 7 हजार में कार बिक सकती है। लेकिन पूरी सरकार की ताकत नहीं है, हमारे प्रधान मंत्री की भी ताकत नहीं है कि वह कह दें कि इस कारखाने को हम चालू करेंगे क्योंकि यह बिरला का हुक्म है कि कार हम ही बेचेंगे। जो भी कीमत तय करेंगे लोगों को लेनी पड़ेगी जितनी भी घटिया किस्म की कार बना कर देंगे लोगों को लेनी पड़ेगी। और हर एक मामले में यही बात है। तो देश में इजारेदारों का कब्जा इस तरह हो गया है। वह नये कारखाने को बनने नहीं देते। मध्यम वर्ग में वह ताकत नहीं है कि गिरोह में आकर कोई नया कारखाना खोलें। इसलिए एक नया संकट पैदा हो गया है कि वह हाकिम हुक्काम हों, वकील या डाक्टर हों और चाहे मैं समझता हूं कि वह इस सदन के माननीय सदस्य भी हों, अगर वह पैसा कुछ उनके पास बचता भी है तो वह उससे जमीन खरीदते हैं। यह हिम्मत नहीं है कि दस बीस का गिरोह कोई छोटा सा कारखाना खोल दें क्योंकि इजारेदारों के मुकाबिले में वह जानते हैं वह टिकेंगे नहीं। कुछ सालों में ही दिवालिया हो जायेंगे। कारखाना बेचकर वापस आना पड़ेगा। सरकार कहती है कि हमारे यहां जमा करो। हम दस साल में दुगुना देंगे। लेकिन वह देखते हैं कि तब तक उस रुपये की कीमत चार आने हो जायेगी इसलिए इन के यहां पैसा जमा करेंगे तो वह 25 प्रतिशत ही रह जायेगा, 75 प्रतिशत गायब हो जायगा। तब लोग समझते हैं कि जमीन में जमा करो, कहीं जमीन खरीद लो। खेती करने के लिए नहीं, उपज बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि कैसी भी जमीन खरीद लो। जमीन कैसी भी हो, उसकी कीमत बढ़ती चली जायगी। ऐसी एक गैरहाजिर जमींदारी की प्रथा शुरु हो गई है और अधिकांश में हम लोग इसके शिकार हैं। हमारे हाकिम हुक्काम इसके शिकार हैं। जो विदेशी दूतावास में रह रहे हैं बीस बीस वर्षों से वह भी जमीन खरीद कर रख रहे हैं क्योंकि वह समझ रहे हैं कि बुढ़ापे में सुरक्षा का एक सहारा वही है क्योंकि इजारेदार लोग इजाजत नहीं देते हैं और कहीं रुपया लगा कर कोई कारखाना वगैरह खोलने की। इसीलिए यह नया मध्यमवर्गीय तबका भूमि-सुधार के खिलाफ हो जाता है क्योंकि वह न तो खेती करेगा और न अपनी संतान को खेती के लिए तैयार करेगा लेकिन अपनी जमीन लेकर रख देगा कि बुरे दिन के लिए वह जमीन हमारा सहारा होगी। इसीलिए एक नये किस्म की हालत पैदा हो रही है, खेतिहरों के हाथ से जमीन निकल रही है और खेती न करने वाला तबका जमीन पर मिल्कियत बढ़ाता चला जा रहा है क्योंकि उसे पैसा लगाने का उद्योग के अन्दर कोई सहारा दिख नहीं रहा है। अगर कोई इक्का दुक्का हिम्मत करता है तो उसे बीच में ही कुंठित होना पड़ता है। हमारे देश में हजारों कारखाने इस तरह के हैं कि जो 12 आने, 14 आने पूरे हो सके, लेकिन उसके बाद आगे नहीं बढ़ सके। 16 आने भी पूरे हो गए लेकिन उसके बाद करोड़पतियों के, इजारेदारों के दबाव से उत्पादन वहां नहीं हो सका।

15 Hrs.

हमारे यहां अशोक पेपर मिल में लगभग 8 करोड़ रुपया लग गया, फ्रांस से साढ़े तीन करोड़ रुपये का कारखाना आया। कारखाना बन कर तैयार है, डालमिया का हुक्म हुआ बिहार सरकार को कि इस को मत बनने दो, कागज

[श्री योगेन्द्र झा]

की इजारेदारी हमारी है। बिहार सरकार इस पर झुक गई। बीच में जो संविद सरकार आई उसने तय किया कि इसको अपने हाथ में ले लेंगे लेकिन अभी जो कठपुतली सरकार कायम की है हमारे गृह मंत्री महोदय ने बिहार के अन्दर उसने कहा कि हम नीलाम करा देंगे। कागज विदेश से आता है। कागज का किस्सा दूसरे सन्दर्भ में अभी हमारे माननीय मित्र गुप्ता जी कह चुके हैं। वह कागज विदेश से आता है लेकिन विदेशी मुद्रा बचाने के लिए भी, चूंकि डालमिया का हुक्म है इसलिए कागज का बना हुआ कारखाना भी चालू नहीं हो सका।

मैं इस पृष्ठभूमि में यह बात उठा रहा हूं कि देश में पच्चीसों लाख ऐसे आदमी हैं कि जो दस हजार, पन्द्रह हजार 20 हजार, 25 हजार या लाख दो लाख रूपया जो भी जायज या नाजायज तरीके से उन्होंने कमाया हुआ है, वह लगा सकते हैं गिरोह में मिल कर उद्योगों में लेकिन वह समझते हैं कि हम इस में कुछ कर नहीं सकेंगे। इस इजारेदारी को जब तक नहीं तोड़ा जाता है देश में बड़े पैमाने पर उद्योग नहीं बढ़ेगा और तब तक सप्लाई और डिमांड का कानून पूंजीवाद का आर्थिक कानून जो है वह, लागू नहीं हो सकेगा इसलिए कि पैदावार को वह कम कर देते हैं। लोगों की क्रय शक्ति घटी तो वह पैदावार को कम कर देते हैं और कम कर के दाम को बढ़ा देते हैं। कम ही पैदा करके वह मुनाफा को बढ़ा लेते हैं। यह इजारेदारों की करामात है। सरकार इस से मुकाबिला कर सके तो संभव है देश के औद्योगीकरण की तरफ हम बढ़ सकें और तब जो अभी सुचेता जी रोई हैं कि हमने बड़े कारखाने खोल लिए लेकिन उसका उत्पादन बेकार पड़ा है इस रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मशीन बेकार पड़ी है, इसलिए नहीं कि 55 करोड़ के देश में उसकी जरूरत नहीं है, बल्कि इसलिए कि लोगों के पास उसको इस्तेमाल करने की ताकत नहीं है इसलिए आज जो हमने सौभाग्य से ऐसी विशाल मशीनें पैदा करने वाले कारखाने तैयार किये उन को इस्तेमाल करने की ताकत हम लोगों में दे नहीं पाते हैं। सरकार कहेगी कि लोग करें, हम क्या करें इसमें? लेकिन लोग करेंगे किस बूते पर जब कि देश का अर्थ तंत्र मुट्ठी भर लोगों के हाथ में है। मैं इक्के-दुक्कों की बात नहीं करता हूं इसलिए कि इक्के दुक्कों से कुछ होने वाला नहीं है। अगर देश की गाड़ी ठीक चले तो इक्के दुक्के लोक टिकेंगे नहीं, उस से देश की प्रगति की रफ्तार बन्द नहीं होगी। लेकिन सारा अर्थ-तंत्र बिका हुआ है, सारी सरकार बिकी हुई है और दुर्भाग्य की बात है कि हमारा सदन उस असर से बाहर नहीं है। देश के कुछ करोड़पति पूरे बैंकों पर कब्जा किए हुए हैं। मेरे सवाल के जवाब में वित्त मंत्री ने कहा था कि कुल 41 करोड़ रुपया देश के प्राइवेट पूंजी वालों ने बैंकों में लगाया हुआ है। कुल उनकी पूंजी 41 करोड़ की है लेकिन उनके हाथ में 35 सौ करोड़ रुपया है और अब वह लगभग 4 हजार करोड़ हो गया है। वह पब्लिक का रुपया है जो लोग जमा किए हुए हैं, नौकरी पेशा करने वाले, मजदूरी करने वाले और कई इलाकों में किसान भी ताकि वक्त पर यह रुपया हमारे काम आयेगा। यह 4 हजार करोड़ रुपया उनके हाथ में आ गया है जिस रुपये से जिस समय भी वह चाहेंगे दाम गिरा देंगे, जिस समय चाहेंगे बढ़ा देंगे। और वित्त मंत्री पता नहीं समझ कर के या नासमझी में कहते हैं जूट का भाव गिरा, ईख का भाव गिरा, कपास का भाव गिरा, हम सभी जानते हैं कि जूट के इजारेदार मालिक लोग, जब जूट बाजार में आता है, बाजार को मंदा कर देते हैं। जूट के छोटे छोटे व्यापारी कलकत्ते में और और दूसरी बड़ी बड़ी जगहों में कैम्प लगाते हैं, पड़े रहते हैं इजारेदार कहते हैं कि जरूरत नहीं है। दस रोज, पन्द्रह रोज किसान गाड़ी लिए हुए बैठा रहता है, बैलों को खिलाता है, खुद खाता है और आखीर में मजबूर हो कर जो 60 रुपये के भाव पर बेचने के लिए आया था वह 15-20-25 या 30 रुपये में उसके हाथ बेचकर वापस चला जाता है।

उपज से उस का कोई सम्बन्ध नहीं है। जो बैंकों के मालिक हैं, जो थोक बाजार के मालिक हैं, जो दश के व्यापार के मालिक हो गए हैं, उनके हाथ में यह चीज हो गई है। इसीलिए जहां पांच साल पहले जूट की जो पैदावार थी वह पिछले साल उस से कम पर आ गई है। पिछले साल दाम जो बढ़ा वह इसलिए कि जूट की मिलें जब बन्द होने लग गई तो मिल वालों ने दाम बढ़ाया तब बढ़ा। इस साल किसान ने जूट बोया और फिर ज्यों ही नया जूट बाजार में आया उसका मूल्य घटा कर आधा कर दिया गया।

अभी वित्त मंत्री खुशी मना रहे हैं कि कीमतें कुछ नीचे आ रही हैं। अभी कीमतों में कमी का कारण यह है कि जहां तक अनाज का सवाल है किसानों से सस्ते दर पर लूटने का वक्त है इसलिए अभी यह इजारेदार चाहते हैं कि कम दाम पर उनके हाथ में यह आये। लेकिन जब बैंकों के गोदामों में वह गल्ला चला आयेगा तो यह निश्चित है कि महीने दो महीने के अन्दर वह दाम फिर बढ़ायेंगे जब किसान के हाथ से निकल जायगा। गांवों में जो बड़ी बड़ी जमीनों के मालिक हैं, जिन के पास रुपया है, वह अपने पास में उसको रख सकेंगे लेकिन साधारण किसान नहीं रख सकेंगे। उन को लगान देने के लिए, कर्जा देने के लिए, कपड़ा खरीदने के लिए, जिन्दा रहने के लिए वह गल्ला बेचना ही है। यह सस्तेपन का सबूत नहीं है। यह कृत्रिम सस्ती है और वह कृत्रिम महंगी है। इस मौके पर यह आशा की जाती थी कि हमारे वित्त मंत्री उस सवाल को छूएंगे। पिछले साल बजट के वक्त उन्होंने कहा था कि रुपये की बढ़ती हो गई है इसीलिए हम सन्तुलित बजट पेश कर रहे हैं। जो सन्तुलित बजट हमारे सामने आया वह हम सभी जानते हैं। उन्होंने वादा किया था, कई सदस्यों ने याद भी दिलाया है, कि वह नोट नहीं छोपेंगे। लोगों को भ्रम हो जाता है और शायद वित्त मंत्री को खुद भी भ्रम हो जाता है कि वह बड़े मजबूत हैं। लेकिन हम जानते हैं कि वह मजबूत हैं जहां पर कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता देने का मामला है, वह मजबूत हैं जहां पर आम जनता पर टैक्स लगाने का मामला है लेकिन वह बहुत ही दब्बू और बुजदिल हैं जहां करोड़पतियों से टक्कर लेने का मामला आता है। इसीलिए वादा किया था कि हम नोट नहीं छापेंगे लेकिन 300 करोड़ छाप कर रख दिया। कम से कम इस वादे के नाम पर अगर वह मजबूती कुछ भी होती तो आज वह नया बजट लेकर हमारे सामने नहीं आते, अपना इस्तीफा लेकर आते कि अपना वादा हम निभा नहीं सके, हमने नोट छाप दिया, इसलिए हम इस्तीफा देते हैं। पिछले साल 300 करोड़ छापा और इस साल कहते हैं कि 290 करोड़ छापेंगे। जब कुछ छापने को नहीं कहा था तब तो 3 सौ करोड़ का छापा और और अब की 290 करोड़ छापने को कहा है तो पता नहीं इसका अन्त कहां पर होगा? लेकिन जहां तक बजट का सवाल है यह बजट जो हमारे सामने है, इसका मुख्य रूप क्या है, इसका मुख्य चरित्र क्या है। मेरा सदन से आग्रह है कि इस सवाल पर विचार करें यह बजट देश के विकास को रोकने वाला है, यह बजट योजना विरोधी है, यह बजट विश्व बैंक के इशारे पर तैयार किया हुआ बजट है।

पिछले साल 1172 करोड़ रुपये योजना के मद में रखे गये थे, इस साल 1179 करोड़ रुपये रखे गये हैं, यानी 7 करोड़ रुपये की बढ़ती दिखाई गई है, जबकि 14 परसेन्ट की मंहगाई में बढ़ती हो गई है। अगर इसका हिसाब लगाया जाये, तो पिछले साल से लगभग 200 करोड़ रुपया की कमी का योजना मदवाला बजट है। अब कहते हैं कि यह जो 140 करोड़ रुपया हम बफर स्टाक बनाने के लिय खर्च कर रहे हैं, अन्न भंडार बनाएंगे जिसमें 35 लाख टन विदेशों से आने वाला अनाज भी शामिल है, वह सारी रकम भी योजना-मद में आ जायेगी। आज का जो पूंजीवादी अर्थ शास्त्र है, उसके मुताबिक भी यह बात नहीं कही जा सकती। यह वित्त मंत्री का अपना अनर्थशास्त्र है। ये

[श्री भोगेन्द्र झा]

कहते हैं कि खाद्यान्न की जो रकम है, वह योजना मद के लिये दी जा रही है, लेकिन हो क्या रहा है जो 140 करोड़ रुपया अन्न भंडार बनाने के लिय ले रहे हैं, उसमें से 107 करोड़ रुपया तो सबसिडी का ही छीन रहे हैं। ऊपर से तो उपभोक्ता देखे कि हमारी जेब में 140 करोड़ रुपया दे रहे हैं, लेकिन नीचे से उसकी पौकेट मार कर 107 करोड़ रुपया छीन रहे हैं।

मैं यह बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि हमारे वित्त मंत्री जी ने अपने इस बजट के द्वारा एक बहुत ही गंभीर खतरे की घंटी बजा दी है—देश के करोड़-पतियों को, इजारेदारों को 85 करोड़ रुपये की करों में छूट दी गई है और दूसरी तरफ आम जनता पर 81 करोड़ रुपये के नये करों का बोझ लाद दिया गया है। शायद आम जनता बहुत पैसेवाली हो गई है, इसीलिये 81 करोड़ रुपये के नये टैक्स लगाये गये हैं। करोड़पति लोग बड़े दरिद्र हो गये हैं, इसलिये उन को 85 करोड़ रुपये की छूट दी है, लेकिन करों की बढ़ोत्तरी का जो एलान किया गया है, उसमें एक एक्सपेंडिचर टैक्स उन पर लगाया गया है, जिससे तीन लाख रुपये की आमदनी होगी—यह क्या मजाक है, अगर आप इसको भी छोड़ देते, अगर इस का भी कर दान कर देते, तो बेहतर था। वास्तव में देखा जाये, तो यह बजट बड़े पूंजीपतियों का बजट है, इजारेदारों का बजट है। लेकिन अगर देश के इजारेदारों का ही होता, तो भी बात समझ में आ सकती थी जैसे मैंने कहा कि हिन्दुस्तान मोटर्स अगर बिरला का ही होता, तो भी मैं समझ सकता था कि आज नहीं तो कल यह धन भारतीय जनता का होगा। लेकिन उसमें "नेफील्ड" की साझेदारी है, उसके बहुत से पुर्जे ब्रिटेन से आते हैं और इस तरह के देश में दो हजार विदेशी साझेदारी के काम कायम हो गये हैं। इस विदेशी पूंजी ने हमारे देश की लगाम को इस तरह से कस दिया है कि आज भी टाटा की मजाल नहीं है कि अपने 501 को लेकर सनलाइट का मुकाबला कर सके, हम्माम को लेकर लक्स का मुकबला कर सके। हमारे इजारेदारों की आज हिम्मत नहीं है और वे विदेशियों के सामने समर्पण कर रहे हैं साझेदारी कर रहे हैं। एक तरह से दोगला पूंजीवाद देश में खड़ा हो गया है जो देश के कल-कारखानों को बढ़ने नहीं दे रहा है। इस स्थिति में अगर ये बैंकों को हाथ में नहीं लेते हैं इजारेदारों को तोड़ते नहीं तो देश का औद्योगीकरण नहीं होगा। तो बाजार पर नियंत्रण नहीं कर सकते हैं अगर बाजार पर नियंत्रण नहीं कर सकते हैं तो भाव इनके हाथ में नहीं रहेगा। इस देश में फसल चाहे अच्छी हो या बुरी, जब भाव गिरने का वक्त आयेगा, बैंक मालिक इसका फायदा उठा जायेंगे, चुराया हुआ रुपया, जो कि तीन-चार हजार करोड़ रुपये के लगभग है, वह सामने आ जायेगा अगर मोरारजी भाई कुछ ऐसी व्यवस्था करते कि यह चुराया हुआ काला रुपया ऊपर आ जाता तो भी मैं समझ सकता था लेकिन इस बजट में उसका कोई जिक्र नहीं है, अब क्या होगा कि वे इस चोरी के रुपये से बाजार में गल्ला खरीदेंगे और इस तरह से उस के भाव को गिरने नहीं देंगे। उसको ऊंचा कर देंगे। इसलिये जब तक ऐसे रुपये पर अंकुश नहीं लगेगा, आप इस में सफल नहीं हो सकेंगे। आप बैंक के रुपये पर सामाजिक नियंत्रण कर रहे हैं, जिसका एक ही मकसद है—गांव के जमीदारों को पूंजी देना, ताकत देना, जो गरीब खेतीहरों को, खेत जोतने वालों को बेदखल कर देंगे, उनको वहां से निकाल देंगे इस तरह से गरीबों की जमीनों को छिनवाकर, जमीदारों को ट्रैक्टर दे कर, अच्छा बीज देकर, खाद दे कर आप पैदावार कराना चाहते हैं लेकिन इस में भी 20 वर्ष लग जायेंगे। दूसरी तरफ अब किसान बेदखल होना बरदाश्त नहीं करेगा। देश में अशांति फैलेगी औ रइस तरह से क्रय-शक्ति बढ़ाने का सवाल बाजार का सवाल भी हल नहीं होगा इन मुट्ठी भर जमींदारों को इजारेदारों को बरदाश्त नहीं किया जायेगा। आज यह हालत है कि कल-कारखाने बन्द होते

जा रहे हैं, जब नये कारखाने खुलेंगे तो उनकी क्या हालत होगी? इस लिये आज स्थिति यह है कि जब देश की तीन-चौथाई से अधिक आबादी देहातों से है, तो कारखाने का सामान तभी बिकेगा जब पैसा उनकी जेब में जाय उनकी क्रयशक्ति बढ़े जोत की जमीन पर उनका स्वामित्व हो उनकी जमीन में अच्छा बीज पड़े, उनके लिये पानी की व्यवस्था हो आपने खाद के नाम पर जो छूट दी है, उसका लाभ इजारेदारों को मिलेगा, गरीब किसानों को नहीं मिल सकेगा।

आपने इस बजट में कहा है कि इस समय जो बड़ी योजनायें चालू हैं, हम उसी से काम चलायेंगे, यानी नई बड़ी योजनाओं को हाथ में नहीं लेंगे, छोटी योजनाओं पर ही ध्यान देंगे। उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी योजनाओं के सम्बन्ध में ये अगर कहते हैं कि कुछ ही योजनायें हम इस साल में पूरी कर लेंगे तब भी थोड़ा सब्र होता। लेकिन, हम ऐसा समझते हैं कि गन्डक योजना, पश्चिमी कोसी योजना, नागार्जुन सागर योजना, तुंगभद्रा योजना---ऐसी योजनायें हैं जो देश को खुशहाली प्रदान कर सकती हैं। केवल गन्डक और पश्चिमी कोसी नहर योजनाएं ही ऐसी योजना है, जिसके द्वारा 50 हजार एकड़ भूमि में सिंचाई हो सकती है और जिसके द्वारा बिहार हर साल फाजिल गल्ला दूसरे राज्यों को दे सकेगा। इसमें किसी विदेशी मुद्रा की जरूरत नहीं है, विदेशी मशीनों की जरूरत नहीं है सिर्फ इनके कागज के नोटों की जरूरत है, जो कि 290 करोड़ रुपये के ये छापने जा रहे हैं। लेकिन इस काम को पूरा करने के लिये इन के पास नोट भी नहीं हैं, जहां विदेशी मुद्रा की जरूरत नहीं है, उस सिंचाई में पैसे खर्च नहीं करेंगे, लेकिन खेती के नाम पर करोड़पतियों को छूट देते चले जायेंगे। खेती की पहली आवश्यकता पानी है, परन्तु बड़ी सिंचाई योजनाओं के लिये ये रुपया नहीं देते। खेती के विकास को जिस तेज रफ्तार से आज बढ़ाने की जरूरत है, ये उस को कुंठित कर देना चाहते हैं।

जहां तक कीमतों का मामला है, कीमतें बढ़ी हैं जब हम मंहगाई भत्ता बढ़ाने की मांग करते हैं तो हमको उपदेश देते हैं कि मंहगाई भत्ते की मांग न करो। 85 करोड़ रुपये की करोड़पतियों को छूट देकर, आम लोगों पर 81 करोड़ रुपये का कर का बोझ डाल कर और पिछले चार सालों में 60 फीसदी मंहगी बढ़ा कर, अब हम को कहते हैं कि पेट पर पट्टी बांध लो, मंहगाई भत्ते की मांग न करो जो मन्जूर हो चुका है उसको भी मत लो, हमारे पास छोड़ दो। हमारे वित्त मंत्री जी देश के लोगों को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर कोई कुछ कहेगा तो हम चौहान साहब से कहेंगे कि अपनी लाठी-गोली ले कर आ जाओ और लोगों को दबाओ। दिल्ली के शिक्षकों के साथ इन्होंने वह रास्ता शुरु भी कर दिया है। शिक्षकों, मजदूरों को अन्य नौकरी पेशा वालों को जेल दो, दमन करो और करोड़पतियों को करों में छूट दो, यही इनका रास्ता है।

सभापति महोदय : आपका टाइम खत्म हो गया, अब आप बैठ जाइये।

श्री भोगेन्द्र झा : सभापति महोदय, मैं अपने दल का समय ले रहा हूं और उसी के अनुसार बोल रहा हूं। अगर कोई दूसरा कायदा हो, तो हम उसको मानेंगे।

सभापति महोदय : आपके दल के 55 मिनट हैं, जिसमें 23 मिनट आपने ले लिये हैं, आपके तीन मेम्बर्स बोलने वाले हैं। आप आपस में फैसला कर लें, अगर सिर्फ आप ही बोलना चाहते हैं तो 55 मिनट भी देने को तैयार हूं।

श्री भोगेन्द्र झा : हमारे दो सदस्य बोलेंगे।

सभापति महोदय : आप 55 मिनट बोलिये, लेकिन इसमें दूसरों को नुकसान होगा।

श्री भोगेन्द्र झा : सभापति महोदय, जहां तक हमारे कृषि उत्पादनों का सवाल है, इसमें 20 प्रतिशत वृद्धि का इनका अन्दाजा है, राष्ट्रीय आय में 11 प्रतिशत वृद्धि का

[श्री भोगेन्द्र झा]

अन्दाजा है, लेकिन उसके बावजूद भी मंहगाई बढ़ेगी, करीब करीब 12 फीसदी बढ़ेगी—यह इनकी बात है। जब तक ये बैंक और थोक बाजारों को अपने हाथ में लेने की हिम्मत नहीं करते हैं, तब तक चाहे कुछ भी करें, यह लगाम इनके हाथ में नहीं रहेगी, तब तक मंहगी को रोकना इनके लिये सम्भव नहीं हो सकेगा। ऐसी हालत में श्रमिक और अन्य वेतन भोगी मंहगाई भत्ते की मांग करने को मजबूर होंगे ही। मैं तो समझता हूं कि इस सरकार ने इस बजट के जरिए इस देश के मेहनत करने वालों से यह कहा है कि तुम भूखे रहो, पैसे की मांग नहीं करो, पैसा तो हमने करोड़-पतियों को दे दिया है, तुम बोलोगे तो जेल में बन्द हो जाओगे और लाठी डन्डे खाओगे। इसलिए मैं अपील करता हूं कि अगर आप शांतिपूर्ण विकास चाहते हैं तो देशी और विदेशी इजारेदारों के हुक्म पर चलना बन्द करें, नये कारखाने खुलवाने के लिए प्रोत्साहित करे। आज इंजीनियरिंग, मशीनों का तमाम सामान बेकार पड़ा हुआ है, उनकी उत्पादन शक्ति बेकार पड़ी हुई है वह सामान इस्तेमाल हो जायगा। लेकिन मैं तो समझता हूं इस देश में समाजवाद का नाम केवल ठगने के लिए लिया गया है, वास्तव में देश पूंजीवाद के रास्ते पर चलता आ रहा है। उस पूंजीवादी रास्ते ने देश को यहां तो इजारेदारों के शिकंजे में ग्रसित करा दिया है। जिस प्रकार एक 5–6 साल की लड़की के गर्भ रह जाए, वही हाल भारतीय पूंजीवाद का हो गया है। आप जनता को बढ़ने नहीं दे रहे हैं। आज हिन्दुतान में खेती और कल-कारखानों में बड़े पैमाने पर पैदावार को बढ़ाने की आवश्यकता है। हमारे वित्त मंत्री को तो छिपे छिपे फारमोसा से प्रेम है, जापान से प्रेम है लेकिन उनकी नकल करके भी वे आगे नहीं बढ़ते हैं। फारमोसा में 5–6 एकड़ पर हदबन्दी कर दी गयी है और जापान में भी 5–7 ऐकड़ की हदबन्दी कर दी गयी है। वे लोग आज मेहनत कर रहे हैं और कृषि उत्पादन में काफी आगे हैं। घनी आबादी वाले हमारे इस देश में आज उसकी बहुत ही जरूरत है। लेकिन यहां तो समाज से दूर रहने वाले नेता, मिनिस्टर, अफसर, व्यापारी और संसद सदस्य जमीन के मालिक हैं। श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा ने यहां पर एक बार कहा था कि वे भी किसान हैं। जब इस तरह का रास्ता आप अपना रहे हैं तो उससे असन्तोष बढ़ेगा और जब असन्तोष बढ़ेगा तो जन-समर्थन खिलाफ हो जायेगा, और वे आपके खिलाफ वोट देंगे। जब वोट आपके खिलाफ जायेगा, दूसरे दलों की सरकार बनेंगी तो फिर आप उन सरकारों को अपदस्थ करने के लिए राज्यपालों का इस्तेमाल करेंगे जैसा कि आजकल आप कर भी रहे हैं।

मैं केवल एक बात की ओर ही ध्यान दिलाना चाहता हूं कि बिहार में 92 फीसदी आबादी गांवों में रहती है। वहां पर जब कांग्रेस की सरकार थी पहले तो उसने 20 वर्षों में कुल मिलाकर 6294 ट्यूबवेल गड़वाए लेकिन संविद सरकार ने एक साल में 9081 ट्यूबवेल लगवाए। कांग्रेसी सरकार ने पंपिंग सेट्स बीस सालों में 18443 लगवाए जबकि संविद सरकार ने केवल दस महीनों में ही 55543 पंपिंग सेट्स लगवाए। लेकिन ऐसी सरकारों को आप किसी प्रकार से भी दबाना और उलटना चाहते हैं। इसलिए जो बजट पेश किया गया है इसको अस्वीकार कर दिया जाना चाहिये। हमारे वित्त मंत्री जी भी हिम्मत दिखलायें और इसको वापिस ले लें। देश के हित में, कल कारखानों के विकास के लिए, कृषि के विकास के लिए, उन्नत बीज और सिंचाई की गारन्टी करने के लिए ताकि पानी के बिना जमीन सूखी न रहे, मैं सदन से इस बजट को ठुकराने का आग्रह करता हूं और वित्त मंत्री जी से भी आग्रह करता हूं कि यदि वे बजट को वापस ले लें तो बेहतर होगा।

SHRI N. K. P. SALVE (Betul) : Mr. Chairman, all those who had carefully studied the budget presented last year

had expressed considerable apprehension over the fact that the Budget was likely, ultimately, to result in deficit financing, unless the Finance Minister resorted to a massive increase in direct and indirect taxes. It did result in deficit. And realising the somewhat irrational animus we had seen on the part of the Finance Minister so far as deficit financing was concerned, one was also apprehensive that it was likely that rather than supplement the resources with deficit financing, the finance Minister would increase direct and indirect taxes which have already had caused considerable burden and hardship to the taxpayers.

But when he presented this budget on his 18th birthday, on the 29th February, his seventy-second year, there was a pleasant surprise. It was a very happy feature to know that the Finance Minister was not so rigid and inflexible as he is reputed to be, and one found that he was amenable to reason in his views on policy matters because that was necessary in the larger interests of the country. He accepted a change in his approach, that is the essence of open-mindedness. He has adopted a new policy, and that is one reason why I consider that the budget proposals this year are less unrealistic, less exuberent, more businesslike, and more functional. It was inevitable that deficit finance would raise a controversy, and unless the controversy had been raised, possibly the debate in the House might have receded into a tame affair. That is at least one contribution that deficit financing has done. It has made the budget discussion a little more lively.

But then, deficit financing is a matter which has been studied by financial experts especially with reference to economies of developing countries, and it has been found by them that deficit financing is to the economy of a developing country what salt is to a human being. It is imperative and essential to a degree, but it is likely to be disastrous and poisonous beyond a certain point. It is an accepted budgetary expedient, of immense benefit if it is applied conscientiously skilfully and within limits. It is a very advantageous budgetary expedient which can be used to supplement the resources *inter alia* for purposes of our developmental plans. That is one reason why though the last budget was ostensibly very well balanced and in this year's budget there is a deficit, you will find that the reaction in the investment markets in Madras, Delhi, Bombay and Calcutta is very much favourable. Therefore, let us not be obsessed merely by the fact that there is deficit financing in this budget. An objective and a realistic assessment and evaluation may be made of the impact of this deficit financing on our economy. If it is confined to a quantum of Rs. 290 crores, as envisaged in the budget proposals, I have no doubt in my mind that notwithstanding this deficit financing, the budget has brought about a silver lining to our entire economy, and even this much-maligned institution of deficit financing has proved to be of help to us.

The two preceding years were perhaps the most critical in the post-independence period so far as our troubled economy is concerned. Between the forceful inflationary pressures on the one side and the nearly unbreakable restrictive and constrictive pressures of recession, the economy of the country was being crushed, and strained to a point where a crash looked inevitable, unless the position was retrieved. The position was that expenditure on plan alone could revive the economy, and therefore it has to be decided whether resources were to be supplemented by additional taxation or reasonable deficit financing. I must congratulate the Finance Minister that he has taken recourse to the latter expedient. The need of the hour was to desperately retrieve the economy of the country by retrieving the investment market from the abyss of depression and despondency.

MR. CHAIRMAN : He may only occasionally refer to his notes.

SHRI N. K. P. SALVE : I am only referring to my notes on certain matters; where I want to be very precise in what I say, I read a line or two. After all, a member should be forgiven for being precise sometimes at least. I am grateful to you nonetheless. I have to speak a whole lot in a limited time.

MR. CHAIRMAN : It should be occasionol.

SHRI N. K. P. SALVE : The need of the hour is desperately to retrieve the economy of the nation by retrieving the investment market from the abyss of depression, and despondency and retrieving the pace of industrial progress, retrieving the pace of our plans and retrieving the lost confidence and determination of businessmen, industrialist the farmer and last but not the least the common man. The budget proposals seek to achieve all this, deficit financing notwithstanding and the budget is therefore a budget which is retrieval oriented budget. So much in favour of deficit financing. But a word of caution is certainly necessary about deficit financing. In fact I must concede as the hon. Member Shri Kanwar Lal Gupta said that deficit financing does have some of the characteristics and attributes of additional taxation. I go a step further and say that it is in the nature of invisible taxation because Government draws from the stocks certain goods and services and pays for them by printing notes. Naturally, it is going to have some inflationary effect and bring about depreciation in the purchasing power of the rupee. Consequently, there is an abridgment in the personal resources of the people and they are not able to command such goods and services as they would otherwise have done. But the question is : in which mode, and manner should the plan be financed ? Could it be financed with the help of deficit financing, that is, invisible taxation or with the help of additional visible taxation ? It has been a right decision of the Finance Minister to prefer invisible taxation, because the deficit is not going to have an adverse effect on the retrieval process of our economy as there are signs of revival of the pace of industrial growth with happy increase of last year's kharif and this year's rabi crops, the redeeming trend of prices declining after October, 1967, the indications are that the burden of invisible taxation, if confined to a maximum of Rs. 290 crores may not strain the citizens any further, and yet give a great fillip to the economy. One very good reason why deficit will not strain, if it is of the order of Rs. 290 crores only, is that it is less than that of the last year with a positively improved prospects of industrial and agricultural production; with its consequent margin to absorb the additional burden, the prices are more than likely to be left unaffected by the deficit of Rs. 290 crores.

There are some other aspects I should now like to consider in my speech. About public sector undertakings, time and again in this House, considerable concern had been voiced about their working and all sorts of allegations had been made. The Finance Minister has come in for fairly scathing indictment for providing Rs. 110 crores for Bokaro in a year when there is so much deficit financing. I have no doubt in my mind that this type of criticism is absolutely inevitable because some of the critics of the public sector undertakings are not so much critics of the undertakings as they are of the very concept of the public sector. It must be clearly understood that the Congress Party's economic policies and programmes would make a mockery of its avowed profession of establishing a socialist pattern of society if it did not in a mixed economy contemplate building a mighty and powerful public sector to be a tower of country's economic strength. So, Bokaro is a challenge to our determination, tenacity and perseverance and we must go ahead with it and bring about a sucecssful completion of this project. The entire Rs. 110 crores provided in the budget is not coming out of the deficit finance. If the hon. Members who had been criticising the Finance Minister for this had cared to look into the explanatory memorandum of the budget, they would find that Rs. 41.31 crores will come from the USSR and we will have to put in only Rs. 66.69 crores. But, it is absolutely necessary for me to point out that Bokaro must not be allowed to become a bottomless pit. It is said that the per unit cost of the whole project of Bokaro is going to be nearly two or three times that of Japan, Italy and France. The unit cost is the cost of a project which is ascertained by dividing the total cost of the project by its capacity. I have collected some figures which reveal that there is a very startling disparity between the cost which is going to be on our head for Bokaro

and the unit cost of such a plant elsewhere in the world.

My figures are here and I would beg the Finance Minister to bear with me. If these figures are correct, I am sure he will take note of these and do whatever is possible to bring about a reduction in the cost of Bokaro. In Fukuyama, in Japan, which was completed in 1966, the unit cost is Rs. 992. In the Spencer Works in the United Kingdom, which was completed in 1962, the unit cost was Rs. 1,170. In Toranto in Italy, which was completed in 1964, the unit cost was Rs. 861. In Dunkirk, France, which was completed in 1963, the unit cost was Rs. 960. As against these figures, I would draw your attention and through you the attention of the House and of the Government that the Soviet estimate for Bokaro is Rs. 2,860 per unit cost. There is a very great disparity. The unit cost is arrived at by dividing the total cost of the project by its capacity. So, as against Rs. 992, 1,170, 861 and 960 in Japan, United Kingdom, Italy and France respectively, the Soviet estimate for Bokaro is going to be Rs. 2,860. I have no doubt in my mind that the Soviet Union has been one of our greatest frineds. It is one of those countries which hos stood by us in time of need.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI K. C. PANT): What capacity is he taking into account ? Are they comparable capacities ?

SHRI N. K. P. SALVE : The capacity as in the Soviet estimate; as mentioned in the Russian's project report. The capacity is mentioned in the project report of the Soviet experts. I am willing to place these figures before the hon. Minister and if he cares to go into the matter he may find more authentic data. I only request the hon. Minister that it is necessary for him to see and determine what steps should be taken to bring about a reduction in cost in Bokaro. We must have Bokaro; it is an absolutely undoubted proposition. The whole thing is, how to bring about economy in its cost. We are collaborating with Russia in this project they have been one of our old friends and we value their friendship, notwithstanding the fact that I and many like me may have our own views and grievances about their political idealogy, and we may have our own personal feelings about it. But they have been our friends; and surely in Bokaro we are not going to pay any hush-hush money for their favours nor are we going to pay them a penny more than what is warranted by exigencies of the pure business consideration. So, I am sure the Finance Minister will kindly look into this aspect.

It is true, and it must be understood that the public sector undertakings, by their very nature, are such and their plants and business cannot be run purely for profit-making purposes like any other commercial concern. Therefore, sometimes there is a longer gestation period because of the nature of the plant and the public obligation, then there is the private sector undertakings. It is, unfair, therefore, to run down the public sector undertakings merely because the return is not as much as it is in the commercial undertakings in proportion to the overall capital. But then, it has to be conceded that all is not well with our public sector undertakings, and we will have to be extremely vigilant.

Take steel for example. We had the cheapest steel made in the world in the forties. But today it is one of the most expensive steel. The only reason for this is that we have just not cared to keep pace with developing technology. One very undoubted misfortune which pervades our public undertakings is the menace of inexperienced, untrained, bureaucrats occupying the highest posts by craft and manoeuvres in the Ministry. Secondly, what is worse is, that politicians who are rejected by their electorates, find an asylum in public sector undertakings. These undertakings cannot be run as charitable institutions. The best and experienced technologists alone must manage these plants. The Hindustan Steel Plant at the moment, it is well known, are in the doldrums. Still, today, in the papers, I read that a politician is being tipped as Chairman of Hindustan Steel. I only hope that seeing such heavy stakes, the Finance Minister would not

[Shri N. K. P. Salve]

allow our Hindustan Steel to be reduced to a charitable institution. If a new Chairman is to be selected, I would only sugegst that a person of long standing and experience in this steel technology and we have such men in our country—must be appointed.

The next aspect I would like to deal with is with regard to the revision of postal tariff. A very very scathing indictment is coming on the Finance Minister for revising the postal rates upwards. I should like to join all those who are attacking him, for who would like to take an unpopular cause. But I sympathise with him for the simple reason that the postal services have to be in principle made self-sufficient. There is the report of the Tariff Commission on the basis of which these postal rates have been revised upwards. There has been all these years a chronic deficit in this department. Last year in the postal branch itself the deficit aggregated to Rs. 16.81 crores and in the telegraph branch it aggregated to Rs. 5.86 crores. Surely, in principle, everyone must accept that if a service is to be rendered by the Government that service has to be self-sufficient and only those who avail of the service must bear the burden of the same.

But I would like to draw the attention of the Finance Minister to one very important aspect of the matter. I have found that the standard of efficiency of our postal department is so low that it can only match with the low charges that we pay for postal tariff. In fact, the efficiency of this department is particularly low and considerable improvement must be made. I may not have any objection to the rates being revised—I hope on the postcard and the inland letter paper there will not be such an unkind increase, though there is no doubt that in the overall budgeting the postal department should be self-sufficient. But what is necessary is that the standard of efficiency of the postal department must improve. After all, letters must reach us if not in 15 or 20 days then at least in one month, express letters must reach us before ordinary letters and telegrams must reach us at least in four day time—even that would be efficient service. If you want to wreck vengeance on somebody instal a telephone in his house through the kindness of the Minister here who is a very kind man. You will be putting him in unending troubles because at three o'clock in the morning the telephone will start ringing only to be told that it is 'wrong number'. Therefore, if there is to be increase in the postal tariff, which is very much necessary and warranted by exigencies of circumstances, and to adhere to the principle that postal department has to be self-sufficient, let there be a corresponding increase in economy together with sincere endeavours made to increase the efficiency of this department.

There are new levies of excise on confectionary chocolates, artiolficial leather cloth, embroidery, steel furniture, parts of wireless sets and crown corks. Except parts of wireless sets and crown corks other items are consumed by affluent section of the society and since it is used by them I will not take up their unpopular cause. Therefore the new levies are excepting the levy on chocolates. I would like the Finance Minister to consider and reconsider that this Rs. 2.40 crores is a revenue which he is going to take out of the pocket monies of children. They should be spared. Children of every section of our society love chocolates. In our country the leaders have been very popular with the children. It would be unfair to take Rs. 2.40 crores out of the pocket money of children. I hope there will be a chocolate-like attitude and the Finance Minister will give relief to these youngsters.

There is one aspect regarding the excise law to which I would like to draw the attention of the Finance Minister particularly. Under the excise laws and rules the executive is entitled to reduce the rates of excise which we fix here and in practical working the same virtually reduces all that we pass by way of rates to a notional or academic discussion. It dilutes Parliament's authority. We may pass any rate but that rate is never operative. The executive by its authority under the rules bring about a completely different rate. And about such changes there is no intimation to Parliament, the paper is never laid on the Table and no reason is given.

MR. CHAIRMAN : While his speech is very interesting, the time is running short.

SHRI N. K. P. SALVE : I am running against time. I hope you will give me another two minutes.

I hope the Finance Minister would be able to give an assurance that hereafter whenever there is any revision in the rates as a result of which the rates passed by Parliament are changed, the relevant orders will be laid on the Table of the House and the reasons given for the same.

The concessions and assistance contemplated in the budget proposals to boost export are very laudable. The exports have shown a slight increase in the recent months. But it is very regrettable that India, which once enjoyed a monopoly of manganese export, has almost been whistled out of world market.

The performance of MMTC, another public undertaking under the vicious grip of a well-meaning inexperienced ICS officer, eternally on tour abroad, needs to be scrutinised and drastic endeavours made to recover export market of manganese.

The proposed changes in direct taxes is a mixture of expedient provisions. The reduction of excess dividend tax, the surtax from 35 per cent to 25 per cent, weighted allowance of expenses for export promotion as well as expenses on improving agricultural productivity, abolition of surcharge have had a salutary effect on the investment market.

In the end, to sum up, I think it would be unfair not to recognise that the Finance Minister under the circumstances could not have done any better in fact, he has charted the wisest course. And, therefore, I would say of him what Tennyson said of a wise, faithful and a beautiful young woman :

> To doubt her fairness were to want an eye to see
>
> To doubt her pureness were to want a heart to feel
>
> To doubt her wisdom were to want a head to think.

SHRI HUMAYUN KABIR (Basirhat) : Mr. Chairman, I recognise that the Finance Minister this year had an extremely difficult situation to face. He had increased taxes last year but very often these increases instead of giving him additional revenue had led to a deterioration in the situation. The economy has been stagnant in the last two years. There were some signs of a pick-up from October 1967 and it was necessary for him to adopt measures so that this buoyancy was kept up and nothing was done to retard the growth of the economy. He was, therefore, operating within very strict limitations and, within those limitations, I would congratulate him for facing the problem boldly and giving us a budget which keeps the economy going on. It has kept the patient alive and promises to keep the patient alive. But I regret I cannot extend to him the same congratulations in devising remedies which will cure the patient completely so that medicines may not be necessary in future. It is a continuing budget, a budget which will more or less help us to job along. But this budget does not contain some of those special measures which are necessary if the economy is to be revived and in the two major dangers facing India today are to be overcome.

The budget is an occasion when we review the entire policy of the Government and, in fact, almost every aspect of administration can be examined and suggestions made. I shall not, therefore, go into details about specific proposals but shall confine myself mainly to certain general issues. I will make only one exception, and that is in respect of increase in the postal rates. A number of speakers have spoken about it, and the speaker who just now sat down, my hon. friend Shri Salve, while paying a compliment to the Finance Minister at the same time was also all the time pulling his legs a little and suggesting that many changes are necessary, not the least of it in the postal rates.

It is true that the postcard has always been a loss to the postal department. But it is not necessary that every single item in any department must be self-support-

[Shri Humayun Kabir]

ing and economic. The postcard is the poorman's way of communication throughout the country and, therefore, even if there be some loss so far as postcards are concerned, I think there is no justification for the hon. Finance Minister to raise the rates on postcards. He may make the Postal Department as a whole self-supporting by altering the rates elsewhere but, so far as the postcards are concerned—perhaps, so far as inland letters also are concerned—there should be re-examination.

But I have also a shrewd suspicion that the Finance Minister will again exhibit the same dry and wry humour which marked a good deal of his speech this time. He revealed one new aspects of his personality during the last Budget speech and made the House laugh more often than perhaps he has done in the past and, perhaps, when he gives his reply to the debate, he will again give up an occasion of pleasure in reducing the surcharges which he has indicated on the post-card and the inland letter maintaining them at their original prices. This is a recommendation which, I think, he will receive from every side of the House and like a true democrat, I hope, he will yield to the wishes of the House in this matter.

Now, as I said, I wish to confine myself to certain major issues and the general approach rather than to specific questions. I think, the two major dangers which face the country today are, firstly, the political unsettlement which we find in different aspects of national life and secondly, the economic stagnation which has been dogging us almost incessantly from 1962-63. If we look at the three Plans we find that there was a definite and steady increase in both total national productivity and *per capita* income upto the year 1961-62. But from the year 1962-63, not only has there been no marked increase in national productivity nor in the *per capita* income but actually if you compare the figures of *per capita* income in 1961-62 with *per capita* income in 1965-66, you will find there was some loss. I think, in one of the economic surveys, it was indicated that during the Third Plan, there was a loss of something like Rs. 400 crores in the sector of organised industry and a loss of something like 700 crores in the sector of agriculture.

Now, I take the question of political unsettlement first. There is a general growth of lawlessness and disorder throughout the country and, under one name or another, there are attacks on the life of the nation itself. There have been riots and disturbances in the past also. But never before has there been this kind of systematic and organised attack on the life of the nation in the name sometimes of religion, sometimes of language and sometimes of territory. All these portend ill for thef uture of the country unless they are controlled in time. I would sugegst that a good deal of this unrest in different forms is ultimately a question of the maintenance of law and order, the question of guaranteeing security of life and property to every single citizen. I am convinced that wherever a Government is determined this kind of riots and disturbances, even if they occur sporadically, cannot continue for long. Before there is any riot on a large-scale, there is a period of simmering and if, during the period of simmering adequate steps are taken by the local administration, they can control the situation. Even if there is an outburst, if immediately strong action is taken, we find control of the situation and there is no repetition of that kind of incidents.

I would give only two examples from within our own knowledge of recent history. The hon. Finance Minister himself, when he was the Home Minister of Bombay, took certain measures which had the effect of effectively putting down communal rioting for a number of years. Similarly, I know that the late Mr. Sri Krishna Sinha who was the Chief Minister of Bihar was so shocked and grieved by the riots of 1947 in that State that he made a vow that during his regime, there shall be no repetition of such riots. I have heard from very high officials of the Bihar Government, some of whom are occupying very high positions in the Government of India today, that Mr. Sri Krishna Sinha told all the District officers concerned that he did not want any excuse, he did not want any apology,

he did not want any explanation,—all that he wanted was to be assured that there will be no riot of that type. During the period he was alive, hardly a single riot disfigured the life of Bihar. What was done in Bombay during the time of my hon. friend, the Finance Minister, what was done in Bihar during the time of the late Mr. Sri Krishna Sinha, can surely be done today. For that, there are many specific things which can be discussed in detail. But of one thing I am certain that, unless the Government takes much firmer action than they have done in the past, if we have incidents like those which happened in Meerut or at Ranchi or at Gauhati or at Karimganj or in other parts of the country on one pretext or the other, unless the Government takes measures which make the repetition of incidents like this impossible, the Government will have failed in its duty. The first claim of any citizen on the State is of security of life, property and honour and a State which cannot fulfil these demands, people will start questioning its action in every field and, I think, this is a matter of which the most serious notice must be taken and the Government must take action to see that there is no repetition of incidents of this type in any part of the country.

If officers feel that their own personal career is linked up with the maintenance of law and order in their area, there will be immediately a salutary change in their entire attitude. The British, through a very small number of British officers, with a judicious mixture of reward and punishment, were able to maintain law and order in a way from which we also can learn certain lessons. I hope that the Government will, even now, awake to the danger which is threatening the very life of the nation. If this position continues, a stage will be created in the country where every individual, whether it be 'X' or 'Y' or 'Z' or whether it be this 'Dal' or that 'Dal', whether it be this organisation or that organisation whether it be this party or that party, whether it be a follower of this religion or that religion, whether it be this community or that community, each man will take the law in his own hands. And if everybody or every group takes the law into its own hands and becomes simultaneously the accusor, the complainant, the judge and the executioner, law and order in this country will break down and that will be the greatest disservice which any government could render to its people.

There is also the spectacle of youth on the rampage. Everywhere we find that the young people are rebellious and they are partly responsible for the kind of situation which has been obtaining in different parts of the country. In many cases, this kind of pogrom which takes place may be inspired by certain politicians or other scheming persons from behind, but very often the young people who have idealism—and their idealism has been misdirected and misguided—go into the pogroms largely out of a sense of frustration. That is why I would suggest that these two aspects of the problem, the political danger of disintegration on the one hand and economic stagnation on the other are closely linked with each other. Wherever you can give to the young people prospects for a bright future, wherever they have an opportunity of creative service to the nation and to humanity, they will never indulge in activities of this kind. Therefore, in order to cure even the political situation, certain economic measures have to be taken. That is where again the budget and the Finance Minister becomes so important.

In creating this situation of greater hope and economic expectancy in this country, several measures are necessary of which, I should say, the very first is increasing food production. This, of course, is a truism and yet, unfortunately, sometimes we forget even truisms. In the past we have not always paid that attention to agriculture which it deserves and demands. Almost the whole of our economy is dependent on agriculture, whether it be in the matter of food production, whether it be in the matter of production of industrial raw material. From every point of view, the comparative neglect of agriculture has imposed a heavy burden on the country which we are now trying to redeem. I admit, and I would like to say so openly that the steps which the Government have taken in this respect in the last two or three years are in the right direction, but we have to go much further, and I think,

[Shri Humayun Kabir]

we have not attacked the question from one of its most important aspects and that is land reform.

In this country we want to increase the production per unit of land. It is not so necessary to increase production per unit of capital or per unit of labour. In fact, in our country, if we concentrate on saving labour and capital in land, we will be making a gross mistake. There is sometimes talk—and the Government itself is guilty of it at times—of large mechanized farms, of State farms, of compulsory co-operatives, but that is not the way in which redemption lies. As one hon. friend pointed out, frankly capitalist countries like Japan and Taiwan have imposed ceilings on the farm; 10 acres are the ceiling, as far as I can recollect, in Japan and 7 acres in Taiwan. Yet, the production per acre of land is among the highest in these two countries. In fact, comparative figures show that the highest production per acre is not in the USA or in the USSR or in Australia or Canada, which have vast farm lands and where each unit of production is perhaps 1,000 acres or 5,000 acres or even 10,000 acres, but the highest production per acre is in small countries like the Netherlands, Denmark, Belgium, Italy, Western Germany, Japan and Taiwan. All this has been achieved by a judicious use of human labour. That is a point which we have to remember. If through judicious land reform and by transfer of the ownership to the peasant we can build up a system of peasant proprietorship here, not only will there be an immediate increase in the production of food but it will also strengthen the basis of democracy in this country. These yeomen as they may be called will serve as one of the surest bulwarks against every kind of subversive activity.

16 HRS.

Now, I go on to the question of prices. It is true that in recent years the agriculturist has had a comparatively higher price than he had enjoyed in the past. In the past, the agriculturist has always borne the entire burden of the Indian economy. During the last seven or eight years, to a certain extent the prices have gone up and he is somewhat better off. There is, therefore, sometimes, especially from urban areas, an insistent demand for lowering the prices of foodgrains and cereals. I would submit that while the prices of foodgrains must be controlled and maintained, they must also be stabilised. Any attempt to depress unduly the prices of foodgrains will have a most harmful effect on the economy. What the agriculturist wants is a fair price. He is prepared to sell his grains and cereals at a reasonable price provided he can get the essentials of his requirements also at reasonable prices. Those essential demands of the agriculturist are, firstly pulses and cereals, then edible oil sugar and cloth and spices and salt and fuel...

SHRI RANDHIR SINGH : Iron and cement also.

SHRI HUMAYUN KABIR : These are the basic demands Iron and cement are also necessary but they are not essential to his very survival as these six other items are. If these things can be assured to him at a reasonable price, he would also be prepared to part with his grains at a ressonable price. I think these can be assured to him at a reasonable price through the co-operatives.

Here, I would suggest to the Finance Minister that he must utilise the co-operative movement in the country on a much larger scale than has been done in order to assure to the agriculturist that these essential needs are supplied at a reasonable price. I have seen some of the work done in the co-operative movement in Bengal which is not too progressive so far as the cooperative movement goes. And yet in spite of the many drawbacks of the co-operative movement in Bengal, the co-operative societies in Bengal have been able to supply edible oil, for instance, at about Rs. 2.50 to Rs. 3 per Kg. when the market price was something like Rs. 4.50 or Rs. 5. They have been able to supply cloth also at reasonable prices. I believe about 10 per cent of the production is reserved for co-operatives. If that 10 per cent could be increased to about 20 per cent and this additional supply of these article reached to the rural areas, to the peasants and the cultiva-

tors, then we could also demand that the prices of foodgrains shall be kept stable. It is obvious that unless we can keep the price of foodgrains stable, there can be no question of price control in the country and the spiral will continuously go on rising.

I would also suggest in this connection a curb on expenditure. Today the prices are high very often because there is too much money flowing about. If there were a curb on expenditure then there would be an immediate control on prices. I know that the Finance Minister has considered an expenditure tax. That would perhaps, be a move in the right direction, but I think he should have a much more rigorous control on infrutuous expenditure of every type. I have mentioned in this House before also that there are certain types of ostentatious expenditure which should surely be curbed. We have, for instance, marriages in this country where sometimes literally tens of thousands of rupees are burnt in lights and in illumination. Very often I also know that the poor parents who undergo this expenditure do not do so very happily but because it is the custom and because it is the fashion and they do not want to be regarded as more miserly or less affectionate to their children than other parents, they indulge in a competition on such expenditure. If some kind of a curb were put and it was said that in all these kinds of festivities, this kind of ostentation shall not be permitted and shall be taxed most heavily...

SHRI RANDHIR SINGH : A very good proposal.

SHRI HUMAYUN KABIR :...then it would be a good thing. We may allow up to a hundred or 200 or 300 guests, but if one wants to give a feast where a thousand people are fed or where ten thousand lights are lit, then if some tax is put on such expenditure, I think it will not only have a salutary effect on the general expenditure but it will also have a salutary effect on general social customs.

In this connection, there is also the question of black money. Unless we can bring this out somehow or other, we cannot control this kind of ostentatious expenditure. One of the simplest ways of doing it—it is not very simple because a monetary measure cannot be simple—is to issue a new set of currency notes. I am not suggesting that there should be any demonetisation in the general sense by which you repudiate your obligations. But if it is provided that the present set of bank notes are withdrawn and a new set are issued and anyone can change them through a bank, only through a bank, immediately a good deal of this black money will have to come out into the open, especially if no questions are asked. If questions are asked, there will be all kinds of surreptious moves to get round. It should be provided that anybody can present the notes at a bank and get a new set; only there will be an entry. Also if the Finance Minister would take courage in his hands and make it unlawful to make any payment over Rs. 250 or Rs. 500 except through cheques—through banks—that will go a very long way in drawing out this black money and in controlling excessive expenditure that very often takes place.

I would make another suggestion for his consideration. In many of the East European countries where they follow the socialist pattern, most of the articles are expensive, but a few of the essential things are given at almost rock bottom prices. I found in Bucharest that transport, housing, bread and milk are given at prices which made one rub one's eyes in wonder. They are cheaper than in our own country. Similarly, as regards clothing, I found that every person was given a coupon by which he could buy one suit annually at a price extremely reasonable, perhaps Rs. 150 for a warm woollen suit in Bucharest. But anyone who wanted a second suit had to go to the shop and pay something like Rs. 700 —800. Everybody was given one pair of shoes per year through a coupon costing Rs. 25—30. If he wanted the luxury of a second pair, he had to pay Rs. 200 or more.

I was discussing at that time whether we could send more consumer goods in order to ensure a greater supply to the people of that city. Some of the Ministers said, 'We may import from India, but that does not mean that the prices

[Shri Humayun Kabir]

will come down. We shall assure to the people basic essentials at this kind of reasonable price, but anyone who wants something over the minimum will have to pay through the nose'.

I would ask the Finance Minister to consider whether we cannot have something on these lines here. We have already rationing on a large scale of cereals. Through their ration cards, people have to get supplies. If in a similar way every citizen was given a basic minimum at a reasonable price and for other things the law of supply and demand was allowed to operate, I think excessive expenditure could be curbed and we would have more resources for development.

If we are to break this present economic stagnation, we have to think in terms of control of prices, in terms of supply of foodgrains and other basic essentials to every citizen. But even more important is the question of increasing employment opportunities. This is where I find the Budget, on the whole, most disappointing. My hon. friend, Shri Salve, who preceded me paid his tribute to Bokaro, but in the end the conclusion he drew proved that Bokaro is not necessary at the moment. Certainly not one Bokaro but ten will be needed in India over the next 15-20 years, but today when we cannot consume all the steel we produce, when we cannot export all the steel that is in excess, when existing steel plants are not working to full capacity, what justification is there for going in for a white elephant of this type? Merely in order to give us the satisfaction that our production of steel goes up from 6 million tons to 7.8 million or 8 million tonnes.

Again, my hon. friend mentioned that the investment on Bokaro was very high, but he did not mention that an equal amount of 1.5 million tonnes of steel could be obtained from our existing plants by enlarging and improving production in Rourkela, Bhilai and Durgapur at a cost of something like Rs. 500 crores; instead of that, we are going in for Rs. 1,100 crores for producing the same amount of steel which also we shall not need immediately. If these Rs. 500 crores which we could have saved, or the Rs. 1,100 crores which is going into Bokaro during the current year, were utilised for small-scale, medium and cottage industries, we would provide employment to a far larger number. I think the hon. Finance Minister cannot deny that Rs. 1,000 crores investment in Bokaro will give employment to only 10,000 persons. In other words, for every crore invested, the employment is only of ten people, but if it is invested in medium-scale industries it will be something like 500 people, and if we go to cottage and small-scale industries, it would be almost double. Therefore, with the same amount we would create employment opportunities for a vast number of young men and women, and this would not only give them employment, and create more wealth in the country, but simultaneously it would lift the mist of depression, the mist of frustration, the threat of disintegration from which society is suffering today.

There are so many tasks which remain to be done. Our people are without education. If the programme of education were taken up seriously, there can be no question of educated unemployment in this country. Even today, the total number of people engaged in education is not 2 million at all levels, and we need for primary education alone something like 3 million teachers if this country is to provide education for every child of schoolgoing age. We require also a fairly large number, I think the number is between 400,000 and half a million, at the secondary stage.

We must, in this country, also do something to control the growth of population, and for that we require another 200,000 people at least to go throughout the country to carry on propaganda. If through these two programmes, they are ultimately the same programme, educating or enlightening the people is taken up seriously, the unemployment problem of the educated can be solved overnight.

So far as the uneducated are concerned, again there are crying needs in the country. Our villagers are very often

cut off from the major centres of trade and industry because there is a gap of a mile, two miles, three miles or four miles of road between a village and a metalled highway. If a vast programme of rural road construction was taken up, not only do we provide employment to people, but simultaneously we build that infrastructure on which the economy of the country can go ahead.

Similarly, about rural housing. We have about half a lakh villages in this country, and I think it would be no exaggeration to say that 90 per cent of the houses in these villages are really not fit for human bahitation. Human beings are living there, but we know that even only 130 years ago in England itself people were living in hovels, where men, poultry and hogs lived in the same room, where probably eight to ten people lived in a tenament of 10 feet square. That was the condition and through their efforts they have completely changed the situation. In this country also, through a programme of rural housing we can not only change the face of the country, but create an atmospher of hope. Unless we take these industries to the countryside, unless we provide employment to the vast mass of our people in the rural areas, unless there is a massive programme of rural industrialisation, not by large scale industry, not through capital-intensive industry but through small-scale and cottage industry, we cannot change the economy of this country. If we do that, not only will there be an immediate removal of economic stagnation in the country, simultaneously there will be a new atmosphere of hope.

Tagore says in one of his essays on the economic future of India that man can do with the loss of almost everything in life, but he cannot do with the loss of hope. If there is no money and there is hope, the man will work because sometime money come. If he has no health, but hope, he will probably work in a way to restore his health. If he has no food but hope, food will come to him some time, but if he has no hope, then everything is lost. Today vast numbers of young people in our country are facing that hopelessness. I should appeal to the hon. Finance Minister and through him to the Government to create an atmosphere of hope and provide employment to these millions of young men and women. If we can do that, this pall of gloom will be dispelled. Not only will there be economic buoyancy but the political stagnation from which we are suffering, the disintegration that is threatening the country will be things of the past. The bickerings going on in different parts of the country and the petty squabbles which are exaggerated beyond recognition, all these will disappear. We can then build that India for which thousands of our people have suffered and hundreds had given their lives.

श्री हेम राज (कांगड़ा) : सभापति महोदय, जो बजट हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब ने हाउस के सामने 29 फरवरी को पेश किया था मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। और बात बहुत साफ है। जिस समय उन्होंने यह मुहकमा अपने सुपुर्द लिया उस समय देश की जो अर्थव्यवस्था थी वह इतनी अस्तव्यस्त हो चुकी थी कि हर एक आदमी एक मायूसी में नजर आता था। यहां पर दो कहत पड़ चुके थे। दो लड़ाइयों का सामना हम कर चुके थे। वह एक तो लड़ाई पाकिस्तान के साथ थी और एक चाइना के साथ। इन दोनों लड़ाइयों में हमारा जो खर्च हुआ उससे ऐसी हालत पैदा हो गई थी कि मुल्क की अर्थ-व्यवस्था बिलकुल विघटित सी हो गई। ..... (**व्यवधान**) ..... में वह भी आप को बताता हूं।

चूंकि आपने यह प्वाइंट उठा दिया है इसलिए कहता हूं कि, उन नवजवानों को और उन फौजियों को आज पहली मर्त्तबा हमारे वित्त मंत्री जी ने कुछ सहूलियतें दी हैं और उन लोगों को जो कोई यूनियन नहीं बना सकते, जो डिसिप्लिन से बन्धे होते हैं उनकी सुविधाएं बढ़ाई हैं। यह मैं इस वास्ते कहता हूं कि मैं उस इलाके से आता हूं जहां की एक चौथाई पापुलेशन जिले की और जितनी एडल्ट पापुलेशन है उसकी आधी आर्मी में

[श्री हेम राज]

है और यही नहीं बल्कि चाइना का ऐग्रेशन हुआ उस वक्त भी और पाकिस्तान का भी ऐग्रेशन जब हुआ उस में भी सब से ज्यादा जो नवजवान शहीद हुए थे वह जिला कांगड़ा के थे। मैं यह समझता हूं कि उनके लिए पहली मर्त्तबा हमारे वित्त मंत्री ने कुछ कदम उठाए हैं। वह जो कि कोई यूनियन नहीं बना सकते थे, उन की सुनवाई उन्होंने की है। इस के लिए मैं उन को धन्यवाद देता हूं।

इस के पीछे ऐसी हालत पैदा हो चुकी थी कि बिहार में कहत पड़ चुका था। देश के जो बाकी हिस्से हैं चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे और दूसरी जगह हो, वहां पर भी कहत पड़ चुका था। यह ठीक है कि सरकार का उसमें बहुत ज्यादा खर्च हुआ जैसा कि आंकड़े बताते हैं कि इस समय तक हम बाहर से जो अनाज मंगाते हैं उस पर गालिबन 33 सौ करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। तो आज पहली मर्त्तबा एक आशा वह बन्धा रहे हैं हमें कि अब एक ऐसी हालत पैदा हो गई है जिस में कि हम अपने मुल्क में अपना जो प्रोक्ययोरमेंट है उस मे कुछ अपनी एक बुनियाद बना सकेंगे जिससे कि बफर स्टाक बन सकेगा और उस के साथ-साथ हमें यह आशा भी बंधती जा रही है, आज यह कहा जा रहा है कि प्राइसेज बहुत नीचे हैं लेकिन मैं एक अर्ज करना चाहता हूं कि कि जहां तक हमारे हिमाचल प्रदेश का ताल्लुक था जिस वक्त सिंगिल स्टेट जोन बना हमारी हालत यह हो गई कि हमें तो अनाज मिलता था 200 रुपये क्विंटल और हमारे साथ ही पंजाब में 75 रुपये क्विंटल पर अनाज बिकता था। तो आज जरूरत इस बात की हो गई है कि जिस समय आप यह समझते हैं कि आप बफर स्टाक बनाने के काबिल हो गए हैं जिस में आप समझ रहे हैं कि बाहर से भी अगरचे मंगवाना पड़ेगा लेकिन अगर ऐसी हालत हो गई है तो आज यह वक्त आ गया है कि आज आप के जो सिंगिल स्टेट जोन हैं उन को आप बड़ा बनाइए। वह इसलिये उस को बड़ा बनवाना चाहते हैं कि जो पैसा आज मिडिल-मैन के कब्जे में चला जाता है, जो पैसा आज ब्लैक मार्केटियर के कब्जे में चला जाता है, वह हमारे सीधे सादे किसान के पास जाये और मिडिल-मैन जो कि ब्लैक मनी में डील करता है, वह वहां से दूर हो जाये।

इसलिये, सभापति महोदय, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर और हरियाणा के गवर्नर साहब ने जो रिकमेंडेशन की है कि अब चूंकि फसल बहुत अच्छी है, इसलिये ये जो सिंगल स्टेट फूडजोन का सिस्टम है इसको हटा देना चाहिये। सिंगल स्टेट फूड जोन की जगह कम से कम नादर्न जोन तो बन ही जाना चाहिये ताकि किसानों को गल्ले के ठीक दाम मिल सकें।

सभापति महोदय, मैं आज अपने वित्त मंत्री जी को बधाई भी देना चाहता हूं—आपने देहातों के लिये पहली मर्त्तबा कई चीजों पर छूट दी है। खासतौर से तम्बाकू के मामले में पहले उन को काफी तंग किया जाता था, लेकिन अब आपने उन को छुट-कारा दिया है—यह आपने बेहतर काम किया है। इसी तरह से आपने आफिसरों के टी० ए० में कमी की है, लेकिन इस हैड में 1967 में काफी इकानामी नहीं हुई। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि आज भी एड-मिनिस्ट्रेशन के इखराजात में काफी कमी हो सकती थी। आप देख रहे हैं कि हाउस में में जो क्रिटिसिज्म हुआ है, उस में बहुत से मेम्बरों ने इस बात पर जोर डाला है कि इसमें इकनामी पूरी तरह से नहीं हुई है। आप का एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपेन्डिचर अभी भी काफी ज्यादा है। आप जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्ज बना रहे हैं, अगर देहात के गरीबों के लिये आपको काम करना है, तो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्ज बनाने की जरूरत नहीं है, आपको इस तरफ अपनी तवज्जह लगानी चाहिये और यह सारे का सारा रुपया प्रोडक्टिव परपजेज के लिये इस्तेमाल होना चाहिये।

16.23 HRS.

[MR. DEPUTY- SPEAKER *in the Chair*]

एक माननीय सदस्य : मिनिस्टरों की संख्या घटानी चाहिये।

श्री हेम राज : मिनिस्टरों की संख्या—मैं समझता हूं —हम ने फिर भी कम रखी है, जहां जहां नान-कांग्रेस गवर्नमेंट्स बनी हैं, वे इस मामले में हम से एक कदम आगे ही चले गये हैं। हम ने शायद सैन्टर में उनकी तादाद 50 रखी थी और राज्यों की सरकारों में शायद 20 या 30 थी, लेकिन इन नान-कांग्रेस गवर्नमेंट्स ने तो उन की तादाद 60 कर दी है।

एक माननीय सदस्य : आपने की है।

श्री हेम राज : हम ने नहीं की है, नान-कांग्रेस गवर्नमेंट्स ने की है।

हमारे वित्त मंत्री जी के सामने एक तरफ खाई थी और दूसरी तरफ समुद्र था, उन्होंने इस चीज को मद्देनजर रखते हुए एक ऐसा रास्ता चुना है—अगर वह इसमें ज्यादा टैक्सेशन बढ़ाते, तो हमारे गरीब लोगों पर ज्यादा बोझ पड़ता, इस के साथ ही यह भी होता कि जो हमारा इन्डस्ट्रीयल प्रोडक्शन है, जिस में रिसेशन आया हुआ है, जिस में कमी हो रही थी, जिस में लोग इन्वेस्ट करने के लिये तैयार नहीं थे, और हमारी प्रोडक्शन बन्द हो जाती—उन्होंने क्या किया ? उन्होंने इन दोनों के दरमियान का एक ऐसा रास्ता चुना जिस में एक तरफ एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने की कोशिश की है, पहली मर्त्तबा खाद के लिये, माइनर इरिगेशन के लिये ज्यादा पैसा रखा। उन्होंने इस चीज को महसूस किया कि मेजर-इरिगेशन स्कीम्ज से उतना फायदा नहीं पहुंच सकता, जितना माइनर इरिगेशन स्कीम्ज पर खर्च करने से पहुंच सकता है, लिहाजा उन्होंने पहली मर्त्तबा इस तरफ तवज्जह दी। इसके साथ ही साथ आज पहली मर्त्तबा जहां एग्रीकल्चरिस्ट्स के लिये फ्लोर प्राइस रखी गई है, वहां उन को इन्सेन्टिव भी दिया है कि अगर कोई एग्रीकल्चरिस्ट रिसर्च करता है तो उस को भी प्रोत्साहन दिया जायगा।

आज इसी मैयार को देखते हुए हमारे बहुत सारे भाई कहते यह हैं कि उन्होंने जो बजट बनाया है, वह जमींदारों की भलाई के लिये नहीं है। पहले तो वह हमेशा सरमायेदारों का दम भरते थे, लेकिन आज पहली मर्त्तबा उनको यह ख्याल आया कि यह बजट जमींदारों के हक में नहीं है, बल्कि उन्होंने यह सुझाव दे डाला कि सारे का सारा एक ही जोन बना दिया जाय। लेकिन, सभापति महोदय, मैं यह समझता हूं कि आज भी जो जोन्ज सरकार ने बनाये थे, जहां अगर किसी इलाके को नुकसान हुआ, तो एक फायदा भी हुआ। इसके जरिये हर एक स्टेट को अपनी पैदावार को बढ़ाने का मौका मिला, उन्होंने कोशिश की माइनर इरिगेशन को बढ़ाने के लिये, अच्छी खाद मुहिया करने के लिये और इस तरह से अपनी पैदावार को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया। इसी बात को एक इकानामिस्ट ने भी मन्जूर किया है और उस ने अपने 3-2-1968 के एक लेख में लिखा है :—

"The budget proposals, therefore, stand the scrutiny of the objectives which the country needs to achieve as immediate goals which are : to initiate industrial recovery, infuse some life into the investment climate, achieve some better performance in export and higher degree of import substitution while meeting the fiscal needs of the Government. If the proposals fail to invoke sufficient response the failure would be of the community and not that of the Government."

मैं समझता हूं कि आज देश में पहली मर्त्तबा यह खयाल पैदा हुआ है कि हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने जो बजट पेश किया है वह मुल्क की पैदावार को बढ़ाने के लिये—चाहे वह इंडस्ट्रीयल साइड हो या एग्रीकल्चर साइड हो, देश के उद्योग धन्धों को बढ़ाने के लिये बहुत बेहतर साबित होगा।

[श्री हेमराज]

इसके साथ साथ उन्होंने फोर्थ-फाइव ईयर प्लान का भी खयाल रखा है, उन्होंने कोशिश की है कि उस को कम न किया जाय, उस में भी कुछ न कुछ बढ़ोत्तरी की है, पचास करोड़ रुपया एन्वल प्लान में ज्यादा रखा है—इसलिये रखा है कि राज्य सरकारें भी बराबर का हिस्सा दें और और इस तरह से जो हमारे यहां एजूकेटेड—अनएम्पलायमेंट बढ़ रही है, एक तरफ तो हमारे इंजीनियर्स में अनएम्पलायमेंट बढ़ी है, दूसरी तरफ टीचर्स में भी अनएम्पलायमेंट बढ़ने लगी है, पंजाब में टीचर्स का भी एजीटेशन चल रहा है—इस मसले को हल किया जा सके ।

अगर हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब डेफिसिट न रखते, तो उन को टैक्सेज बढ़ाने पड़ते—उस सूरत में जब हमारे अपोजीशन के भाई कहते हैं कि ज्यादा टैक्ससेज नहीं होने चाहियें, लेकिन दूसरी तरफ वह यह भी कहते हैं कि प्राइसेज नहीं बढ़नी चाहिये, —यह कैसे मुमकिन हो सकता है । अगर टैक्सेज ज्यादा बढ़ाये जाते तो कुदरती तौर पर नतीजा यह होता कि हमारी प्राइसेज में इजाफा होता, लेकिन आज उन्होंने कम से कम इजाफा एक्साइज ड्यूटी में किया है ताकि प्राइसेज न बढ़ने पावें ।

इन शब्दों के साथ मैं कुछ सुझाव उन के सामने रखना चाहता हूं । मेरा एक सुझाव तो यह है—यह ठीक है कि जहां आपने बहुत सारे काम किये हैं कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने एक नई चीज की तरफ अपनी तबज्जह दी है, मैं चाहता हूं कि सैन्ट्रल गवर्नमेंट भी उस तरफ तवज्जह दे, इससे हमारे रेवेन्यूज में काफी इजाफा हो सकता है और उसके जरिये से हमारे देहाती इलाकों में और दूसरी जगहों पर जो रुपया बढ़ रहा है, वह मौपअप हो सकता है । खास तौर से हमारे पंजाब और राजस्थान ने अपने यहां लाटरी सिस्टम को जारी किया है । जिससे कि लोगों से रुपया खींचा जा सकता है और उसको डेवेलपमेंट के कामों में इस्तेमाल किया जा सकता है । मैं यह कहना चाहता हूं कि पिछले दिनों से आपकी स्माल सेविंग्ज स्कीम में आहिस्ता-आहिस्ता रुपया कम वसूल हो रहा है । यह एक ऐसा तरीका है, जिससे कि, लोगों के पास जो फालतू रुपया है, वह आपके पास आ सकता है ।

एक बात मैं आपसे और अर्ज करना चाहता हूं कि आजकल देश में करप्शन का बहुत बोल-बाला है और करप्शन को मिटाने के लिए भी बहुत आवाज उठाई जा रही है । आज सेल्स टैक्स का जो तरीका है, मैं समझता हूं उससे करप्शन बढ़ता है । कई दफा यहां पर पहले भी प्रपोजल्स आये हैं कि सेल्स टैक्स के बजाय मामूली यूनीफार्म एक्साइज ड्यूटी लगा दी जाए तो इन्सपेक्टर्स में आज जो करप्शन है, इतना ज्यादा पैसा जो वे खाते हैं और साथ ही साथ दुकानदारों को भी हिसाब-किताब रखना पड़ता है, वह दोनों चीजें बन्द हो जायेंगी । अगर आप ओरिजिनल स्टेज पर ही एक्साइज ड्यूटी ले लेंगे तो उससे बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है ।

एक बात और अर्ज करना चाहता हूं । आपके यहां 25 लाख इनकम टैक्स के असेसीज हैं । उन पर ज्यादा खर्चा करने के बजाय, जैसा कि भूतलिंगम कमेटी ने साढ़े सात हजार की लिमिट रिकमेंड की है, आप अगर 6 हजार की लिमिट भी रख दें तो यह चीज बड़ी मुफीद साबित होगी । इससे आज जो दर्मियानी तबका है जोकि दबा पड़ा है, उसको भी कुछ राहत मिल सकेगी । पहले जब आपने लिमिट रखी थी उस समय आज के मुकाबले चीजों की एक तिहाई प्राइसेज थी । आज चीजों के दाम तीन और चार गुने चढ़ चुके हैं । मिडिल क्लास का ही आज जो तबका है वह गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है, उनको इससे कुछ राहत मिल सकेगी ।

एक अर्ज और करना चाहता हूं । लेबर के मुताल्लिक आपकी ऐसी पालिसी रहे कि उनको ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले ।

लिविंग इंडेक्स की बेसिस पर तो उनकी वेज रही लेकिन कभी भी आपने लेबर पालिसी को इस लिहाज से देखने की कोशिश नहीं की कि वह प्रोडक्शन ओरियन्टेड हो। आज देश में प्रोडक्शन ओरियन्टेड लेबर पालिसी की सबसे बड़ी जरूरत है। इसके न होने से आज जो देश में पब्लिक अन्डरटेकिंग्ज हैं उनमें कम काम हो रहा है। हमारे इन्डस्ट्रीज मिनिस्टर साहब यहां बैठे हैं, उन्होंने किसी मीटिंग में यह बात कही है कि पब्लिक अन्डरटेकिंग्ज में जो आई० सी० एस० आफिसर्स लगे हैं, जिन को कि बिजनेस का कोई तजुर्बा नहीं है, उनको वहां से हटाया जाना चाहिये। उनके बजाय एक पूल बनाना चाहिए—जैसी कि कोशिश भी थी—जो लोग बिजनेस के माहिर हों उनको लिया जाना चाहिये। आज पब्लिक अन्डरटेकिंग्ज में 3,300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 4 करोड़ का मुनाफा मिल रहा है जोकि बहुत ही कम है। लेकिन ऐसा करने से मैं समझता हूं पब्लिक अन्डरटेकिंग्ज की हालत बेहतर हो जायेगी।

इसके साथ-साथ मैं एक चीज और अर्ज करना चाहता हूं। जिस हिमाचल के इलाके से मैं आता हूं, वहां पर चाय होती है। इसी प्रकार यू० पी० में भी है और बिहार में भी है। वहां जो काली चाय होती है उस पर आपकी एक्साइज ड्यूटी बहुत ज्यादा है, 30 पैसे है। जोन नं० 1, ईस्ट नार्दर्न जोन रखा गया है। जो कीमतें ईस्टर्न जोन की हैं, जोकि आसाम और बंगाल की हैं, उनके मुकाबले में यहां पर जो कीमतें हैं, वह 50 परसेन्ट से भी कम वसूल की जाती हैं। इसलिए इसका एक अलग जोन बनाया जाए और एक्साइज ड्यूटी कम की जाय।

जहां तक हमारे हिमाचल प्रदेश का सम्बन्ध है, जिस समय भी हम यहां पर यह सवाल पेश करते हैं कि हिमाचल प्रदेश को फुल स्टेट-हुड का दरजा दिया जाये तो हमारे सवाल पर यही एतराज पेश किया जाता है कि चूंकि हमारा यूनिट जो है वह रेवेन्यु और एक्सपेन्डीचर को बराबर नहीं कर सकता इसलिए फुल स्टेट-हुड का दरजा नहीं दिया जा सकता। मेरी अर्ज यह है कि अभी तो आपको 100 परसेन्ट ग्रांट देनी पड़ती है, जब पूरे राज्य का दर्जा दे देंगे तो फिर हमें अगर जरूरत पड़ेगी तो ज्यादा से ज्यादा टैक्सेशन से भी वसूल कर सकेंगे और अपने अखराजात को पूरा कर सकेंगे। इसके लिये हमारी हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने कुछ प्रपोजल्स भी भेज रखे हैं कि हम परचेज और प्रोडक्शन टैक्स लगाना चाहते हैं क्योंकि हमारे पास दो किस्म की चीजें कैश क्राप्स की शक्ल में हैं। फल और आलू बगैरह पर अगर हम प्रोडक्शन और परचेज टैक्स लगा सकें तो हमें 6-7 करोड़ की आमदनी उससे हो सकती है।

एक चीज में आपसे और अर्ज करना चाहता हूं। जो वाटर पावर है, पंजाब को जो पावर जाती है, राजस्थान को जो पावर जाती है और हरियाणा को जो पावर जाती है, वह वाटर पावर हिमाचल प्रदेश से आती है। उसका फायदा हमें कुछ नहीं होता है। हम तो उजड़ जाते हैं। उसका अगर फायदा होता है तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को होता है। पंजाब, हरियाणा राजस्थान बैटरमेंट लेवी लेते हैं। उनकी बेटरमेंट लेवी से हमको हिस्सा दिलवाया जाये क्योंकि जो पानी हमने दिया है उससे फायदा उन्हें पहुंचा है। इसके जरिए भी हमारा रेवेन्यु पूरा हो सकता है और आज हिमाचल प्रदेश का केन्द्रीय सरकार पर जो इतना ज्यादा बोझ पड़ रहा है वह भी कम हो जायेगा। इन शब्दों के साथ मेरी यह मांग है कि हिमाचल प्रदेश को फौरी तौर पर फुल स्टेट-हुड का दरजा दिया जाए। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बजट यहां पर पेश किया है, इन शब्दों के साथ मैं उसका समर्थन करता हूं।

SHRI A. T. SARMA (Bhanjanagar): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I thank the Finance Minister as he has presented an excellent Budget. I call it excellent because provisions have been made in all the aspects of it and that, just like the Orissa Budget, it is not repeated like that.

The hon. Member Mr. Masani, has made a pride that his Party could produce a so-called surplus Budget in the Orissa State. But that is not a Budget at all. The thing is this. I would like to tell a few things here. It has shown that an amount of Rs. 12 lakhs would be surplus. But in the Budget a provision has been made to raise Rs. 4½ crores and by providing for Rs. 4½ crores by way of loan, they have shown a surplus amount of Rs. 12 lakhs. This is one thing.

Another thing is that the figures on the receipts side have been so exaggerated that there is no truth, no actuals, nothing else. I would like to narrate three or four items of that nature. One is that about Rs. 2 crores have been provided for the collection of arrears. Generally, every year, we anticipate receipts and we collect some arrears. What we anticipate in receipts, there may be some receipts or some arrears. So, the figure of arrears always stand constant. That from the arrears they will collect Rs. 2 crores is impossible. So, Rs. 2 crores have been shown as the collection of arrears.

Then, a very ridiculous figure that has been provided is of Rs. 50 lakhs from the municipal rent revenue. We do not know what it is. There is no rule, no regulation, nothing else. It is a speculative figure that they have provided.

Again, they have provided Rs. 30 lakhs as profit from the State transport. Generally, it is running on a loss. Not even a pie is being received as profit. But in this Budget, they have shown that Rs. 30 lakhs would accrue as net profit. There are so many absurdities.

It has provided that about Rs. 60 lakhs would come from the collection of bonus on foodgrains which are not possible at all. They have abolished zila parishads; they are going to abolish Girls High Schools and Women's Colleges in the name of co-education. They are going to abolish the Sanskrit Department in my State and they are asking the Matriculates to take Sanskrit in P.U.C. and B.A. courses. This is the nature of the Budget! Mr. Masani is taking pride in that and he has bitterly criticised this excellent Budget here. I do not know what is this. Once there was a king who said that if anybody could give a convincing answer to a certain point, he would give Rs. 1,000. Everybody approached him, but he said, 'No, I am not conviced'. This is the Budget! They want to enhance their revenue by abolishing prohibition. Prohibition was introduced by the Congress Government and it was in operation for the last 20 years. But they have abolished prohibition and they anticipate about Rs. 2 crores out of this. This is the nature of their Budget! It is not a constructive budget, but it is a destructive budget. Mr. Masani may take pride in that, but our Budget is not like that. It is depending on the actuals. For every thing, provision has been made. For planning, about Rs. 50 crores have been provided in addition to the existing provision. For nitrogenous fertilisers, 3½ millions have been provided this year. For agriculture, all sorts of facilities have been granted. Again, for procurement, a reasonable price has been assured to the cultivators. Our budget shows that proper calculation has been made to fix the price so that the cultivator may not lose anything under the procurement system. Yet, Mr. Masani criticised it saying that, by introducing procurement, the cultivator is not given his proper share. I do not know how he says that...

SHRI DATTATRAYA KUNTE (Kolaba) : Is he discussing Mr. Masani or the General Budget ?

SHRI A. T. SARMA : That is also a part of the Budget. When somebody criticises our Budget, then it is our duty to criticise him. I am coming to this Budget point by point. Why should he say that, under the system of procurement, the cultivator will lose his proper share? On the other hand, under the procurement system, the cultivator is

benefited because he is getting his cost of production immediately....

SHRI GADILINGANA GOWD (Kurnool) : What are the rates fixed ?

SHRI A. T. SARMA : Why is he getting annoyed? I am coming to the point, Why should he be in a hurry ?

There is no difference in the price and the cultivator gets the articles produced by him sold immediately. He is satisfied. He is benefited thereby. So, procurement does not deprive the cultivator of his dues but rather assures him of those dues.

Then, my hon. friend Shri M. R. Masani has criticised the provision of Rs. 110 crores for the Bokaro project. I would like to ask my hon. friends whether the Bokaro project is justified or not. Shri M. R. Masani wants that this amount should have been spread over some other projects, but if that were done, we would not be able to save much thereby. But here if this one single project is completed, we shall be benefited by the production of steel from this factory. That is why such a big amount has been provided for this single project, and there is, therefore, justification for this.

Then, Shri M. R. Masani had said that the Congress had got only about 40 per cent of the total votes. I would like to ask him whether the Congress Government is popular or not. I would also ask him to analyse the position of his own party. I may point out that in all the States the Congress has emerged as the single largest party. Even in this House, the Congress has the majority. So, I do not know what type of calculation the hon. Member depends upon. I do not understand how he could criticise the Congress and pass such remarks about the Congress. We have seen now how the non-Congress Governments in other States have not been able to succeed at all. I would like to foretell that again the Congress will come back to power in those States within a short period, and the other non-Congress Governments are going to fall.

Coming to the budget, my hon. friend opposite had said that this was not a budget for the janata. I do not understand what he means by the term 'janata'. In this budget everything has been provided for the janata. Implements for agricultural cultivation have been provided for, and to increase food production, all sorts of attempts have been made. So, how could my hon. friend say that nothing has been done for the janata in this budget? Of course, he has freedom of speech in the House and he can say what he wants, but that kind of citicism has no meaning at all. I would submit that this budget is a budget for the janata in every respect. So, merely saying that it is not a budget for the janata would not do.

My hon. friend has pointed out that what the janata needs is food, clothing, education and shelter, and he says that nothing has been done in this behalf in this budget. I would like the House to consider whether what he has said is correct and sound. I do not think that it is correct or sound. As I have pointed out already, attempts have been made to increase ogricultural production and so on.

We should also consider the circumstances under which this budget has been brought forward. The prices had been rising sky-high, and our crops had failed during the last two years, but under the able guidance of our Finance Minister we were able to face the crisis well. Is that not a fact ?

SHRI UMANATH (Pudukkottai) : It is a fact that he prayed to God and there was rain.

SHRI A. T. SARMA : It is a fact that we were able to face the crisis well, and there is no doubt about it.

It is true that we have been dependent on food imports from outside. I personally do not like it and am not very happy about it. We must make attempts to increase our foodgrains production so that we become self-sufficient and do not have to depend on foreign sources. That is my individual opinion. But attempts have been made to achieve that in the budget. Production of nitrogenous fertilisers has been doubled during the year and provision has been made for minor irrigation. These are things which

[Shri A. T. Sarma]

the cultivator wants. What is our deficit in food? Only 7 per cent. If we improve our cultivation system, we can make it up.

For this, I suggest three things. First, there are vast lands lying uncultivated. Even in my State, there are 72 thousand acres which are not under cultivation. Similar is the position in every other State. If we improve these lands and bring them under cultivation, we can get enough production to meet our deficit. So this must be attended to. Secondly, as a member of the Rice Research Committee, I know there are 300 varieties of seeds which require less of water and time but are high-yielding. But these have not been used. If these are utilised, we would get an abundant crop every year. With one variety, Taichung Native, we get three to four times the normal crop. If these seeds are used, then we can considerably increase our production.

Thirdly, the agency system should be discontinued. At present, the cultivator does not get his requirements direct from Government but through agents and sub-agents. Thereby he is losing a lot. That is why it leads to a rise in his cost of production. If we abolish this system and give these things direct to the cultivator...

AN HON. MEMBER : From where ?

SHRI A. T. SARMA : From government stores or co-operative stores, not through agents.

Then I would suggest some new sources of revenue. Our Finance Minister has tried his best to make up the deficit by enhancing taxes and other things. I will suggest some things which are not pleasant. First of all, we should abolish the privy purses. No attempt has been made in this direction. This step was approved by the AICC. It was discussed and the House has given full support to it. But it has not materialised yet. I would draw the Finance Minister's attention to this.

SHRI UMANATH : Why not materialised ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : He is offering his views. He might be allowed to proceed.

SHRI A. T. SARMA : It may be due to oversight. I am reminding him of it.

Coming to the second suggestion, we find in every department there is increase in expenditure. The postal department has increase its expenditure by Rs. 22 crores and in the railways there is a deficit of Rs. 40 crores. They are increasing their expenditure. For this only Gandhism is the remedy. Gandhiji used to say that there should not be any officer drawing more than Rs. 500. We have to adopt social reform of our Government. The Finance Minister has announced the appointment of a Finance Commission, I suggest that the Finance Commission should consider this item also. If we do not touch the existing staff and introduce it only in respect of future recruitment, I think there will be no difficulty at all. The salaries of every one from the President downwards to Grade I officer should be revised thoroughly.

The third suggestion is about retrenchment of officers. Every department wants to increase its staff by adding some members during the year. That tendency should be given up *in toto*. There should not be overstaffing of any department. As Vice-President of the District Board, once we appointed a retrenchment committee, and they suggested something the result of which was that some posts of clerks and peons were abolished. So, here, the retrenchment should not affect the Class III and Class IV employees of the Government. It should effect the Grade I and Grade II officers. Thereby, we will save a lot of money and can utilise it more usefully.

The country is full of mines. I am speaking from the experience of my own State. If these means are worked properly, we can get more money, there is no doubt. Proper action should be taken for that. Also, by developing tourism we can earn a lot of foreign exchange. So, I want the Finance Minister to pay attention to these points and balance the budget next year.

17 HRS.

श्री अमृत नाहाटा (बाड़मेर) : मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे वित्त मंत्री महोदय ने बजट बनाते समय देश की सुरक्षा की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा है। कुछ दिन पहले मैंने अखबारों में पढ़ा था—पता नहीं यह कहां तक सही है—कि कुछ दबाव डाला जा रहा है भारत सरकार पर विदेशों द्वारा कि अगर तुम ने अपनी सुरक्षा पर पैसा अधिक खर्च किया तो हम तुम को यह मदद नहीं देंगे, वह मदद नहीं देंगे। मुझे खुशी है कि वित्त मंत्री जी अगर ऐसा कोई दबाव था तो उस दबाव में नहीं आए और उन्होंने बजट में सुरक्षा के लिए उचित व्यवस्था की है। उन्होंने पिछले साल के बजट के मुकाबले में इस साल के बजट में सुरक्षा पर कुछ पैसे की व्यवस्था की है। मैं आशा करता हूं कि देश की सीमाओं को और अधिक सुरक्षित करने का प्रयास निरन्तर उनकी तरफ से किया जाता रहेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक सीमा क्षेत्र से आता हूं। इसलिए मैं विशेषकर इस बात पर जोर दूंगा कि पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी भारत की सीमा पर जहां पिछले युद्ध के समय में हमारी सुरक्षा सब से कमजोर साबित हुई थी और जहां दुश्मन ने सब से ज्यादा हमारी भूमि पर कब्जा किया था, उस ओर विशेष ध्यान दिया जाए। मिसाल के तौर पर पिछले युद्ध में वहां हारने का जो कारण था उसमें सब से मुख्य कारण यही था कि रेगिस्तानी इलाके में न पानी था, न सड़कें थीं और न रेलवे लाइन थी। अब भारत सरकार ने काफी अच्छे पैमाने पर उस क्षेत्र में सड़कें बनाने की योजना को हाथ म लिया है। लेकिन हम लोग यह महसूस करते हैं कि वह अपर्याप्त है, नाकाफी है। यह भी सही है कि सड़कें बनाने का काम आहिस्ता चल रहा है। हो सकता है कि वहां कुछ कठिनाइयां हों। राजस्थान की सरकार के पास प्रचुर मात्रा में उपकरण न हों। लेकिन मैं फिर भी भारत सरकार से निवेदन करूंगा कि वह स्वयं अगर उन सड़कों को बनाने का उत्तरदायित्व अपने हाथ में लेने की स्थिति में न हो तो कम से कम राजस्थान सरकार को हर तरह से मदद तो दे ताकि जो सड़कें अभी बन रही हैं वे पूरी हो सकें और उसके बाद और नई सड़कें मंजूर करके, वहां पर सड़कों का जाल बिछाया जा सके।

रेलों का जहां तक सम्बन्ध है, अभी पोखरण से जैसलमेर तक एक नई रेल लाइन बनी है जो हमारी सुरक्षा में बहुत मदद करेगी। लेकिन मैं बार-बार कह रहा हूं कि जब तक जैसलमेर से बाड़मेर तक रेलवे लाइन नहीं बनेगी तब तक हमारे यहां सुरक्षा का उचित प्रबन्ध नहीं हो सकेगा। आश्चर्य मुझे यह है कि एक ऐसी रेलवे लाइन बन रही है—चुर्क से कटनी तक रेलवे लाइन बन रही है—जिस पर कि करीब पच्चीस करोड़ रुपया खर्च होगा और जो एक ऐसे इलाके में से जाती है जहां बहुत सी नदियां हैं, पहाड़ हैं लेकिन बीच में कोई गांव ही नहीं है, लेकिन इस रेलवे लाइन की तरफ ध्यान ही नहीं दिया जाता है। कहा यह आता है कि जो यह रेलवे लाइन मंजूर की गई है यह इस वास्ते की गई है कि यहां कोयला निकलने की आशा है। लेकिन यह साबित हो चुका है कि वहां कोयला जो निकलने की उम्मीद भी थी वह बहुत घटिया किस्म का कोयला है। मैं समझता हूं कि यह निश्चित बात है कि पच्चीस करोड़ रुपया खर्च करके इस रेलवे लाइन को सिर्फ इसलिए बनाया जा रहा है कि वहां बिड़ला जी का एक एल्यूमीनियम का कारखाना लग रहा है। उसके लिए पच्चीस करोड़ की रेलवे लाइन बन सकती है लेकिन देश की सुरक्षा के लिए दस करोड़ की रेलवे लाइन बाड़मेर से जैसलमेर तक मंजूर नहीं की जाती है। मैं बहुत जोर से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप इस क्षेत्र की सुरक्षा को मजबूत करना चाहते हैं तो रेल और सड़क और पानी की ओर आप पूरा ध्यान दें, उस क्षेत्र के विकास की ओर पूरा ध्यान दें।

[श्री अमृत नाहारा]

मुझे खुशी है कि बजट में इस बात पर जोर दिया गया है कि हम जल्दी से जल्दी देश को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। यह कहा गया कि सिंचाई की बड़ी-बड़ी योजनायें पहले से हाथ में ली गई हैं उन्हें चालू रखा जायेगा और जल्दी उन्हें पूरा किया जायगा।

17.05 Hrs.

[SHRI C. K. BHATTACHARYYA *in the Chair*]

लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि एक बहुत बड़ी योजना जो पहले से हाथ में ले ली गई है—राजस्थान नहर योजना—वह पता नहीं पूरी होगी भी या नहीं और अगर होगी तो कब होगी। मैं इस ओर आपका विशेष ध्यान दिलाना चाहता हूं इस वास्ते कि यह योजना दूसरे क्षेत्रों में जो योजनायें बनती हैं, उन से भिन्न है। अगर कहीं कोई पच्चीस लाख एकड़ की सिंचाई वाली योजना दूसरे इलाके में देश के बनती है और राजस्थान में अगर पच्चीस लाख एकड़ वाली सिंचाई की योजना बनती है तो इन दोनों में बहुत फर्क है। इस का कारण यह है कि यह जो भूमि है यह सदियों से प्यासी चली आ रही है पानी के लिए तरसती चली आ रही है और देश के दूसरे हिस्सों में जमीन जितना पैदा करती है उसे पांच पुना या सात गुना ज्यादा यह जमीन पैदा करेगी। हमें मुट्ठी भर खाद की भी कई सालों तक जरूरत नहीं होगी। सिर्फ हमें पानी चाहिये। राजस्थान नहर की योजना का हाल यह है कि राजस्थान सरकार वहां से इंजीनियरों को निकाल रही है। वह स्थिति में नहीं है कि कुछ अधिक पैसा इसके लिये दे सके। यह ठीक है कि आपने कुछ ज्यादा पैसा राजस्थान सरकार को दिया है लेकिन यह पैसा राजस्थान की योजना के अन्दर ही दिया गया है। अगर राजस्थान की योजना के अन्दर ही राजस्थान नहर के लिए पैसा दिया जाता है तो राजस्थान सरकार योजना का कोई दूसरा काम नहीं कर सकती है। राजस्थान सरकार की इस वास्ते मांग यह है कि इस योजना को केन्द्र अपने हाथ में ले ले और उसके लिए एक आथोरिटी बना कर उस योजना को पूरा करे। अगर इस योजना को जल्दी ही पूरा कर लिया जाता है तो हिन्दुस्तान की सत्तर लाख एकड़ भूमि को लाभ होगा। यह वह भूमि है जोकि सोना उगलेगी। उस भूमि में सिंचाई की जा सकेगी। यह एक अकेली ऐसी योजना है जो अगर पूरी कर ली जाती है तो हमारे देश की सारी जितनी डिमांड है, खाद्यान्नों की, उसको इस योजना से पूरा किया जा सकता है और अन्न के मामले में हम आत्म निर्भरता प्राप्त कर सकते हैं।

बार बार कहने पर भी दलील यह दी जाती है कि अगर हम इस योजना को अपने हाथ में ले लेंगे तो दूसरे राज्य भी कहेंगे कि इस योजना को केन्द्र अपने हाथ में ले ले, उस योजना को केन्द्र अपने हाथ में ले ले। लेकिन मैं दो बातों के आधार पर यह दावा कर सकता हूं कि यह राजस्थान नहर की योजना राजस्थान के वित्त की योजना नहीं है। वहां तो अभी कोई आदमी भी नहीं रहता है और जो रहते भी हैं, अगर दो इंच बारिश हो जाती है तो वे राजा भोज हैं। वे अपनी चारागाह रखते हैं, पशु चरते हैं वे खेती करना भी नहीं जानते हैं यह राजस्थान के हित की योजना कतई नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि राष्ट्र आत्म निर्भर बने, स्वावलम्बी बने, कृषि के मामले में, अनाज के मामले में और वह विदेशों पर निर्भर न रहे तो आप इस योजना को अपने हाथ में लें और इसको आप पूरा करें। यह एक राष्ट्रीय योजना है। कृषि की दृष्टि से भी इसका बहुत महत्व है और सुरक्षा की दृष्टि से भी इसका बहुत महत्व है। यह ऐसी नहर है जो हमारी सीमा के समानान्तर चलती है। देश की सुरक्षा के लिए भी इस नहर का बनाया जाना नितान्त आवश्यक है। यह राजस्थान और पाकिस्तान की सीमा के समानान्तर चलेगी और पूरे कच्छ के रन तक समानान्तर चलेगी और हमारी सीमा को पूरी

तरह से सुरक्षित कर देगी । सीमा के तीस मील आगे तक नहर एक ऐसी पूरी दूरी तक होगी जिस से दुश्मन कभी आगे नहीं बढ़ सकेगा । इसके साथ साथ वह इलाका सरसब्ज होगा, लोग बसेंगे, खेती करेंगे । हमने देखा कि पिछले युद्ध में पंजाब में एक एक इंच जमीन के लिए लोग लड़े थे । इसका कारण यह था कि वह सरसब्ज और विकसित इलाका था । हमारे इस क्षेत्र की कोई सुरक्षा करने वाला नहीं था, कोई इंसान नहीं था । जिधर दुश्मन ने चाहा वह घुस गया और रेत के टीलों पर खड़ा हो कर आगे जहां तक उसकी नजर गई उसने कल्पना कर ली कि इतना क्षेत्र हमारे कब्जे में है । नहर खुद भी शारीरिक रूप से, फिजिकली, हमारी रक्षा करेगी और नहर की वजह से जो विकास होगा वह हमारी इस सीमा की सुरक्षा में योगदान देगा । इसलिए भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सुरक्षा के दृष्टि-कोण से तथा देश को अन्न के मामले में स्वावलम्बी बनाने के दृष्टिकोण से भी, तथा इस क्षेत्र के विकास के दृष्टिकोण से भी राजस्थान नहर एक राष्ट्री योजना की कोटि में अती है और उसे भारत सरकार अपने हाथ में ले कर उसको पूरा करे ।

जहां तक नर्बदा नहर का प्रश्न है, राजस्थान और गुजरात दोनों कह रहे हैं मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से कि उसका पानी राजस्थान को दिया जाए । सिर्फ प्रश्न इतना है ....

श्री यशवन्त सिंह कुशवाह (भिंड) : यह सारा मध्य प्रदेश के कैचमेंट एरिया का पानी है । क्यों मध्य प्रदेश राजस्थान को देगा ।

श्री अमृत नाहाटा : मुश्किल यह है कि लोग समझते हैं कि राजस्थान हिन्दुस्तान में नहीं है । राजस्थान भी हिन्दुस्तान में है, मध्य प्रदेश भी हिन्दुस्तान में है । राजस्थान माही का पानी गुजरात को देता है । नर्बदा कैनाल प्राजैक्ट के जो अध्यक्ष थे, खोसला साहब उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मध्य प्रदेश को तथा महाराष्ट्र को तथा गुजरात को पूरा पानी देने के बाद भी इतना पानी बचता है और वह बचा हुआ पानी राजस्थान को मिलना चाहिये । अगर पानी न बचता तो हमें एतराज नहीं था । केवल ऊंचाई अगर ज्यादा कर दी जाए तो राजस्थान की लाखों एकड़ भमि में पानी दिया जा सकता है । इसलिए मैं निवेदन करूंगा खास कर चह्वाण साहब से कि वह इस प्रश्न को सुलझाने के लिए अगवानी करें और राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के प्रतिनिधियों को बिठा कर इसका फैसला करे ताकि नर्बदा का पानी राजस्थान की प्यासी धरती को भी दिया जा सके ।

एक विशेष प्रश्न की ओर मैं आपका अब ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । जबलपुर में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तो हम लोगों ने एक मांग की थी । कांग्रेस का जो दस सूत्री प्रस्ताव था उस में एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र यह था कि देश की जनता की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा किया जाए । उस वक्त हमारी प्रधान मन्त्री महोदया ने एक घोषणा की थी और कहा था कि यह सब से महत्वपूर्ण चीज है और जिन्दगी की आवश्यकतायें तो और भी बहुत हैं लेकिन पीने के पानी की समस्या भी एक बहुत ही गहन समस्या इस देश में है और इसको सुलझाया जाना चाहिये । इस एक समस्या को अगर हल कर दिया जाए तो देश की जनता की बहुत बड़ी आवश्यकता पूरी हो जायेगी । उड़ीसा के कुछ माननीय सदस्यों ने और आन्ध्र के भी कुछ माननीय सदस्यों ने इसका जिक्र किया है । राजस्थान की ओर से मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि राजस्थान के लाखों लोग ऐसे हैं जिन के परिवारों के दो-दो सदस्य चौबीसों घंटे सिर्फ पीने का पानी लाने में लगे रहते हैं । दस दस और चौदह चौदह मील से वे पानी लाते हैं । अगर आप उनके घर चले जायें तो आपको कुछ खारा पानी और कुछ मीठा पानी मिला कर देंगे । बिल्कुल मीठा पानी देने की स्थिति में वे नहीं

[श्री अमृत नाहाटा]

हैं। जहां लोग पीने के पानी के लिए तरसते हैं, वहां खाना, शिक्षा और चिकित्सा आदि तो उन के लिए स्वप्न हैं। मैं वित्त मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह राजस्थान के ग्रामीणों को पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान सरकार को अधिकतर पैसा दें और यह ईयर-मार्क कर के दें कि यह पैसा गांवों के लोगों के लिए पीने के पानी की योजना के लिए है। यह योजना तो बीस साल से बन चुकी है कि राजस्थान के हर एक गांव में मीठा पीने का पानी उपलब्ध किया जाये, चाहे वह नलों से हो, टैंकों से हो और चाहे ट्यूबवैल खोद कर हो। कुछ ट्यूबवैल खोदे गए हैं, लेकिन एक्सप्लोरेटरी ट्यूबवैल आर्गनाइजेशन ने जितने ट्यूबवेल खोदने का वादा किया था, उतने नहीं खोदे गए हैं। संगठन ने बहुत अच्छा काम किया है। वहां पर काम बहुत कठिन है। दो दो हजार फीट की गहराई पर पानी मिलता है। अगर चार ट्यूबवैल खोदे जाते हैं, तो एक में पानी मिलता है। करीब दो ढाई लाख रुपया एक ट्यूबवैल पर खर्च होता है। लेकिन अगर किसी ट्यूबवैल में पानी मिल जाता है, तो वह अमृत के समान होता है और लोगों को पीने के लिए पानी मिल जाता है। यह आवश्यक है कि जितने ट्यूबवैल खोदने का वादा एक्सप्लोरेटरी ट्यूबवैल आर्गनाइजेशन ने किया था, उतने ट्यूबवैल उस क्षेत्र में खोदे जाय। मैं फिर कहूंगा कि राजस्थान सरकार को जनता की पीने के पानी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पूरा पैसा दिया जाय, ताकि वह इस समस्या को हल कर सके।

जब हम राजस्थान नहर, नर्बदा नहर, पीने के पानी और अन्य विकास-कार्यों की बातें करते हैं और दूसरे माननीय सदस्य भी अपने अपने क्षेत्रों के विकास की बात करते हैं, तो उस वक्त हमारे सामने एक समस्या आ जाती है और वह है बेकारी की समस्या। इस वक्त देश में इंजीनियर या तो परी तरह से बेकार हैं और या जैसा काम उन को मिलना चाहिये, वैसा उन को नहीं मिल रहा है—वे कम पैसों में काम कर रहे हैं। इस तरह के पूरे बेकार या अर्द्ध-बेकार इंजीनियर 70,000 हैं। जून में उनकी संख्या एक लाख हो जायेगी। उन को काम देने की समस्या है। यह ऐसी विडम्बना है कि हम अपने देश को विकासशील देश कहते हैं, हम यहां पर निर्माण-कार्य करना चाहते हैं, हम इस देश का विकास करना चाहते हैं, लेकिन जो निर्माण करने वाले हैं, वे बेकार बैठे हैं।

जब ये सारे प्रश्न उठते हैं, तो एक ही समस्या हमारे सामने आती है और वह समस्या है साधनों की। एक तो साधनों को इकट्ठा करने का प्रश्न है। मैं उस पर बाद में कुछ विचार प्रकट करूंगा। लेकिन जो साधन बिल्कुल व्यर्थ हो रहे हैं, उनकी ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं एक मिसाल की तरफ तत्काल वित्त मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं। क्योंकि वह बहुत महत्वपूर्ण है।

बर्ड एंड कम्पनी पर बहुत से अपराधों की वजह से 1,65 लाख रुपये का जुर्माना किया गया। उस के बाद पता नहीं क्यों अचानक वह जुर्माना 1,65 लाख रूपय से कम करके सिर्फ 65 लाख कर दिया गया। कम्पनी ने उसके खिलाफ भी मुकदमा किया। अदालत ने भारत सरकार से कहा कि अगर वह चाहे, तो वह कम्पनी को यह नोटिस दे दे कि यह जुर्माना और क्यों न बढ़ा दिया जाये। अदालत ने उस के लिए एक वक्त की सीमा तय की। 13 तारीख को वह सीमा खत्म हो रही है। अगर उस से पहले पहले भारत सरकार ने बर्ड एंड कम्पनी को यह नोटिस नहीं दिया कि उसका जुर्माना क्यों न बढ़ा दिया जाये, तो चाहे अदालत ने यह भी फैसला कर दिया कि जुर्माना कम है, फिर भी भारत सरकार वह जुर्माना बढ़ा नहीं सकेगी। चूंकि यह एक तात्कालिक महत्व की बात है, इसलिए मैं वित्त मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वह उस कम्पनी को नोटिस दे

दें कि उसका जुर्माना क्यों न बढ़ा दिया जाये ।

जहां तक फैमिली प्लानिंग का सम्बन्ध है, मैं चुनौती और दावे के साथ कहना चाहता हूं कि फैमिली प्लानिंग के नाम पर हर रोज लाखों रुपया बिल्कुल बर्बाद हो रहा है । इस लूप में बहुत से लूपहोल हैं । मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि केवल कागज पर लूप लगते हैं, असल में नहीं लगते हैं । तेरह रुपये एक लूप पर खर्च होते हैं । वे तेरह रुपये लूप लगाने वाली डाक्टरनी, नर्स और फर्राश मिल कर खा जाते हैं और झूठे दस्तखत बना कर एन्ट्री कर देते हैं । वास्तव में लूप लग नहीं रहे हैं । कागज पर लूप लग जायेंगे, यहां पर आंकड़े आयेंगे कि इतने लूप लगाए, यहां पर हिसाब लगाया जायेगा कि आबादी इतनी कम हो जायेगी और उसके अनुसार योजना बनाई जायेगी, लेकिन वह आबादी कम होने वाली नहीं है ।

एक माननीय सदस्य : माननीय सदस्य एथारिटी हैं ।

श्री अमृत नाहाटा : मैं एथारिटी हूं, क्योंकि मैं रेड क्रास की तरफ से, जिस की एक्सीक्यूटिव का मैं मैम्बर हूं, जोधपुर में तीन फैमिली प्लानिंग क्लिनिक्स चलाता हूं । यद्यपि हमारे कार्यकर्ता सजग रहते हैं, लेकिन फिर भी ऐसी बातें हुई, जिन को हम ने बन्द किया । लेकिन सारे हिन्दुस्तान में सरकारी अस्पतालों में यही हो रहा है और लाखों रुपये बर्बाद हो रहे हैं । फैमिली प्लानिंग का कार्य किया जाना चाहिये, लेकिन तेरह-तेरह या पच्चीस यच्चोस रुपये दे कर जो काम हो रहा है, उस में सारा रुपया बर्बाद हो रहा है और लाभ कुछ भी नहीं हो रहा है ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अब समाप्त करें ।

श्री अमृत नाहाटा : मैं तो अभी सिर्फ सात मिनट बोला हूं ।

सभापति महोदय : नहीं, सात मिनट का डबल ।

श्री अमृत नाहाटा : यह देखना चाहिये कि फैमिली प्लानिंग के नाम पर यह पैसा बर्बाद न हो ।

फारेन एक्सचेंज का जबंदस्त अपव्यय और तबाही हो रही है । मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं । जब देश भूखों मर रहा था, तो हम बाहर से लक्सरी आर्टिकल्ज मंगा रहे थे । आज लक्सरी आर्टिकल्ज मंगाने पर जो करोड़ों रुपये खर्च हो रहे हैं, उस को बन्द करना चाहिए और फारेन एक्सचेंज को सेव करना चाहिये ।

इस समय इनकम टैक्स के एरियर्ज 541 करोड़ रुपये के हैं । उन की वसूली के लिए सख्ती से कदम उठाने चाहियें । जब हम यह बात करते हैं, तो कहा जाता है कि तरीका बताओ । अगर उनके पास तरीका नहीं है, तो वे क्यों वहां पर बैठे हैं । क्या वे इनकम टैक्स के एरियर्ज भी वसूल नहीं कर सकते हैं ?

माननीय सदस्य, श्री हुमायून् कबिर, ने ब्लैक मनी को निकालने के लिए डीमानिटाइजेशन का सुझाव दिया है । वह सही सुझाव है और उस पर अमल करना चाहिये । साधन जुटाने के तरीके बहुत हैं, जो कि बार-बार बताए गए हैं । वे हमारी पार्टी के चुनाव घोषणापत्र में हैं और हमारे प्रस्तावों में हैं । क्यों नहीं हम बैंकों और विदेश व्यापार का राष्ट्रीयकरण करते ? विदेश व्यापार के राष्ट्रीयकरण से न सिर्फ 200 करोड़ रुपये हर साल की आमदनी होगी, बल्कि अंडर-इनवायसिंग और ओवर इनवायसिंग के द्वारा जो करोड़ों रुपये अनधिकृत रूप से विदेशों के बैंकों में जमा होते हैं, वे भी बचेंगे । चाय-बागान और कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं किया जाता है ? आज कोयला-खानें कोयले का भाव बढ़ाने के लिए सरकार पर दबाव डाल रही हैं, जिस से रेलवेज का घाटा और भी बढ़

[श्री अमृत नहाटा]

जायेगा, लेकिन हमारी सरकार को उन के दबाव में आना पड़ता है।

क्यों नहीं हम अपने देश में कान्सी पिकुअस कनजम्पशन को, जिस की ओर माननीय सदस्य ने ध्यान आकर्षित किया है, खत्म कर सकते ? हम शहरी आमदनी और जायदाद पर सीमाबन्दी, हदबन्दी या सीलिंग क्यों नहीं लगा सकते ।

अगर इस प्रकार साधनों को जुटाया जाये, तो फिर हमें 290 करोड़ रुपये का घाटे का बजट बनाने की जरूरत नहीं होगी । यह घाटे की अर्थ-व्यवस्था देश के सामने प्रस्तुत संकट से निकलने का रास्ता नहीं है, बल्कि इससे संकट के और गहरा होने का खतरा है। इस संकट का कारण यह है कि इस देश में विकास से जो दौलत ज्यादा बढ़ी है, उस का वितरण ठीक नहीं हुआ है, वह दौलत कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में पहुंच गई है। घाटे का बजट हमारी अर्थ-व्यवस्था की इस विकृति का हल नहीं है, बल्कि इस से विकृति और बढ़ेगी, अमीर और गरीब के बीच की खाई और बढ़ेगी और कीमतें और ज्यादा बढ़ेगी । आज थोड़े दिनों के लिए कीमतें घटे गई हैं किसानों को लूटने के लिए और उनको धोखा देने के लिए। यह एक क्षणिक चीज है। इसके बाद जब घाटे के बजट का अर्थ-व्यवस्था पर असर पड़ेगा, तो कीमतें और बढ़ेंगी ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अब समाप्त करें ।

श्री अमृत नाहाटा : में एक मिनट में समाप्त करता हूं ।

आज जो रिसेशन की बात की जा रही है, वह मुख्यतः पब्लिक सेक्टर में हैं। आज कहा जाता है कि पब्लिक सेक्टर ठीक नहीं चल रहा है। वह ठीक कैसे चलेगा, जब सरकार ने उसका नेशनलाइजेशन किया ही नहीं, केवल ब्यूरोक्रेटाइजेशन किया है ? क्या भगत राम पब्लिक सेक्टर में विश्वास करते हैं, जिनको इंडियन एयरलाइन्ज कारपोरेशन का अध्यक्ष बना दिया गया है । क्या हमारे बड़े बड़े आई० सी० एस० आफिसर पब्लिक सेक्टर में विश्वास करते हैं, जो रिटायर होने के बाद सेठों के यहां नौकरी करते हैं ? जो मजदूर हमारे पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं, क्या सरकार ने उन को विश्वास में लिया, क्या उन के प्रतिनिधियों को मैनेजमेंट में लिया और क्या उन को यह अहसास दिया कि यह राष्ट्रीय सम्पत्ति है, उस में अधिक उत्पादन करना चाहिए । इस सारे ब्यूरोक्रेटाइजेशन को खत्म करना पडेगा और जो लोग ईमानदारी से पब्लिक सेक्टर में विश्वास करते हैं, उन को रखना होगा । अगर इन सारी संस्थाओं का सही मानों में राष्ट्रीयकरण किया जायेगा, तभी वे ठीक ढंग से काम कर पायेंगी। आज हमारे देश में साधनों की कोई कमी नहीं है, लेकिन उन को जुटाने के लिए सही नीति पर चलना होगा ।

आज हम बहुत बड़े कारखाने प्राइवेट सेक्टर को सौंप रहे हैं । हम कृषि उन को सौंप रहे हैं। हम उनके इंडस्ट्रियल रिवाइवल की बात सोचते हैं, लेकिन हम पब्लिक सेक्टर और अपनी अर्थ-व्यवस्था के रिवाइवल की बात नहीं सोचते हैं। मैं इस को एक डिसटार्टिड और विकृत तरीका मानता हूं । अगर देश का सही मानों में विकास करना है, तो पब्लिक सेक्टर को और स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, विकास-कार्य बहुत बड़े पैमाने पर करना पड़ेगा और उन के लिए आवश्यक साधनों, रीसोर्सिज, को इकट्ठा करना पड़ेगा ।

SHRI RANE (Buldana) : Mr. Chairman, I rise to offer my comments on the budget proposals and also meet some points of criticism, if I find time. I want to suggest some modifications in the budget proposals. I am afraid of your bell, Sir, and so I shall go directly to the budget proposals, because otherwise I may not find time for it at the fag end of my speech. My first suggestions are about the postal rates.

My first suggestion is about the money order commission. The Finance Minister has increased it from 15 p. to 20 p. for very rise and, I find, that is a steep rise in the commission. If we take into consideration the pattern of our industrial labour, I submit, that almost all the industrial labour who are in lakhs comes from the villages and, as their families stary in the villages, they are required to send some help to their family members. The industrial labour will be hit by this increase. So, I submit that at least the money order commission should not be increased, up to M.O. of Rs. 50/-.

Then, about the inland letters, it is 10 p. per inland letter which is proposed to be increased to 15 p. If we look at the Tariff Enquiry Committee's Report, it says that this service gives more than Rs. 8 crores of profit on this service. So, my submission is that it is unjustified to increase the price inland letters. If at all the Finance Minister wants to increase it, he will be justified only to the extent of the cost of production of the inland letter. The Report itself says that its cost between 11 to 12 p. May submission is that if the Finance Minister wants to increase it, he can only increase it to the extent of the cost of 12 p. per inland letter.

About the post-card, the Enquiry Committee Report says that more than Rs. 5 crores are the losses on this service. If we take the whole increase, the increase on inland leters is 50 per cent; on the envelope, it is 33 per cent while the post-card, it is 66 per cent. My submission is that, taking into consideration the production cost of the post-card, etc., the increase should not be the extent of 66 per cent but at the most he can make it 8 p. per post-card, not 10 p. That is a steep rise and, I submit, that the Finance Minister should consider my proposal and, I say, he will not lose anything. You will find that the losses on the postal service are about Rs. 23 crores. He seeks to get, by taxation, about Rs. 26 crores. So, even if he accepts my suggestion, he is not going to lose very much. Therefore, at least the postal taxation can be balanced. Of course, there is a very harsh criticism about it. But I can understand the difficulties of the Finance Minister because he is compelled to raise it. I find from the table of the dearness allowance that in 1964-65, it wa about Rs. 10.40 crores and now this year, it will go perhaps to Rs. 30 crores. So, the increase in dearnes allowance itself is about Rs. 20 crores. I think, we should sympathise with him rather make a harsh criticism on this point.

My second suggestion is that the Bokaro Steel Plant project should be postponed for at least 2 years. That will reduce the deficit financing. I do not agree with Mr. Salve but I agree with Mr. Humayun Kabir and Mr. Masani that it is not absolutely necessary, I submit that it will be unwise on our part to invest so much money specially when we know that these steel plants are not a paying concern for the present. Let us wait for two years and see whether the public sector is going to give us the expected revenue and then we can invest the money. That is my second suggestion. These are the only two suggestions about the budget proposals.....

SHRI BAKAR ALI MIRZA (Secunderabad) : What about tobacco ?

SHRI RANE : I am not interested in tobacco.

AN HON. MEMBER : What about beedi ?

SHRI RANE : I am not interested in beedi or cigarettes or even whisky or brandy. I am glad that there is an increase there.

My third submission is about remunerative prices to the farmers. I am glad that the Finance Minister, in his speech, has said that an assurance of remunerative prices to the farmers should be given. But I am afraid that they will not be able to implement it. There is a long history behind it. For the last 25 years, several committees sat and they advocated remunerative and fair prices to the farmers, but when the time came, nothing was done; even the Agricultural Prices Commission did not give fair and remunerative prices to the farmers. On the other hand, they gave up that principle in favour of fixing *ad hoc* prices. There is no necessity to appoint an Agricultural Prices Commission if prices of agricultural commodities are to be fixed on an *ad hoc* basis.

[Shri Rane]

The Finance Minister or the Minister of Agriculture can ask his officers to sit and ask them to give *ad hoc* prices where is the necessity for employing all these theorists, academicians, professors, etc., and making them sit on the agricultural prices commission and give a report if they are going to fix prices on an *ad hoc* basis ?

Now what is the position today ? The jute prices have gone down below the floor prices. This morning I read in the papers that even today the jute mills association is not willing to purchase jute. The price in 1966 and in the beginning of 1967 was, I think, about Rs. 65 permaund, and now I am told that the price is about Rs. 25 to 30. There is such a steep fall in raw jute prices !

About cotton also, the story is the same. In November, in my district, jarilla cotton was sold at Rs. 250 per quintal. The textile mill-onwers association and the textile mills have decided not to purchase it now. There are no purchasers and the price prevailing today in the market for jarilla cotton is only Rs. 140 to 160. The pice of raw cotton has gone down.

The story is the same with regard to foodgrains also. I have come to the conclusion that the policy of the Government is : the bumper the crop, the lesser the prices for the farmers. Of course, this is a principle in economics; the forces of supply and demand play their role. But when the prices of agricultural commodities go up, then the restrictions come, a heavy hand falls on the farmers and they are not able to get the prices that they deserve to get. My submission is that the Finance Minister should try to implement the assurance that he has given in his speech. This is my submission about remunerative and fair prices to farmers.

Mr. Masani has stated that the Government has neglected agriculture. I do not agree with him here. Of course, there are very few people who can understand the life of agriculturists. From my own experience during the las 50 years, I can say that in agriculture, there are cycles of seasons : one year is a normal or good season; the second is a fair one and the third is a bad one. These cycles play their own part. And yet many of the theorises and professors of agriculture and the people in the Planning Commission have this idea that the agriculturists have become rich or they have become prosperous and their position has improved. They do not take into consideration how risky the life of the agriculturist is. Let me give you an example. In Maharashtra, for instance, in November, the season was very good and a very good harvest was expected. But unseasonal rains in December and aJnuary have destroyed the kharif crop to a large extent. The rabi crops were god in the case of jowar, wheat etc. But the hailstorm in February and the first week of March has destroyed the rabi crop and the rabi crop is almost gone. The kharif crop is also gone. That is how the farmers' fortune is affected. And yet the professors and the theorists and the Planning Commission think that the position of the agriculturist has improved and he has become prosperous and, therefore, they could get money from him. These are wrong ideas which those persons who have no experience of the life of the agriculturist advocate in theory.

But, as I have submitted already, Shri M. R. Masani's criticism that the agriculturist has been neglected by Government is not correct. Government have done many things for the agriculturist. Even the speech of the Finance Minister shows what he is going to do.

Shri Kanwar Lal Gupta and others have said that during the last twenty years nothing has been done and so on. This criticism is unjustified. I shall just quote one small passage from Mr. J. R. D. Tata's speech, which he recently made before the Chamber of Commerce. He says :

> "I for one am not one of those who see nothing good in what Government has done for the country since Independence. If we rightly blame them for our lack of progress in certain spheres, it is only right that we should recognise the part they have played in the considerable progress we have made, some of it quite spectacular by any standard in the fields of health, education, electrification, science, technology and heavy industry."

This is the admission of even a very hard critic like Mr. J. R. D. Tata who does not see eye to eye with the policies of Government. Even he has admitted that much progress has been made, and he says, by any standard. So, the criticism that nothing has happened during these twenty years is absolutely wrong and unjustified.

Sir, I am not an eocnomist. I do not understand very much the principles of economics and so on, but I would like to say one thing about deficit financing. The Finance Minister's expectations last year have been belied. Though he expected that there would not be any deficit in the budget it has come to about Rs. 300 crores. This year he says that it will be about Rs. 219 crores. There has been criticism of the budget on this score. I personally do not like deficit budgets or deficit financing. But as regards the criticism that deficit financing has grown to this proportion because of these happenings or planning and so on, I would only quote one economist Mr. H. V. R. Iengar. He has compared our deficit financing with Bombay Plan of 1944 and he says :

> "Out of a total expenditure of Rs. 10,000 crores as much as Rs. 3400 crores were to be created money. This is actually a higher proportion than was resorted to by the Government of India during the first three Plan priods.".

This is the conclusion of an economist. He had made this observation before the Forum of Free Enterprise in the course of a short memorial lecture. So, I submit that even the critics of Government and those who do not see eye to eye with Government will agree with Mr. H. V. R. Iengar that the deficit financing that was resorted to in the Bombay Plan was very high as compared to what has been resorted to by Government.

I do not want to take more of your time. There are many problems for which I have no time to deal, for example, the unemployment problem, the population problem, the problem of the standard of living of the people and supply of primary necessities to them. But I would conclude with the last and most important submission to the Finance Minister that he should look into the problem of giving remunerative prices to the farmer.

श्री गुलाम मुहम्मद बख्शी (श्रीनगर) : जनाववाला, मैं कोई ज्यादा वक्त ऐवान का नहीं लेना चाहता हूं। हालांकि मैं ने बजट को समझने के सिलसिले में काफी मेहनत की है और कुछ फीगर्स भी वर्क आउट किये हैं लेकिन उन में मैं जाना नहीं चाहता हूं। हालांकि एक चीज जहां तक बजट का ताल्लुक है यह कहे बगैर मैं नहीं रह सकता हूं कि मौजूदा हालात में जो कि मुल्क के हालात हैं और जो मुल्क को मसायल और पेचीदगियां दरपेश हैं उन हालात को सामने रखते हुए इस से बेहतर बजट पेश नहीं किया जा सकता था । इसलिए मैं अपनी तरफ से आनरेबुल फाइनेंस मिनिस्टर को और उन के साथियों को यकीनन मुबारकबाद दूंगा। बजट के डिटेल्स में एप्रोचेज में और बाकी और चीजों में पचासों शिकायतें हो सकती हैं लेकिन उन के बजट से हमें देखना यह है और किसी भी बजट को परखने का और देखने का खास तौर पर यह ढंग होता है कि मुल्क पर उसका असर क्या पड़ता है ? हम ने देखा है कि बजट पेश होने के बाद से आज तक मुल्क में इसका एक अच्छा खासा असर पड़ रहा है। मेरा अपना यह खयाल है कि और जैसा कि अखबारों के ट्रेंडर्स और खास तौर पर वह लोग जोकि मुल्क की एकोनामी को समझते हैं उन से बात चीत वेत करने के बाद यह मालुम पड़ता है कि यह मौजूदा रिसेसशन भी एक स्टैब्लिाइजिंग फैक्टर होगा । चुनांचे मेरा अपना यह खयाल है कि यह ट्रेड, कामर्स और इंडस्ट्रीज जिन मुश्किलात में अपने आप को पाते थे वह भी धीरे धीरे उस में से उसमें से निकलेंगे और धीरे, धीरे निकल कर आगे बढ़ेंगे ।

एक ही चीज मैं स्टडी करता रहा कि इसका असर शेयर्स और स्टाक एक्सचेंज पर क्या पड़ा ? एक मुल्क की एकोनामी की यह बातें आईनादार होती हैं और उन पर मैं देख रहा हूं कि एक अच्छा खासा असर पड़ रहा

[श्री गुलाम मुहम्मद बख्शी]

है और प्राइसैज जो थे वह सिर्फ स्टैब्लिाइज ही नहीं हुए बल्कि कुछ अच्छे भी हुए। इस लिए इस बजट का आम तौर पर असर ठीक पड़ रहा है।

मुल्क को दी, तीन बातों की तरफ खास तवज्जह देने की जरूरत है। एक तो चीज है मुल्क का डिफेंस, मुल्क की सिक्योरिटी उसके लिए लाजिमी हमें खयाल रखना है कि मुल्क के बचाव के लिए और मुल्क की सिक्योरिटी के लिए इंतजाम हो चुनांचे बजट में आप देखेंगे कि उसकी तरफ खास तवज्जह दी गई है। ऐक्सपेंडीचर कुछ थोड़ा बहुत हमारा बढ़ा है लेकिन उस से हमें घबड़ाना नहीं चाहिए क्योंक अगर मुल्क महफूज है तो सब कुछ महफूज है। लेकिन अगर मुल्क महफूज नहीं है, हिन्दुस्तान महफूज नहीं है तो करोड़ों छोड़ कर हजारों करोड़ की भी आमदनी हो उस से कोई फायदा नहीं है। यह भी एक खासा अच्छा स्टेप है जिस के जरिये से मुल्क की हिफाजत की तरफ तवज्जह दी गई है।

यहां पर जितनी बातें हुई, मैं सुनता रहा, बजट स्पीचेज और अप्रांचेज हर एक शख्स की और हर एक तरीके की। लेकिन एक चीज में गुजारिश करूंगा कि हम ने अपने जो आब्जेक्टिव्ज और आइडियल्स देश के सामने रखे हैं, आजादी के वक्त से आज तक, उनकी तरफ ज्यादा से ज्यादा तवज्जह देनी चाहिये, और वह यह कि हम इस देश को धीरे धीरे सोशलिज्म की तरफ ले जायें। अगर हम कहें कि सोशलिज्म एक दिन में आ जाये तो यह नामुमकिन है और मुश्किल है। सोशलिज्म की तरफ कदम उठाने में हम ने तीन जरूरी चीजें कही हैं, यानी यह कि हम जहां पब्लिक सैक्टर को बढ़ावा देंगे वहां कोआपरेटिव सेक्टर को भी साथ चलायेंगे और प्राइवेट सेक्टर को भी साथ-साथ बढ़ावा देंगे। अगर हम सिर्फ पब्लिक सेक्टर पब्लिक सेक्टर ही करते रहे और प्राइवेट सेक्टर को इग्नोर किया तो हमारी एकानमी का बैलेंस टिल्ट हो जायेगा, और जहां तक हमारा खयाल है, हम आगे नहीं बढ़ पायेंगे। इस ना बढ़ने के साथ-साथ आप ने यह देखा होगा कि यहां पर क्रिटिसिज्म होता है कि हम को पब्लिक सेक्टर में नुकसान क्यों हो रहा है। इस के कई कारण हैं, लेकिन मैं इस वक्त उन में नहीं जाऊंगा। अगर फिर कभी मौका मिलेगा तब इस में जाऊंगा, लेकिन अगर तीनों चीजों पर साथ-साथ निगाह नहीं रखेंगे मुल्क के सुधार के लिये और एकानमी के सुधार के लियें, तो हम बड़ी गलती करेंगे। अगर हम को इस में कुछ क्रिटिसिज्म भी बर्दाश्त करना पड़े तो भी हम को मुल्क को धीरे धीरे उस गोल की तरफ आगे ले जाना है जहां उन इन तीनों चीजों की गुंजाइश हो और यह तीनों चीजें पनपें और फलें फूलें। तीनों को मिला कर ही हम कुछ कर सकेंगे क्योंकि अगर हम सिर्फ पब्लिक सेक्टर की तरफ अपनी तवज्जह देना चाहें तो हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है। रिसोर्सेज न होते हुए भी अगर हम को उस को आगे बढ़ाना है तो फिर वह कौन बढ़ाये ? आस्मान से फरिश्ते तो नहीं आयेंगे उसको बढ़ाने के लिये, दूसरे मुमालिक भी नहीं आयेंगे उस को बढ़ाने के लिये और मदद करने के लिये। चूंकि रुपया अपना होना चाहिये, रास्ता हमारा अपना होना चाहिये और मंजिल भी हमारी अपनी होनी चाहिये, इस लिये यह लाजिमी है।

इस तरफ कुछ कदम उठाये गये हैं धीरे-धीरे। बहुत से दोस्त कहते हैं कि नेशनलाइजेशन आफ बैंक्स ठीक है। ऐज ए स्लोगन यह ठीक है, लेकिन हम को देखना यह है कि आया क्या हम उस मुकाम पर पहुंच गये हैं जहां पर हम ऐसा कर सकते हैं, आया हम तैयार भी हैं। हम सभी कुछ चाहते हैं लेकिन हम को देखना है कि क्या मुल्क इस चीज के लिये तैयार है या नहीं। हम देख रहे हैं कि कि इस तरफ निहायत हिम्मत से कदम बढ़ाया गया है। सोशल कन्ट्रोल से इब्तदा

की गई है। नैचुरली हम को देखना है कि यह कैसे बढ़ेगा और कैसे पनपेगा और इसका असर साल, दो साल, तीन साल तक क्या रहेगा। उसके बाद हम देखेंगे। खुदा के फज़ल से इस से हमारी पोजीशन अच्छी हो जायेगी और हम एक कदम और आगे बढ़ा सकेंगे। मैं समझता हूं कि मुल्क की एकानमी पर इस से भी बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा क्योंकि जो जो शिकायात आई थीं बैंक चलाने वालों की, बैंक डाइरेक्टर्स की, बैंक के चेयरमैन की, बैंक के मैनेजिंग डाइरेक्टर्स की उस को हिम्मत से रोका गया और उस के बजाय ऐसा सिस्टम किया गया जिस में उन बातों के लिये कोई जगह नहीं है। मैं समझता हूं कि यह बहुत बड़ा कदम है।

उस के बाद हमारा मकसद है फोर्थ प्लैन के हिसाब से काम करना। उसके लिये हम सब कुछ कर रहे हैं। क्योंकि मेरा जहन प्लैन्ड डेवेलपमेंट की तरफ है, और उसके बगैर हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता है। मामूली सी दो बातें हुई। 1962 में चाइनीज वार और 1965 में पाकिस्तानी ऐग्रेशन। उसके साथ साथ बाकी बातें हुई। चुनांचे बद-किस्मती से हमारी एकानमी पर इस कदर असर पड़ा कि चौथी फाइव इअर प्लैन को हम को पीछे करना पड़ा। आज दो साल हो गये होते उस प्लैन को और शायद इस वक्त हम पांचवीं प्लैन के मुताल्लिक तैयारी करते। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, उम्मीद है चौथी पांच साला प्लैन अब साल भर के बाद शुरू की जायेगी। लेकिन जहां तक प्लैन्स का ताल्लुक है, अगर कोई कहे कि हम ने कुछ ऐचीव नहीं किया, तो यह गलत बात है। हां जो कुछ हम करना चाहते थे वह नहीं कर पाये, यह ईमानदारी की बात है। चा वह फूड का मामला हो, चाहे ऐग्रिकल्चर का हो चाहे डेवेलपमेंट का हो, चाहे इंडस्ट्रीज का हो, मेजर प्लैन्स का हो;, स्टील प्लैन्ट्स का हो, वह लगे तो सही। इस से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि आज भिलाई नहीं है। कोई भी अपनी आंखें नहीं बन्द कर सकता। लेकिन जो तमन्ना और ख्वाशिबात हमारी थीं वह पूरी नहीं हुई। लेकिन जो कुछ भी हम ने किया, अपने रिसोर्सेज के मुताबिक काफी किया और हम आगे बढ़ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। यह हो सकता है कि हमारे काम में खामियां रही हों। जहां जहां पर खामियां हैं, मैं दख्वास्त करूंगा कि वक्त आया है कि जहां और सब बातों की तरफ तवज्जह दी जाती है, उस तरफ भी तवज्जह दी जाये।

मैंने अभी कहा कि मैं तीनों सेक्टर्स में यकीन करता हूं। दैट इज दि आब्जेक्टिव क्योंकि जब हम ने 1951 में प्लैनिंग शुरू की तब हम अपने सामने जो आब्जेक्टिव रखे थे उन को बदला नहीं है यानी यह कि हम को पब्लिक सेक्टर, कोआपरेटिव सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर तीनों को ही साथ साथ बढ़ावा देना है। जब वक्त आयेगा सिर्फ पब्लिक सेक्टर की बात कहने का उस वक्त हम देखेंगे कि हमें क्या करना चाहिये, जब चौथी पांच साला प्लैन बनेगी, पांचवीं पांच साला प्लैन बनेगी। जैसा अभी हमारे दोस्त ने फैमिली प्लैनिंग के सिलसिले में कहा कि वह उसके माहिर हैं और अपनी महारत की बिना पर उन्होंने कुछ बातें कहीं, मैं उसका माहिर नहीं हूं, लेकिन चूंकि मेरा भी ताल्लुक रहा है पांचसाला प्लैन से, मैं समझता हूं कि हमारी पांच साला प्लैन्स की प्रापर स्क्रुटिनी हो और उस के टार्गेट्स फिक्स हों। टार्गेट्स फिक्स करने के साथ उन के ऐचीव करने की रिस्पांसिबिलिटी सेन्टर और स्टेट्स के बीच शेअर हो। जो सेन्टर की रिस्पांसिबिलिटी हो उसके सेन्टर पूरा करे और जो स्ट्टेस की रिस्पांसिबिलिटी हो उस को स्टेट्स पूरा करें, तो मैं समझता हूं कि कुछ नतीजाबरामद हो सकता है।

जैसा मैंने पहले अर्ज किया मेरा स्टेट से ताल्लुक रहा है। स्टेट्स की हर वक्त यह कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा रुपया उनको मिले, 200 करोड़, 300 करोड़, लेकिन उस के लिये रिसोर्सेज कहां हैं? हम को देखना चाहिये है कि हमारे पास इतना है या

[श्री गुलाम मुहम्मद बख्शी]

नहीं । स्टेट्स के अपने रिसोर्सेज इतने नहीं हो सकते, लेकिन साइज आफ दि प्लैन के मुताबिक, स्टेट्स का अपना कंट्रिब्यूशन टुवर्डस दि प्लैन होना चाहिये, चाहे वह 1/2 हो, 1/4 हो, 1/5 हो या 1/10 हो । तभी स्टेट्स को भी पिच करेगा कि यह स्कीम चलाई जाये । उन में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं, जिनका मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन अगर उन को ड्राप कर दिया जाये तो मेरे खयाल में उस से देश का जो रुपया जाया हो रहा है, उस से बहुत बड़े बड़े काम हम कर सकते हैं । लेकिन हमें हिम्मत से काम लेना है ।

मैं खादी की बात करूं । खादी वाले दोस्त शायद मुझ से नाराज हो जायें, लेकिन वह देखें कि खादी ऐंड विलेज इंडस्ट्रीज पर हम ने करोड़ों रुपये खर्च किये, लेकिन व्हाट इज दि रेजल्ट ? इसी तरह गवर्नमेंट ने भारत सेवक समाज पर करोड़ों रुपये खर्च किये, लेकिन व्हाट इज दि रेजल्ट ? पब्लिक अकाउंटस कमेटी की रपोर्ट को मैं पढ़ रहा था, और मैं ने देख लिया कि ऐसी चीजें हैं, जिन को, माफ कीजिये मुझे कोई और लफ्ज नहीं आता, मैं खुराफात ही कह सकता हूं । हम इस तरह की 20, 30 चीजों को मिला लें, 20 ही मिला लें, और अगर उन में से एक एक पर 5 करोड़ रुपया खर्च होते हैं तो 100, 200 करोड़ रुपये उन पर खर्च हो जाते हैं । इन 200 करोड़ रुपयों से आप क्या और कोई प्रोजेक्ट कायम नहीं कर सकते हैं ? अगर यह 200 करोड़ रुपया हम ऐग्रीकल्चर को दे दें तो शायद हम अपनी इम्पोर्ट्स कम ही न करें बल्कि हमेशा के लिये खत्म कर दें । आज तक मैं सुनता आया हूं कि मरहूम रफी अहमद किदवई साहब ने नैशनल डेवेलपमेंट कौंसिल में कहा था कि हम फूड के मामले में सिर्फ सेल्फ सफिशिएंट ही नहीं होंगे बल्कि अगले साल हम एक्स्पोर्ट भी करेंगे । आज रफी साहब को आंजहानी हुए सालहा साल हो गये लेकिन हम अभी भी फूड इम्पोर्ट करते जा रहे हैं । हमें फूड इम्पोर्ट करना है, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं । बम्पर क्राप्स के बावजूद करने हैं, बफर स्टाक जब तक हम विल्ड नहीं करेंगे तब तक हम उन ट्रेडर्स और ऐसे आदमियों के हाथों में खेलेंगे । बफर स्टाक हमारे लिए होना लाजिमी है । उस तरफ तवज्जह देना जरूरी है । चाहे हमारी कितनी अच्छी फसल भी क्यों न हुई हो अगले साल क्या होगा क्या नहीं होगा कोई कह नहीं सकता । तब तक इम्पोर्ट लाजिमी है । इम्पोर्ट कितना होगा, कितना नहीं होगा यह आप उन पर डाल दीजिए जिनकी जिम्मेदारी है । लेकिन देश में अकाल नहीं होना चाहिए । मुल्क में कीमतें इस प्रकार से न बढ़ें जैसे कि अभी हमने देखा कि 5 रुपये सेर चीनी और 3 रुपये सेर मामूली चावल । इन चीजों की तरफ तवज्जह दी जा रही है और दी जायगी । लेकिन बेसिकली जहां तक बाकी बातों का ताल्लुक है, एक साहब अभी कह रहे थे पोस्टकार्ड के मुताल्लिक, मैं चाहता हूं कि पोस्टकार्ड मुफ्त दे दिया जाय लेकिन देखना यह है कि क्या हमारी हालत ऐसी है कि मुफ्त दिया जाय ? एक आदत है कहने की कि फलां चीज मुफ्त हो लेकिन जब एक नेशन को बनना है और आप आज से 6 साल पहले देखें 1962 में आप का 221 या 228 करोड़ रुपया डिफेंस पर खर्च था, आज 1100 करोड़ है, यानी डिफेंस के लिए यह जरूरी है, तो हमें इतना बोझा खुद ही उठाना है । हालांकि इसके जो माहिर लोग हैं, उनका कहना है कि 1947 के 200 करोड़ और आज के 11 सौ करोड़ प्राइस लेवेल के लिहाज से एकसां हैं । . . .

MR. CHAIRMAN : The hon. Member will be brief now.

श्री गुलाम मुहम्मद बख्शी : I will take two or three minutes more.

तो मैं यह अर्ज कर रहा था फोर्थ प्लान के सिलसिले में । यानी एक असर इस बजट ने डाल दिया । उस ने अपना काम किया और करेगा । लेकिन मैं यह अर्ज करूंगा कि प्लान

में से बहुत सी ऐसी चीजें जो हैं उनके बारे में आप सोचें जैसे कि कम्यूनिटी डेवलपमेंट है, मैं जानता हूं कि हमने इसको रेजिस्ट किया लेकिन एक हवा चली कि कम्यूनिटी डेवलपमेंट होना चाहिए। जीप्स, बी० डी० ओज़०, डी० डी० ओज़० सी० डी० ओज़० और ए० नम्बर आफ डी० ओज़० बने और फाइनली इस नतीजे पर हम पहुंचे कि ऐडमिनिस्ट्रेशन जो है, वह बंट गई। ऐडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स जो हैं वह भी डिस-इंटीग्रेट हो गई और कोई काम नहीं कर सकतीं। न यह न वह, न बी० डी० ओ० न टी० डी० ओ०। नतीजे के तौर पर हमारा सारा पैसा जाया हुआ। तो मैं बजट के फ्रेम करने वालों से गुजारिश करूंगा प्लानिंग कमीशन के साथ आप बातचीत करें। मैं यहां बैठा हुआ हूं, इसके बावजूद जहां तक मुल्क के मामलात का ताल्लुक है, मुल्क के लिए जान भी हाजिर है। मैं नेशनल लीडरशिप से अर्ज करना चाहता हूं चाहे वह इधर हों चाहे उधर हों, नेशनल मामलात के सिलसिले में एक नेशनल अप्रोच हो और नेशनल मामलात की तरफ ज्यादा से ज्यादा तवज्जह दी जाय, बजट को बनाने, बजट को इम्लीमेंट करने और बजट को आगे चलाने के सिलसिले में एक कलेक्टिव थिंकिंग हो, एक कलेक्टिव अप्रोच हो, एक कलेक्टिव रेस्पांसिविलिटी हो और जो कुछ भी किया जाय, वह सोच समझ कर के किया जाय। ऐसा न किया जाय, जैसा कि मैं नाम नहीं लेना चाहता, अभी एक साथी जो वहां बैठे हैं उन्होंने कहा कि बेड़ा गर्क, मैं कहता हूं, बेड़ा गर्क नहीं, बेड़ा पार। अब खुद आप के आदमी कहें कि बेड़ा गर्क है तो दैट इटसेल्फ शोज कि आपस में कोहेशन नहीं है, आपस में कलेक्टिव थिंकिंग नहीं है। इस से मुल्क पर बड़ा खराब असर पड़ता है। तो मुझे यह अर्ज करनी है कि ऐसे मामलात चाहे वह डिफेंस हो चाहे हिन्दुस्तान की एकोनामी को बढ़ावा देना हो उस में कलेक्टिव थिंकिंग होनी चाहिए

Let us come from this pedestal of that prestige or false notions of prestige.

एक और एक दो सिर मिल कर ग्यारह हो जाते हैं। मिलकर अगर बैठें और मिल कर सोचें तो कन्ट्री की सारी डिफिकल्टीज़ हल हो सकती हैं। कंट्री के सामने जब भी डिफिकल्टीज़ आईं, चाइनीज़ ऐग्रेशन आया तो आप ने सोना मांगा, मुझे याद है, छोटी छोटी नाबालिग लड़कियों ने अपने ऊपर से सोना उतार कर दे दिया और जान देने के लिए भी तैयार हैं। उसके बाद 1965 आया। उस समय भी ऐसा ही हुआ। आज यहां बात हो रही थी राजस्थान का पानी और मध्य प्रदेश का पानी, —राजस्थान और मध्य प्रदेश तो ठीक है, बजाते खुद यह तो ठीक है, उनका पानी और उनका पानी लेकिन यह सारे देश का पानी है, यह कोई नहीं सोचता है। अगर देश मजबूत है तो देश के सारे अंग भी मजबूत हैं। लेकिन आज हिन्दुस्तानी के नाते कोई नहीं सोचता। आज हम सोचते हैं काश्मीरी के नाते, आन्ध्र प्रदेश के नाते, बंगाली के नाते, मध्य प्रदेश के नाते, राजस्थान के नाते लेकिन हिन्दुस्तानी के नाते नहीं सोचते। राजस्थान कैनाल का पानी पंजाब को सैलाब करता है, राजस्थान को भी करता है, मध्य प्रदेश को भी करेगा और जहां जहां देश में जो कमी है वहां उस चीज को देना है। मैं अर्ज करूंगा कि यह जिम्मेदारी है नेशनल लीडरशिप की आज हिन्दुस्तान में वह फिजा पैदा करने की और वह फिजा पैदा कर के लोगों को उसके ऊपर चलाने की। यह बजट जो है उसी अन्दाज़ में अगर पेश किया जाय तो मेरा अपना ख्याल है कि कहीं से आवाज नहीं उठेगी। आज मेरी ख्वाहिश थी कि आनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर इनकम टैक्स की लेबेल बढ़ा कर 5 हजार या 7 हजार करते। लेकिन मुल्क की हालत ऐसी नहीं है तो इसका क्या यह मतलब है कि हम न दें? यह तो कुर्बानी है मुल्क की बढ़ोत्तरी के लिए। मैं एक सजेशन दूंगा। एक चीज फाइनेंस डिपार्टमेंट से खास तौर पर या इनकी जो कलेक्टिंग एजेंसीज हैं चाहे इनकम टैक्स की या और कोई, उनसे मैं अर्ज करूंगा निहायत अदब के साथ कि वह हिन्दुस्तानियों के साथ आबरूमन्दाना सुलूक

[श्री गुलाम मुहम्मद बख्शी]

करें। आबरूमन्दाना सुलूक जब मैं कहता हूं उसका मतलब यह है कि जिससे भी आपको टैक्स लेना है, जो ड्यू है वह ले लेकिन उनके साथ चोरों जैसा सुलूक न करें बल्कि उनके साथ आबरूमन्दाना और इन्सान जैसा सुलूक करें। यह आपके पालतू बेटे हैं जो कमाते हैं आप के लिए, कमाऊ बेटे हैं और कमाऊ बेटे के साथ कोई गलत सुलूक नहीं करता। आज यह काले धन की बात करते हैं। मैं मोरार जी भाई से कहूंगा कि वह बहुत ज्यादा गांधी भक्त हैं। गांधी जी ने जो फारमूला दिया वह जरा लागू कर के देखें। कर के देख लीजिए, काला धन आपके सामने आता है या नहीं आता है? लाजिमी तौर पर आयेगा। लेकिन हिम्मत से काम लें।

यहां पर तो स्लोगन्स चारों तरफ चलते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जब कि जर्मनी को बनाने के लिए बात आई तो उन्होंने एलान कर दिया कि जिसके पास जो दौलत है, कौम को इस वक्त जरूरत है, कोई पूछताछ नहीं होगी, आये और बनाए और आज आप देखते हैं कि पहले से भी ज्यादा ताकतवर और अच्छा जर्मनी बन कर समाने आ गया है? हम हिन्दुस्तानियों को हो क्या गया है? यहां सिर्फ यह है कि जो यहां बैठे हैं वह अपने आप को समझते हैं फरिश्ता और जो दूसरे हैं वह हैं और जो दूसरे हैं वह हैं चोर। यह फरिश्ता और चोर आज तक कभी न मिले न मिलेंगे। हमें इन्सान बन कर जमीन पर कदम रखना है और जमीन पर कदम रख कर जनीन के प्राबलम को हमें हल करना है। यह मैं उनसे अर्ज करूंगा। इस तरीके से यह बातें नहीं आयेंगी। मसलन जैसे उन्होंने कहा कि कंसीलमेंट के लिए सजा दी जाए। ठीक है, दीजिए आप। उसको फांसी लगा दीजिए। कोई एतराज नहीं है। लेकिन एक शख्स मेरे घर पर आकर डाका डालता है, मुझे कत्ल करके जाता है और घर में जो कुछ है वह भी ले जाता है। उस के लिए पीनल कोड में सजा क्या है और आप यहां क्या कहते हैं? सोचिए मौत और काला पानी की सजा, खैर वह काला पानी तो आज नहीं रहा, लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद भी क्या हाल है? तो अपने इन कमाऊ बेटों के साथ जरा हिम्मत से काम लीजिए। एक क्रिटिसिज्म होता है, दो क्रिटिसिज्म होते हैं, तीन होते हैं, कोई बात नहीं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, इस बजट ने मुल्क में हालात ऐसे किए कि खुदा ने चाहा तो रिसेशन छः महीने में खत्म हो कर रहेगा और इंडस्ट्री और ट्रेड आगे बढ़ेगा। जहां तक बाकी चीजों का ताल्लुक है आल राउंड स्टेबिलिटी के आसार नुमायां हैं। जरा हिम्मत से और इरादे से काम लीजिए। लेकिन एक चीज में अर्ज करूंगा कि जमीन पर पांव रखिए। जमीन पर पांव रख कर जितने भी हैं छोटे बड़े उनको हिन्दुस्तानी समझिए और हिन्दुस्तानी गांधी जी के लब्जों में आबरूमंद इन्सान है। उसके साथ आबरूमन्दाना सुलूक करना लाजिमी है। यह मैं इनसे कहता हूं। बाकी डीटेल्स में मैं जाना नहीं चाहता हूं। मैं फिर बैठने से पहले मुबारकबाद देता हूं। यकीनन यह एक अच्छा खासा बजट है। इस को हमें हर सूरत में सपोर्ट करना चाहिए।

[شری غلام محمد بخشی (شری نگر):

جناب والا - میں کوئی زیادہ وقت ایوان کا نہیں لینا چاہتا ہوں - حالانکہ میں نے بجٹ کو سمجھنے کے سلسلے میں کافی محنت کی ہے اور کچھ فیگرس بھی ورک آؤٹ کئے ہیں لیکن ان میں میں جانا نہیں چاہتا ہوں - حالانکہ ایک چیز جہاں تک بجٹ کا تعلق ہے یہ کہے بغیر میں نہیں رہ سکتا ہوں کہ موجودہ حالات میں جو کہ ملک کے حالات ہیں اور جو ملک کو مسائل اور پیچیدگیاں در پیش ہیں ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اس سے بہتر بجٹ پیش

اور پرائسیز جو تھے وہ صرف اسٹیبلائزنز ہی نہیں ہوئے بلکہ کچھ اچھے بھی ہوئے ۔ اس لئے اس بجٹ کا عام طور پر اثر ٹھیک پڑ رہا ہے ۔

ملک کو دو تین باتوں کی طرف خاص توجہہ دینے کی ضرورت ہے ۔ ایک تو چیز ہے ملک کا ڈیفنس ۔ ملک کی سیکیوریٹی ۔ اس کے لئے لازمی ہمیں خیال رکھنا ہے کہ ملک کے بچاؤ کے لئے اور ملک کی سیکیوریٹی کے لئے انتظام ہو چنانچہ بجٹ میں آپ دیکھینگے کہ اس کی طرف خاص توجہہ دی گئی ہے ۔ ایکسپینڈیچر کچھ تھوڑا بہت ہمارا بڑھا ہے لیکن اس سے ہمیں گھبرانا نہیں چاہئے کیونکہ اگر ملک محفوظ ہے تو سب کچھ محفوظ ہے ۔ لیکن اگر ملک محفوظ نہیں ہے، ہندوستان محفوظ نہیں ہے نو کروڑں چھوڑ کر ہزاروں کروڑ کی بھی آمدنی ہو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے ۔ یہ بھی ایک خاصہ اچھا اسٹیپ ہے جس کے ذریعہ سے ملک کی حفاظت کی طرف توجہ دی گئی ہے ۔

یہاں پر جتنی باتیں ہوئی ہیں سنتا رہا ۔ بجٹ اسپیچیز اور اپروچیز ہر ایک شخص کی اور میں ہر ایک طریقہ کی ۔ لیکن ایک چیز میں گذارش کرونگا کہ ہم نے اپنے جو آبجیکٹوز اور آئڈیلس دیش کے سامنے رکھے ہیں ۔ آزادی کے وقت سے آج تک ۔ ان کی طرف زیادہ سے نہیں کیا جا سکتا تھا ۔ اس لئے میں اپنی طرف سے آنریبل فائنس منسٹر کو اور ان کے ساتھیوں کو یقیناً مبارک باد دونگا ۔ بجٹ کے ڈیٹیلس میں اپروچیز میں اور باقی اور چیزوں میں پچاسوں شکائتیں ہو سکتی ہیں لیکن ان کے بجٹ سے ہمیں دیکھنا یہ ہے اور کسی بھی بجٹ کو پرکھنے کا اور دیکھنے کا خاص طور پر یہ ڈھنگ ہوتا ہے کہ ملک پر اس کا اثر کیا پڑتا ہے ۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بجٹ پیش ہونے کے بعد سے آج تک ملک میں اس کا ایک اچھا خاصا اثر پڑ رہا ہے ۔ میرا اپنا یہ خیال ہے اور جیسا کہ اخباروں کے ٹرینڈس اور خاص طور پر وہ لوگ جو کہ ملک کی ایکانامی کو سمجھتے ہیں ان سے بات چیت کرنے کے بعد یہ معلوم پڑتا ہے کہ یہ موجودہ ریسیشن بھی ایک اسٹیبلائزنگ فیکٹر ہوگا ۔ چنانچہ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ ٹریڈ ۔ کامرس اور انڈسٹریز جن مشکلات میں اپنے آپ کو پاتے تھے وہ بھی دھیرے دھیرے اس میں سے نکلینگے اور دھیرے دھیرے نکل کر آگے بڑھینگے ۔

ایک ہی چیز میں اسٹڈی کرتا رہا کہ اس کا اثر شیرئس اور اسٹاک ایکسچینج پر کیا پڑا ۔ ایک ملک کی ایکانامی کی یہ باتیں آئنہ دار ہوتی ہیں اور ان پر میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک اچھا خاصا اثر پڑ رہا ہے

گول کی طرف آگے لے جانا ہے جہاں ان تینوں چیزوں کی گنجائش ہو اور یہ تینوں چیزیں پنپیں اور پھلیں پھولیں - تینوں کو ملا کر ہی ہم کچھ کر سکیں گے کیونکہ اگر ہم صرف پبلک سیکٹر کی طرف اپنی توجہ دینا چاہیں تو ہمارے پاس اتنے رسورسیز نہیں ہیں - رسورسیز نہ ہوتے ہوئے بھی اگر ہم نے اس کو آگے بڑھانا ہے تو پھر وہ کون بڑھائے ؟ آسمان سے فرشتے تو نہیں آئیں گے اس کو بڑھانے کے لئے - دوسرے ممالک بھی نہیں آئیں گے اس کو بڑھانے کے لئے اور مدد کرنے کے لئے - چونکہ روپیہ اپنا ہونا چاہئے - راستہ ہمارا اپنا ہونا چاہئے اور منزل بھی ہماری اپنی ہونی چاہئے - اس لئے یہ لازمی ہے -

اس طرف کچھ قدم اٹھائے گئے ہیں دھیرے دھیرے - بہت سے دوست کہتے ہیں کہ نیشنلائزیشن آف بینکس ٹھیک ہے - ایز اے سلوگن یہ ٹھیک ہے - لیکن ہم کو دیکھنا یہ ہے کہ آیا کیا ہم اس مقام پر پہنچ گئے ہیں جہاں پر ہم ایسا کر سکتے ہیں - آیا ہم تیار بھی ہیں - ہم سبھی کچھ چاہتے ہیں - لیکن ہم کو دیکھنا ہے کہ کیا ملک اس چیز کے لئے تیار ہے یا نہیں - ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرف نہایت ہمت سے قدم بڑھایا گیا ہے - سوشل کنٹرول سے ابتدا کی گئی ہے - نیچورلی ہم کو

[شری غلام محمد بخشی]

زیادہ توجہ دینی چاہئے - اور وہ یہ کہ ہم اس دیش کو دھیرے دھیرے سوشلزم کی طرف لے جائیں - اگر ہم کہیں کہ سوشلزم ایک دن میں آ جائے تو یہ ناممکن ہے اور مشکل ہے - سوشلزم کی طرف قدم اٹھانے میں ہم نے تین ضروری چیزیں کہی ہیں - یعنی یہ کہ ہم جہاں پبلک سیکٹر کو بڑھاوا دیں گے وہاں کوآپریٹو سیکٹر کو بھی ساتھ چلائیں گے اور پرائیویٹ سیکٹر کو بھی ساتھ ساتھ بڑھاوا دیں گے - اگر ہم صرف پبلک سیکٹر پبلک سیکٹر ہی کرتے رہے اور پرائویٹ سیکٹر کو اگنور کیا تو ہماری ایکانامی کا بیلینس ٹلٹ ہو جائے گا - اور جہاں تک ہمارا خیال ہے ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے - اس نہ بڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ یہاں پر کریٹیسزم ہوتا ہے کہ ہم کو پبلک سیکٹر میں نقصان کیوں ہو رہا ہے - اس کے کئی کارن ہیں - لیکن میں اس وقت ان میں نہیں جاؤنگا - اگر پھر کبھی موقع ملے گا تب اس میں جاونگا - لیکن اگر تینوں چیزوں پر ساتھ ساتھ نگاہ نہیں رکھیں گے ملک کے سدھار کے لئے اور ایکانمی کے سدھار کے لئے - تو ہم بہت بڑی غلطی کریں گے - اگر ہم کو اس میں کچھ کریٹیسزم بھی برداشت کرنا پڑے تو بھی ہم کو ملک کو دھیرے دھیرے اس

وقت ہم پانچویں پلین کے متعلق تیاری کرتے ۔ لیکن جیسا کہ کہا جاتا ہے ۔ امید ہے چوتھی پانچ سالہ پلین اب سال بھر کے بعد شروع کی جائے گی ۔ لیکن جہاں تک پلینس کا تعلق ہے ۔ اگر کوئی کہے کہ ہم نے کچھ اچیو نہیں کیا ۔ تو یہ غلط بات ہے ۔ ہاں جو کچھ ہم کرنا چاہتے تھے وہ نہیں کر پائے ۔ یہ ایمانداری کی بات ہے ۔ چاہے وہ فوڈ کا معاملہ ہو ۔ چاہے ایگریکلچر کا ہو ۔ چاہے ڈیولپمنٹ کا ہو ۔ چاہے انڈسٹریز کا ہو ۔ میجر پلینس کا ہو ۔ اسٹیل پلانٹس کا ہو ۔ وہ لگے تو صحیح ۔ اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ آج بھلائی نہیں ہے ۔ کوئی بھی اپنی آنکھیں نہیں بند کر سکتا ۔ لیکن جو تمنا اور خواہشات ہماری تھیں وہ پوری نہیں ہوئیں ۔ لیکن جو کچھ بھی ہم نے کیا ۔ اپنے رسورسیز کے مطابق کافی کیا اور ہم آگے بڑھ رہے ہیں ۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے ۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے کام میں خامیاں رہی ہوں ۔ جہاں جہاں پر خامیاں ہیں ۔ میں درخواست کرونگا کہ وقت آیا ہے کہ جہاں اور سب باتوں کی طرف توجہ دی جاتی ہے ۔ اس طرف بھی توجہ دی جائے ۔

•

میں نے ابھی کہا کہ میں تینوں سیکٹرس میں یقین کرتا ہوں ۔ ڈیٹ از دیکھنا ہے کہ یہ کیسے بڑھے گا اور کیسے پنپے گا اور اس کا اثر سال ۔ دو سال ۔ تین سال تک کیا رہے گا ۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے ۔ خدا کے فضل سے اس سے ہماری پوزیشن اچھی ہو جائے گی اور ہم ایک قدم اور آگے بڑھا سکیں گے ۔ میں سمجھتا ہوں کہ ملک کی ایکانمی پر اس سے بھی بہت بڑا فرق پڑے گا کیونکہ جو جو شکایات آئی تھیں بینک چلانے والوں کی ۔ بینک ڈائریکٹرس کی ۔ بینک کے چیرمین کی ۔ بینک کے مینیجنگ ڈائریکٹرس کی اس کو ہمت سے روکا گیا اور اس کے بجائے ایسا سسٹم کیا گیا جس میں ان باتوں کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے ۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا قدم ہے ۔

اس کے بعد ہمارا مقصد ہے فورتھ پلین کے حساب سے کام کرنا ۔ اس کے لئے ہم سب کچھ کر رہے ہیں۔ کیونکہ میرا ذہن پلینڈ ڈیویلپمنیٹ کی طرف ہے ۔ اور اس کے بغیر ہمارا دیش آگے نہیں بڑھ سکتا ہے ۔ معمولی سی دو باتیں ہوئیں ۔ ۱۹۶۲ میں چائنیز وار اور ۱۹۶۵ میں پاکستانی ایگریشن ۔ اس کے ساتھ ساتھ باقی باتیں ہوئیں ۔ چنانچہ بدقسمتی سے ہماری ایکانمی پر اس قدر اثر پڑا کہ چوتھی فائو ایئر پلین کو ہم کو پیچھے کرنا پڑا ۔ آج دو سال ہو گئے ہوتے اس پلین کو اور شائد اس

زیادہ سے زیادہ روپیہ ان کو ملے - ۲۰۰ کروڑ - ۳۰۰ کروڑ - لیکن اس کے لئے رسورسیز کہاں هیں ؟ هم کو دیکھنا چاهئے که هے همارے پاس اتنا هے یا نہیں - اسٹیٹس کے اپنے رسورسیز اتنے نہیں هو سکتے - لیکن سائز آف دی پلین کے مطابق اسٹیٹس کا اپنا کنٹریبیوشن ٹرورڈس دی پلین هونا چاهئے - چاهے وہ ½ هو - ¼ هو - ⅕ هو یا $\frac{1}{10}$ هو - تبھی اسٹیٹس کو بھی پنچ کریگا که یه اسکیم چلائی جائے - ان میں بہت سی ایسی باتیں هوتی هیں - جن کا میں نام تو نہیں لینا چاهتا - لیکن اگر ان کو ڈراپ کر دیا جائے تو میرے خیال میں اس سے دیش کا جو روپیه ضائع هو رها هے - اس سے سے بہت بڑے بڑے کام هم کر سکتے هیں - لیکن همیں همت سے کام لینا هے -

میں کھادی کی بات کروں - کھادی والے دوست شائد مجھ سے ناراض هو جائیں - لیکن وہ دیکھیں که کھادی اینڈ ولیج انڈسٹریز پر هم نے کروڑوں روپئے خرچ کئے - لیکن وهاٹ از دی ریزلٹ - اسی طرح گورنمنٹ نے بھارت سیوک سماج پر کروڑوں روپئے خرچ کئے - لیکن وهاٹ از دی ریزلٹ - پبلک اکاونٹس کمیٹی کی رپورٹ کو میں پڑھ رها تھا - اور میں نے دیکھ لیا که ایسی سی چیزیں هیں - جن کو - معاف

[شری غلام محمد بخشی]

دی آبجیکٹو کیونکه جب هم نے ۱۹۵۱ میں پلیننگ شروع کی تب هم نے اپنے سامنے جو آبجیکٹوز رکھے تھے ان کو بدلا نہیں هے یعنی یه که هم کو پبلک سیکٹر - کوآپریٹو سیکٹر اور پرائویٹ سیکٹر تینوں کو هی ساتھ ساتھ بڑھاوا دینا هے - جب وقت آئے گا صرف پبلک سیکٹر کی بات کہنے کا اس وقت هم دیکھیں گے که همیں کیا کرنا چاهئے - جب چوتھی پانچ ساله پلین بنیگی - پانچویں پانچ ساله پلین بنیگی - جیسا ابھی همارے دوست نے فیملی پلیننگ کے سلسلے میں کہا که وہ اس کے ماهر هیں اور اپنی مہارت کی بنا پر انہوں نے کچھ باتیں کہیں - میں اس کا ماهر نہیں هوں - لیکن چونکه میرا بھی تعلق رها هے پانچ ساله پلین سے - میں سمجھتا هوں که هماری پانچ ساله پلینس کی برابر سکروٹینی هو اور اس کے ٹارگیٹس فکس هوں - ٹارگیٹس فکس کرنے کے ساتھ ان کے اچیو کرنے کی رسپانسبیلیٹی سینٹر اور اسٹیٹس کے بیچ شیئر هو - جو سینٹر کی رسپانسبیلیٹی هو اس کو سینٹر پورا کرے اور جو اسٹیٹس کی رسپانسبیلیٹی هو اس کو اسٹیٹس پورا کریں - تو میں سمجھتا هوں که کچھ نتیجه بر آمد هو سکتا هے -

جیسا میں نے پہلے عرض کیا میرا اسٹیٹ سے تعلق رها هے - اسٹیٹس کی هر وقت یه کوشش رهتی هے که

اگلے سال کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا کوئی کہہ نہیں سکتا - تب تک امپورٹ لازمی ہے - امپورٹ کتنا ہوگا کتنا نہیں ہوگا یہ آپ ان پر ڈال دیجئے جن کی ذمہ داری ہے - لیکن دیش میں اکال نہیں ہونا چاہئے - ملک میں قیمتیں اس پرکار سے نہ بڑھیں جیسے کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ ۵ روپیہ سیر چینی اور ۳ روپیہ سیر معمولی دال - ان چیزوں کی طرف توجہ دی جا رہی ہے اور دی جائیگی لیکن بیسیکلی جہاں تک باقی باتوں کا تعلق ہے ایک صاحب ابھی کہہ رہے تھے پوسٹ کارڈ کے متعلق میں چاہتا ہوں کہ پوسٹ کارڈ مفت دے دیا جائے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہماری حالت ایسی ہے کہ مفت دیا جائے ؟ ایک عادت ہے کہنے کی کہ فلاں چیز مفت ہو لیکن جب ایک نیشن کو بننا ہے اور آپ آج سے ۶ سال پہلے دیکھیں ۱۹۶۲ میں آپ کا ۲۲۱ یا ۲۲۸ کروڑ روپیہ ڈیفینس پر خرچ تھا آج ۱۱۰۰ کروڑ ہے یعنی ڈیفینس کے لئے یہ ضروری ہے تو ہمیں اتنا بوجھ خود ہی اٹھانا ہے—حالانکہ اس کے جو ماہر لوگ ہیں ان کا کہنا ہے کہ ۱۹۴۷ کے ۲۰۰ کروڑ اور آج کے ۱۱۰۰ کروڑ پرائس لیول کے لحاظ سے یکساں ہیں -.....

MR. CHAIRMAN : The hon. Member will be brief now.

SHRI GHULAM MOHAMMAD BAKSHI : I will take two or three minutes more.

کیجئے مجھے کوئی لفظ نہیں آتا - میں خرافات ہی کہہ سکتا ہوں - ہم اس طرح سی ۲۰-۳۰ چیزوں کو ملا لیں ۲۰ ہی ملا لیں - اور اگر ان میں سے ایک ایک پر ۵ کروڑ روپئے خرچ ہوتے ہیں تو ۱۰۰-۲۰۰ کروڑ روپئے ان پر خرچ ہو جاتے ہیں - ان ۲۰۰ کروڑ روپیوں میں سے آپ کیا اور کوئی پروجیکٹ قائم نہیں کر سکتے ہیں - اگر یہ ۲۰۰ کروڑ روپیہ ہم ایگریکلچر کو دے دیں تو شائد ہم اپنی امپورٹس کم ہی نہ کریں بلکہ ہمیشہ کے لئے ختم کر دیں - آج تک میں سنتا آیا ہوں کہ مرحوم رفیع احمد قدوائی صاحب نے نیشنل ڈیولپمینٹ کونسل میں کہا تھا کہ ہم فوڈ کے معاملہ میں صرف سیلف سفیشنٹ ہی نہیں ہوں گے بلکہ اگلے سال ہم ایکسپورٹ بھی کریں گے - آج رفی صاحب کو آنجہانی ہوئے سالہا سال ہو گئے لیکن ہم ابھی بھی فوڈ امپورٹ کرتے جا رہے ہیں- ہمیں فوڈ امپورٹ کرنا ہے - میں اس کے خلاف نہیں ہوں - بمپر کراپس کے باوجود کرنے ہیں - بفر سٹاک جب تک ہم بلڈ نہیں کرینگے تب تک ہم ان ٹریڈرس اور ایسے آدمیوں کے ہاتھوں میں کھیلینگے - بفر سٹاک ہمارے لئے ہونا لازمی ہے - اس طرف توجہ دینا ضروری ہے - چاہے ہماری کتنی اچھی فصل بھی کیوں نہ ہوئی ہو

[شری غلام محمد بخشی]

تو میں یہ عرض کر رہا تھا فورتھ پلان کے سلسلے میں - یعنی ایک اثر اس بجٹ نے ڈال دیا - اس نے اپنا کام کیا اور کریگا - لیکن میں یہ عرض کرونگا کہ پلان میں سے بہت سی ایسی چیزیں جو ھیں ان کے بارے میں آپ سوچیں جیسے کہ کمیونٹی ڈیولپمینٹ ھے میں جانتا ھوں کہ ھم نے اس کو ری زسٹ کیا لیکن ایک ھوا چلی کہ کمیونٹی ڈیولپمینٹ ھونا چاھئے - جیپس، بی 'ڈی، اوز، ڈی، ڈی اوز، سی، ڈی، اوز، اور اے نمبر آپ ڈی اوز بنے - اور فائنلی اس نتیجہ پر ھم پہنچے کہ ایڈمنسٹریشن جو ھے وہ بنٹ گئی - ایڈمنسٹریٹو یونٹس جو ھیں وہ بھی ڈس انٹیگریٹ ھو گئیں - اور کوئی کام نہیں کر سکتیں - نہ یہ نہ وہ نہ جی 'ڈی، او، نہ ٹی، ڈی، او، - نتیجہ کے طور پر سارا پیسہ ضائع ھوا - تو میں بجٹ فریم کرنے والوں سے گذارش کرونگا پلاننگ کمیشن کے ساتھ آپ بات چیت کریں - میں یہاں بیٹھا ھوا ھوں اس کے باوجود جہاں تک ملک کے معاملات کا تعلق ھے ملک کے لئے جان بھی حاضر ھے - میں نیشنل لیڈر شپ سے عرض کرنا چاھتا ھوں چاھے وہ ادھر ھوں چاھے ادھر ھوں نیشنل معاملات کے سلسلے میں ایک نیشنل اپیروچ ھو اور نیشنل معاملات کی طرف زیادہ سے زیادہ توجہہ دی جائے بجٹ کو بنانے، بجٹ کو امپلیمینٹ کرنے اور بجٹ کو آگے چلانے کے سلسلہ میں ایک کلیکٹو تھنکنگ ھو—ایک کلیکٹو اپروچ ھو—ایک کلیکٹو ریسپانسبلٹی ھو اور جو کچھ بھی کیا جائے وہ سوچ سمجھ کر کیا جائے - ایسا نہ کیا جائے جیسا کہ میں نام نہیں لینا چاھتا ابھی ایک ساتھی جو وھاں بیٹھے ھیں انہوں نے کہا کہ بیڑا غرق—میں کہتا ھوں کہ بیڑا غرق نہیں بیڑا پار - اب خود آپ کے آدمی کہیں کہ بیڑا غرق ھے تو دیٹ اٹ سیلف شوز کہ آپس میں کوھیشن نہیں ھے آپس میں کلیکٹو تھنکنگ نہیں ھے - اس سے ملک پر بڑا خراب اثر پڑتا ھے - تو مجھے یہ عرض کرنی ھے کہ ایسے معاملات چاھے وہ ڈیفینس ھو چاھے ھندوستان کی ایکونامی کو بڑھاوا دینا ھو اس میں کلکیٹو تھنکنگ ھونی چاھئے -

Let us come from this pedestal of that prestige or false notions of prestige.

ایک اور ایک دو سر مل کر گیارہ ھو جاتے ھیں - مل کر اگر بیٹھیں اور مل کر سوچیں تو کنٹری کی ساری ڈفیکلٹیز ھل ھو سکتی ھیں - کنٹری کے سامنے جب بھی ڈفیکلٹیز آئیں چائنیز ایگریشن آیا تو آپ نے سونا مانگا مجھے یاد ھے چھوٹی چھوٹی نابالغ لڑکیوں نے اپنے اوپر سے سونا اتار کر دے دیا اور جان دینے کے لئے بھی تیار ھیں - اس کے بعد ۱۹۶۵ آیا - اس سمے بھی ایسا ھی ھوا - آج یہاں بات ھو رھی تھی راجستھان کا پانی اور مدھیہ پردیش کا پانی - راجستھان اور مدھیہ پردیش تو ٹھیک ھے - بذات خود یہ تو ٹھیک ھے ان کا پانی اور ان کا پانی لیکن

ٹیکس کی یا اور کوئی ان سے میں
عرض کرونگا نہایت ادب کے ساتھ
کہ وہ ہندوستانیوں کے ساتھ
آبرومندانہ سلوک کریں - آبرومندانہ
سلوک جب میں کہتا ہوں اس کا
مطلب یہ ہے کہ جس سے بھی آپ
کو ٹیکس لینا ہے جو ڈیو ہے وہ
لیں لیکن ان کے ساتھ چوروں جیسا
سلوک نہ کریں بلکہ ان کے ساتھ
آبرومندانہ اور انسان جیسا سلوک
کریں - یہ آپ کے پالتو بیٹے ہیں جو
کماتے ہیں آپ کے لئے - کماؤ بیٹے
ہیں اور کماؤ بیٹے کے ساتھ کوئی
غلط سلوک نہیں کرتا - آج یہ
کالے دھن کی بات کرتے ہیں - میں
مرار جی بھائی سے کہونگا کہ وہ
بہت زیادہ گاندھی بھگت ہیں -
گاندھی جی نے جو فارمولا دیا وہ
ذرا لاگو کرکے دیکھیں - کرکے
دیکھ ایجئے کالا دھن آپ کے سامنے
آتا ہے یا نہیں آتا ہے- لازمی طور
پر آیگا - لیکن ہمت سے کام لیں -
یہاں پر تو سلوگنس چاروں طرف
چلتے ہیں - میں کہنا چاہتا ہوں
جب کہ جرمنی کو بنانے کے لئے
بات آئی تو انہوں نے اعلان کر دیا
کہ جس کے پاس جو دولت ہے قوم کو
اس وقت ضرورت ہے کوئی پوچھ تاچھ
نہیں ہوگی - آئے اور بنائے اور
آج آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے سے بھی
زیادہ طاقت ور اور اچھا جرمنی
بن کر سامنے آگیا - ہم ہندوستانیوں
یہ سارے دیش کا پانی ہے یہ
کوئی نہیں سوچتا ہے - اگر دیش
مضبوط ہے تو دیش کے سارے
انگ بھی مضبوط ہیں - لیکن آج
ہندوستانی کے ناتے کوئی نہیں سوچتا-
آج ہم سوچتے ہیں کاشمیری کے
ناتے، آندھر پردیش کے ناتے، بنگالی
کے ناتے، مدھیہ پردیش کے ناتے،
راجستھان کے ناتے، لیکن ہندوستانی کے
ناتے نہیں سوچتے - راجستھان کینال
کا پانی پنجاب کو سیلاب کرتا ہے
راجستھان کو بھی کرتا ہے مدھیہ
پردیش کو بھی کریگا اور جہاں
جہاں دیش میں جو کمی ہے وہاں
اس چیز کو دینا ہے - میں عرض
کرونگا کہ یہ ذمہ داری ہے نیشنل
لیڈر شپ کی آج ہندوستان میں وہ
فضا پیدا کرنے کی اور وہ فضا پیدا
کرکے لوگوں کو اس کے اوپر چلانے
کی - یہ بجٹ جو ہے اسی انداز میں
اگر پیش کیا جائے تو میرا
اپنا خیال ہے کہ کہیں سے آواز نہیں
اٹھیگی - آج میری خواہش تھی کہ
آنریبل فائنینس منسٹر انکم ٹیکس کی
لیویل بڑھا کر پانچ ہزار یا سات ہزار
کرتے - لیکن ملک کی حالت ایسی
نہیں ہے تو اس کا کیا یہ مطلب ہے
کہ ہم نہ دیں - یہ تو قربانی ہے
ملک کی بڑھوتری کے لئے - میں ایک
سجیشن دونگا - ایک چیز فائنینس
ڈپارٹمینٹ سے خاص طور پر یا ان کی
جو کلیکٹنگ ایجینسیز ہیں چاہے انکم

کر رہیگا اور انڈسٹری اور ٹریڈ آگے بڑھیگا ۔ جہاں تک باقی چیزوں کا تعلق ہے آل راؤنڈ سٹیبلٹی کے آثار نمایاں ہیں ۔ ذرا ہمت سے اور ارادے سے کام لیجئے ۔ لیکن ایک چیز میں عرض کرونگا کہ زمین پر پاؤں رکھئے ۔ زمین پر پاؤں رکھ کر جتنے بھی ہیں چھوٹے بڑے ان کو ہندوستانی سمجھئے اور ہندوستانی گاندھی جی کے لفظوں میں آبرومند انسان ہے ۔ اس کے ساتھ آبرومندانہ سلوک کرنا لازمی ہے ۔ یہ میں ان سے کہتا ہوں ۔ باقی ڈیٹیلس میں میں جانا نہیں چاہتا ہوں ۔ میں پھر بیٹھنے سے پہلے مبارک باد دیتا ہوں ۔ یقیناً یہ ایک اچھا خاصا بجٹ ہے ۔ اس کو ہمیں ہر صورت میں سپورٹ کرنا چاہئے ۔]

18 hrs.

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : चेयरमैन, महोदय, मैं आपका बहुत मशकूर हूं कि आपने मुझे वक्त दिया । अपनी तकरीर शुरू करने से पहले मैं अपना यह बुनियादी फर्ज समझता हूं कि अपने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करूं कि उन्होंने हमारी बहादुर फौजों—बरी फौज, बहरी फौज और हवाई फौज—के अफसरान और सिपाहियों की तन-ख्वाहों को बढ़ा कर न सिर्फ देश की सेवा की है, बल्कि फौज के अन्दर बेहद अपना मान बढ़ाया है, और फौज का मोरेल हाई किया है—जिसके लिये वह मुबारकवाद के पात्र हैं ।

दूसरी बात—सब से ज्यादा कमी अगर मैं किसी बात में समझता हूं तो वह यह है कि सरकार के खजाने का मुंह शहर के बजाय देहात की तरफ़ होना चाहिये और देहात में भी सब से पहले उन गरीबों की तरफ़ जो कीड़े-मकौड़ों की जिन्दगी बसर करते हैं, जो आलीशान बंगलों

[شری غلام محمد بخشی]

کو ہو کیا گیا ہے ۔ یہاں صرف یہ ہے کہ جو یہاں بیٹھے ہیں وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں فرشتہ اور جو دوسرے ہیں وہ ہیں چور ۔ یہ فرشتہ اور چور تو آج تک کبھی نہ ملے نہ ملینگے ۔ ہمیں انسان بن کر زمین پر قدم رکھنا ہے اور زمین پر قدم رکھ کر زمین کے پرابلم کو ہمیں حل کرنا ہے ۔ یہ میں ان سے عرض کرونگا ۔ اس طریقے سے یہ باتیں نہیں آئیں گی ۔ مثلاً جیسے انہوں نے کہا کہ کنسیل مینٹ کے لئے سزا دی جائے ۔ ٹھیک ہے دیجئے آپ ۔ اس کو پھانسی لگا دیجئے ۔ کوئی اعتراض نہیں ہے ۔ لیکن ایک شخص میرے گھر پر آ کر ڈاکہ ڈالتا ہے مجھے قتل کرکے جاتا ہے اور گھر میں جو کچھ ہے وہ بھی لے جاتا ہے ۔ اس کے لئے پینل کوڈ میں سزا کیا ہے اور آپ یہاں کیا کہتے ہیں ۔ سوچئے موت اور کالا پانی کی سزا خیر وہ کالا پانی تو آج نہیں رہا لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود بھی کیا حال ہے ۔ تو اپنے ان کماؤ بیٹوں کے ساتھ ذرا ہمت سے کام لیجئے ۔ ایک کرٹسزم ہوتا ہے دو کرٹسزم ہوتے ہیں تین ہوتے ہیں کوئی بات نہیں ۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اس بجٹ نے ملک میں حالات ایسے کئے کہ خدا نے چاہا تو ریسیشن ٦ مہینے میں ختم ہو

में इस शहर की फ़िज़ा में नहीं, जहां बड़े बड़े रेक्रियेशन के सैन्टर नहीं हैं, जहां सिनेमाघर नहीं हैं, बल्कि वे आदमी जिनके पास आज सिर छुपाने की भी जगह नहीं है। जो कच्ची झोपड़ियों और झुग्गियों में रहते हैं और आये-साल बरसात में जिनके कच्चे मकान, झुग्गियां गिर जाती हैं, उनको बसाने का वह ख्याल करें। हमारे देश की 80 फीसदी आबादी आज देहातों में रहती है, इन 80 फीसदी में से 50 फीसदी आदमी ऐसे हैं, जो बेहद दुखी हैं, जिनका नाम "हरिजन" है, जिनका नाम बैकवर्ड क्लासेज है, जिनका नाम गरीब-मजदूर है, जिनका नाम गरीब किसान है—मैं खास तौर से उनकी तरफ़ आपकी तवज्जह दिलाना चाहता हूं।

मैं उनका नक्शा इस वास्ते आपके सामने रखना चाहता हूं कि शहरों में तो लोगों के लिये "ओन योर-हाउसिंगस-स्कीम" गवर्नमेन्ट की भी चल रही है और एल० आइ० सी० की भी चल रही है शहरों में एक अमीर आदमी को इतनी अपारचुनिटीज हासिल हैं कि अगर वह कहीं पर कोई प्लाट लेना चाहे तो उसे प्लाट भी मिलेगा और अगर लाख-दो-लाख रुपया खर्च करना चाहें, घर में चाहे उसकी कौड़ी भी न हो उसको लाख-दो-लाख रुपया भी मिल जाएगा और एक बड़ा आलीशान मकान उसके रहने के लिए बन जाएगा, लेकिन देहात में अगर एक गरीब आदमी माकन बनाने के लिए सौ रुपया या दो सौ रुपया सरकार से लेना चाहे या एल० आई०सी० से लेना चाहे, तो उसे नहीं मिलेगा। हमारे संविधान के प्रीयेम्बल में लिखा है कि हर एक आदमी को ईक्वल अपारचुनिटी मिलेगी—लेकिन हमारे इन करोड़ों आदमियों को वह ईक्वल अपारचुनिटी नहीं मिल पाती है। हमें कम से कम उनके रहने के लिए, सिर छुपाने के लिए जगह देनी चाहिए।

चेयरमैन साहब, मैं कोई जज्बात की बात नहीं कहता हूं। जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, वही कहता हूं। 4' बाई 6' की कच्ची कोठरी है, जिसमें 15 आदमियों का कुनबा रहता है, उन 15 आदमियों में 2 जवान बेटिया हैं, 4 जवान बेटे हैं, जिनकी चार जवान बहुएं हैं, सर्दी का मुकाम है, वह कैसे सोयें। मैं आपको बताना चाहता हूं—मुझे शर्म आती है—जवान लड़की जब घर में आती है तो उसको सोने की जगह नहीं मिलती है इसी वजह से कई रिश्ते छूट गए, कहां सुलाए बहू को। इसलिए मैं फाइनेन्स मिनिस्टर साहब से यह दरख्वास्त करना चाहता हूं कि यह बड़ा गम्भीर मामला है—इसकी तरफ उन्हें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि महात्मा गांधी बड़े जोर से इस बात को कहते थे, अपने लेखों में लिखा करते थे, हमारे स्वर्गीय प्रधान मन्त्री पं० जवाहर लाल नेहरू इस बात को बड़े जोर से कहते थे और जब उनकी जगह को और स्लम्ज को वह देखते थे तो उनके दिमाग पर इतना असर होता था कि उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। वह शहर की जगहों को, यहां के स्लम्ज को देखते थे, देहात के स्लम्ज को देखने का तो उनको टाइम नहीं मिलता था। मैं इसलिए इन बातों को कहना चाहता हूं—खास तौर पर देहात को जो मिट्टी के तोंदे हैं, उनको बनाने के लिये आप हाउसिंग स्कीम जारी करें और कुछ रुपया चाहे एल० आई० सी० का हो या दूसरे रिसोर्सेज का हो, इसके लिये मुहिया करें।

अगर आप यह कहें कि इसके लिये रिसोर्सेज बताओ—तो मैं यह कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में रिसोर्सेज की कमी नहीं है, सिर्फ मोबिलाइज करने की बात है। मैं बार बार उसी बात को कहूंगा हालांकि वह रेपिटीशन होगी कि रिसोर्सेज हैं, उनको निकालने की बात है। वे रिसोर्सेज क्या हैं—मैं बार बार कह चुका हूं—एक हजार करोड़ रुपया एल० आई० सी० के पास पड़ा है, एल० आई० सी० के उस रुपये को एक साल के लिये, दो साल के लिये आप एक फेस्ड प्लान बना कर लगायें। जिनके पास मकान नहीं हैं, उनको बनाने के लिये 500 रु० या 1000 रुपया दें। आप कहेंगे कि 500 रु० में या एक हजार रुपये में क्या मकान बनेगा। मैं एक मिसाल देना चाहता हूं—

[श्री रणधीर सिंह]

साउथ इण्डिया में कोयम्बटूर एक जगह है, वहां एक जी० डी० नायडू नाम के एक सज्जन हैं, जो पहले इण्डस्ट्रीयलिस्ट हुआ करते थे। उन्होंने मुझे एक मकान दिखाया और चेयरमैन साहब, आप यकीन करिये, 24 घंटे क्या 8 घंटे में मकान बनाकर दिखा दिया—उसमें एक कमरा और एक रसोई है, कौरुगेटेड शीट्स की मदद से उसको बनाया गया। उन्होंने मुझे 500 रु० का मकान दिखाया, हज़ार रुपये का मकान दिखाया, वह आदमी नहीं विजार्ड है, बड़े दिमाग का आदमी है। मैं रिकमेण्ड करूंगा कि उस आदमी की स्कीम गरीब जनता के लिये, देहात के हरिजनों के लिये, बैकवर्ड किसानों के लिये, बल्कि तमाम देश के लिये एक पैटर्न स्कीम बन सकती है। आप उसको बुलाकर उसकी बात को सुनें—मैंने खुद वह चीज़ देखी है। जो मकान पांच हज़ार और चार हज़ार में नहीं बनता, उसके नक्शे के मुताबिक मैं समझता हूं कि हज़ार और पांच सौ रुपये में बन सकता है। अगर देश के लिये एक ऐसी स्कीम बनाई जाय, तो हमारे देश का जो यह कलंक है, वह दूर हो सकता है।

एक बात चेयरमैन साहब, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे देश का किसान जब खुशहाल होगा तो सारी चीजें, जितना रिसेशन है, मन्दीपन है, वह दूर हो जायगा। सब से बड़ी जरूरत इस बात की है कि क्रेडिट फैसिलिटीज़ देहात में किसानों के लिये काफ़ी नहीं हैं। मैं फाइनेन्स मिनिस्टर साहब की तारीफ करता हूं कि पीछे बजट में जो प्रावीज़न था, उससे ज्यादा इस बार रखा गया है, इस बार किसान की तरफ़ तवज्जह दी गई है, लेकिन जब तक आप एक हद मुकर्रिर नहीं करेंगे—पांच साल या दस साल की—सारे देश में किसान की जितनी ज़मीन है, जिस पर पानी नहीं है, उसके लिये एक कमीशन मुकर्रिर करवा कर हिसाब लगायेंगे कि कितनी जमीन है। जिस पर पानी आ सकता है, कितनी ज़मीन है जिस पर ट्यूबवेल से पानी आ सकता है, कितनी ऐसी है जिस पर नहरों से पानी आ सकता है, इन सब का तखमीना बना कर और फिर एक फेसेड प्रोग्राम बना कर कि पांच या सात साल में हमें इस ज़मीन पर पानी लाना है, अगर काम किया जाय, तो मैं आपको यकीन दिलाऊं ऐसी ज़मीन जहां पानी आता है, उसमें एक बीघे में 15 मन या 10 मन अनाज किसान पैदा करता है और जब पानी नहीं था तो 20 सेर भी पैदा नहीं होता था। यह सिर्फ पानी की ही बरकत है। इस लिये पानी लाने के वास्ते गवर्नमेन्ट के ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज़ को उस तरफ़ डाइवर्ट किया जाय।

इसके साथ ही एक और कड़ी बात जो आज किसान को दुखी करती है, उसको चीजें तो मिलती हैं, लेकिन महंगी मिलती हैं, वह ले नहीं सकता है। जैसे फर्टिलाइज़र है। फर्टिलाइजर से पैदावार बढ़ती है लेकिन वह फर्टिलाइजर इतनी कीमती है कि किसान उसे खरीद नहीं सकता है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर फर्टिलाइजर सब्सिडाइज्ड रेट पर किसानों को दी जाए तो उससे किसानों का और देश का हित होगा। इससे दुगुनी और चौगुनी पैदावार हो सकेगी। जहां और चीजों को आप सब्सिडाइज़ करते हैं उसमें इससे बड़ा और कोई काम नहीं हो सकता। इतनी कीमत में फर्टिलाइजर को किसान नहीं ले सकता है।

अब यह बात भी साबित हो गई है कि बैलों से जो हल खींचा जाता है उससे उतनी पैदावार नहीं होती जितनी कि ट्रैक्टर से खेती करके हो सकती है। एग्रीकल्चर के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स का और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ की एथारिटीज़ का यह आब्जर्वेशन है। यह बात भी ठीक है, जैसा कि एक भाई ने कहा कि एक किसान ट्रैक्टर ले सके, यह भी मुश्किल है। आप 20–20, 25–25 घरों को एक एक ट्रैक्टर दें। किसान की आज ट्रैक्टर के लिए बड़ी जबर्दस्त डिमान्ड है। आज 5 हजार का ट्रैक्टर 20 हजार में खरीदना पड़ता है। मेरा सुझाव यह है कि जो एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन है उसकी मार्फत सरकार देहातों में ट्रैक्टर्स कोआपरेटिव बेसिस पर सरमाएदार लोगों को हैंड-ओवर कर दे। साथ ही इस देश

में ज्यादा से ज्यादा ट्रैक्टर बनाए जाएं और मीडियम साइज के ट्रैक्टर कम कीमत पर, तीन हजार या 5 हजार रुपए में किसानों के दिए जायं। फिर आप देखें कि देश में कितनी पैदावार बढ़ती है।

तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि किसी तरह से भी हो, जितना देश का रुपया है उसे आपको इस गरीब देश को मजबूत बनाने के लिए लगाना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि जितनी बैंकें हैं उन सारी बैंकों का रुपया नेशनलाइज करके इधर लगाया जाए। जितना एक्सपोर्ट इम्पोर्ट है, उसको नेशनलाइज किया जाए और इस तरफ वह रुपया लगाया जाए। इसी तरह से प्लान्टेशन का जितना रुपया है वह भी नेशनलाइज करके इधर लगाया जाए।

एक बात जिसको कि मैं पहले भी कह चुका हूं, वह यह है कि आपने किसान के ऊपर सीलिंग की है, तीन लाख से ज्यादा की जायदाद एक किसान नहीं रख सकता है क्योंकि 30 स्टैंडर्ड ऐकड़ जमीन उसके लिए आपने मुकर्रर कर दी है। आम तौर पर 2–3 लाख रुपया इतनी जमीन की कीमत होती है। विधान में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। जब दो तीन लाख से ज्यादा की जायदाद किसान नहीं रख सकता तो शहर में रहने वाले जो सरमाएदार हैं, कारखानेदार हैं, बिजनेस करनेवाले हैं या तनख्वाह पाने वाले हैं, उनके पास भी दो तीन लाख से ज्यादा की जायदाद नहीं होनी चाहिए। आप कहेंगे कि क्यों यह बात कहते हो? मैं इस वास्ते कहता हूं कि किसान की जायदाद की सीलिंग अगर आपको मुकर्रर करनी है तो फिर शहर में जो गैर किसान हैं उनकी जायदाद की सीलिंग भी आप मुकर्रर करें। दो तीन लाख की जायदाद को छोड़ कर बाकी जायदाद को आप नेशनलाइज करें। यह बड़ा इन्कलाबी नारा है लेकिन मैं कहता हूं कि इसकी बड़ी जरूरत है। जब दूसरों के फंडामेन्टल राइट्स पर आप कुछ नहीं करते तो किसान के लिए ही क्यों करते हैं? फिर दूसरों की जायदाद पर भी सीलिंग होनी चाहिए, चाहे वह किसी प्रकार की भी आमदनी हो। एक तरफ तो एक आदमी की तनख्वाह 65 और 70 रुपए है और दूसरी तरफ, जैसा कि कल कहा गया था, जो बड़े-बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स बिरला और टाटा हैं उनके यहां 40 हजार रुपए माहवार पर भी मुलाजिम हैं। तो इन तनख्वाहों पर भी सीलिंग होनी चाहिए। आज जो डिसपैरिटी तनख्वाहों में है, वह भी दूर हो जानी चाहिए। फिर जो फाजिल रुपया हो उसे नेशनल डवलपमेन्ट के लिए इस्तेमाल किया जाए।

मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, मेरा खयाल यही है कि अबकी दफा बजट में जो बातें रखी गई हैं वह बेहद तारीफ करने लायक हैं, आज के हालात में यह बहतरीन बजट है। लेकिन आगे के लिए जितनी भी देश की रिसोर्सेज हैं, सरमाएदार, कल-कारखानेदार, बैंक्स, प्लान्टेशन, इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट, आप सारे के सारे सरमाए पर सीलिंग मुकर्रर करें, उसको नेशनलाइज करें और जितना रुपया हासिल हो वह देश के फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाए। यह बात तो नहीं कही जा सकती कि देश में तरक्की नहीं हुई है लेकिन सोशलिस्ट कन्ट्रीज अपने को जो कहते हैं, जैसे स्वीडन, डेनमार्क, इजराइल और जैसा कि बख्शी जी ने कहा, जरमनी ने 10 साल में ही खंडहरों से अपने को फिर बना लिया, उसी तरह से हमारा देश भी बन सकता है लेकिन रिसोर्सेज के लिए आप रेवोलयूश्नरी मेजर्स उठाएं और फेज्ड प्रोग्राम बनाएं जैसे 5 साल में सिंचाई के लिए पानी का इन्तजाम करना है। देहातों के गरीब किसान, मजदूर के हित के लिए मकान बनाने, दवा और तालीम देने का प्रोग्राम होना चाहिए? मैं चाहता हूं कि अगले बजट में यह सब कुछ किया जाए। बाकी इस मर्तबा जो बजट फाइनेन्स मिनिस्टर ने यहां पर पेश किया है, मैं उसकी तारीफ करता हूं और उसकी पुरजोर हिमायत करता हूं।

श्री यशवन्त सिंह कुशवाह (भिंड) : माननीय सभापति जी, अभी दो माननीय सदस्यों

[श्री यशवन्त सिंह कुशवाह]

ने, नर्मदा नदी का पानी राजस्थान और गुजरात को मध्य प्रदेश द्वारा नहीं दिया जा रहा है, इसकी शिकायत की है। मैं स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश को किसी भी प्रान्त विशेष से राग द्वेष नहीं है। वह सारे देश को एक मानता है और सारे देश की तरक्की में सहायक बनना चाहता है, लेकिन नरबदा का पानी जो हमारी आवश्यकता के लिए है, हमारे कैचमेन्ट एरिया का है, हमारे हिस्से में से नरबदा में हमारे प्रदेश की सीमा तक बहा है उस अपने पानी को हम स्वत: इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा पिछड़ा हुआ प्रान्त है, वहां पर आदिवासी और हरिजन रहते हैं, उनके विकास में मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट दिलचस्पी रखती है। इसलिए हम न्याय चाहते हैं। मैं केन्द्रीय सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में चूंकि गैर-कांग्रेसी गवर्नमेन्ट है इसलिए राजस्थान व गुजरात भी जो कांग्रेसी गवर्नमेन्ट्स हैं उनके कहने पर, उनके दबाव में आकर मध्य प्रदेश को न सताया जाए। मध्य प्रदेश बड़ी विनम्रता से निवेदन करना चाहता है, कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट जो कांग्रेस की है, उसके दबाव में आकर हम अपने हिस्से के पानी की एक बूंद भी नहीं देंगे। हम केवल इन्साफ चाहते हैं।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय वित्त मन्त्री जी ने अगले वर्ष से चौथी पंच वर्षीय योजना के चालू होने का संकेत दिया है, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन जो पिछली पंच वर्षीय योजनाएं रही हैं वे फेल हुई हैं। उन पर यद्यपि अधिक धन व्यय किया गया परन्तु ग्रामों के विकास की मुख्य भूमिका ठीक ढंग से अदा नहीं की गयी। हमारे देश की बहुसंख्यक जनता गांवों में रहती है, उसका विकास नहीं हुआ। वहां पर सड़कें नहीं हैं, वहां बीज और पानी नहीं मिल रहा है, सिंचाई के साधन नहीं दिए गए हैं, बहुत से गांवों को पीने तक का पानी नहीं मिला है। जो शिक्षा दी जा रही है वह केवल बेकारों की संख्या बढ़ाने वाली है। इस प्रकार से, गांवों का जो आदर्श नक्शा बनाने की बात थी, वह काम नहीं किया गया है। गांधी जी ने जो कहा था कि "गांवों की ओर जाओ", हमारा देश गांवों का है, उस नारे की बिल्कुल उपेक्षा हुई है। आप पंच वर्षीय योजनाएं अवश्य चालू करिए लेकिन मेरा निवेदन है कि जो अपव्यय हो रहा है उसको न होने दीजिए और गांवों के वास्तविक विकास को खास तौर से ध्यान में रखिये।

वित्त मन्त्री जी ने कृषि उत्पादन बढ़ाने की बात कही है, उसमें कहा है कि नयी कृषि योग्य भूमि का रकबा बढ़ाया जाएगा, 1.50 लाख एकड़ से बढ़ाकर 2.10 लाख एकड़ किया जाएगा। यह बड़ी अच्छी बात है, इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं लेकिन साथ में यह निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले वर्ष से मध्य प्रदेश गवर्नमेन्ट बराबर इस बात के लिए आग्रह करती आ रही है कि हमारे पास बहुत बड़ी तादाद में उपजाऊ कृषि योग्य भूमि है, हमें साधन दीजिए उसे आबाद करने को, लेकिन आजतक वह साधन नहीं दिए गए। अगर वे साधन दिए जायं तो केवल मध्य प्रदेश में ही इतना अधिक अन्न उत्पादन बढ़ सकता है कि वही देश में जो अन्न की कमी है उसको पूरा कर दे। इसलिए मेरा निवेदन है कि अब जो कृषि भूमि का रकबा बढ़ाया जा रहा है, और खेती की तरक्की के लिए जो साधन बढ़ाए जा रहे हैं और इसके सम्बन्ध में मध्य प्रदेश की जो मांग है, जमीन को आबाद करने के लिए मध्य प्रदेश द्वारा जो धनराशि की मांग है, उसमें उदारतापूर्वक मध्य प्रदेश को सहायता देने का कष्ट करें।

18.20 Hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

कृषि के सिलसिले में छोटी सिंचाई योजनाओं की अब तक उपेक्षा होती रही है। इस सिलसिले में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब माननीय सिंचाई मंत्री डा० राव ग्वालियर मध्य प्रदेश में गये थे तो उन्होंने छोटी सिंचाई योजना—सिंध नदी पर मगरौनी के पास बांध बांध कर उसे नहर द्वारा हरसी डैम तक पहुंचाने की मौके पर जाकर देखी थी, इसको

बहुत पसन्द किया था और वहीं मौका देख कर उन्होंने हजारों लोगों के बीच में वादा किया था कि दो, तीन महीने के भीतर, भीतर इस योजना का काम शुरू हो जायगा। लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज तक उस योजना को न तो स्वीकृत घोषित किया गया और न ही उसे प्रारम्भ किया गया। इतनी छोटी योजना और इतनी अधिक उपयोगी योजना जो थोड़े खर्चे में कई गुना लाभ दे सकती है, सारे देश में सिंचाई का जो मापदंड है उन मापदंडों की दृष्टि से भी जो एक उपयोगी योजना है, और जब ऐसी योजना को अभी तक हाथ में नहीं लिया गया है तो यह विश्वास करना बड़ा मुश्किल होता है कि जो बातें कही जाती हैं उन पर अमल किस सीमा तक किया जायेगा? मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने उस योजना का समर्थन कर दिया है और भारत सरकार से प्रार्थना की है कि उसे हाथ में लिया जाये और इसलिए मैं चाहता हूं कि उसे कार्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए और सिंध नदी पर मगरौनी के पास बांध बांध कर उसे नहर द्वारा हरसी डैम तक पहुंचाने की यह योजना पूरी की जानी चाहिए।

माननीय वित्त मंत्री ने कृषि उत्पादन के सिलसिले में बड़ी आशाएं प्रकट की हैं लेकिन मुझे यह कहते हुए बड़ा आश्चर्य होता है कि जिस रासायनिक खाद के बारे में वे बड़े आशावान हैं उसका नमूना उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की सेवा में पेश करूंगा जिसको कि मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र से लाया हूं। किसानों को किस तरीके की खाद दी जाती है वह उसे देखने से मालूम हो जायेगा। उसमें खाद का अंश शायद 10 प्रतिशत है और बाकी का रेती व कचरा है जो कि उसमें मिला हुआ है और रेती उसमें बहुत मिली हुई है। अब इस किस्म की रद्दी खाद देकर खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि की आशा करना व्यर्थ है। इस तरह से हमारे किसानों के साथ बड़ा अन्याय होता है जिसकी ओर सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए और उसका निदान करना चाहिए।

पंचवर्षीय योजनाओं की सफलता के लिए माननीय वित्त मंत्री ने पूंजी वालों से और जो बड़ी आमदनी वाले लोग हैं उनसे पूंजी लगाने की आशा की है। उनसे उन्होंने अपेक्षा की है कि वह पंचवर्षीय योजना को कामयाब बनाने के लिए अपनी पूंजी इसमें लगायें। मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्रपोजल तो अच्छा है लेकिन पूंजी को आकर्षित करने का तरीका सरकार द्वारा ठीक नहीं अपनाया गया है। पूंजी के आकर्षण का तरीका अगर अपनाया जाय तो जो पूंजी विदेशों में लगी है वह भी इस देश में आ सकती है और जो पूंजी छिपी हुई है वह भी प्रकाश में आ सकती है। इस बारे में इस तरीके की नीति अपनाई जानी चाहिए जिससे लोगों को शंका, कुशंका न हो। उनकी पूंजी सुरक्षित रहेगी इसका उन्हें विश्वास हो जाये तभी वह छिपी हुई पूंजी बाहर आ सकेगी।

जो 590 करोड़ रुपया प्रदेशों के विकास के हेतु इस बजट में बांटने की बात कही गई है उसके सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो प्रदेश ज्यादा पिछड़े हुए हैं उनको उसमें अधिक हिस्सा दिया जाना चाहिए। जैसे उदाहरण के रूप में मध्य प्रदेश का सारा का सारा आदिवासी ऐरिया एक बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है तो उसको विशेष तौर पर सहायता देनी चाहिए।

बजट को देखने से एक बात यह साफ़ प्रकट होती है कि दिनोंदिन देश की आर्थिक स्थिति का संतुलन बिगड़ता जा रहा है। मुद्रा का भी अवमूल्यन हुआ लेकिन फिर भी हम अपने भावों पर नियन्त्रण नहीं रख सके। विदेशी मुद्रा कोष में से 6 करोड़ रुपये की अभी कमी की गई है और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में से भी अभी 9 करोड़ डालर उठा लिये गये हैं। इसी तरह से देश पर कर्ज भी बहुत बढ़ गया है। अब इस तरह से दिन प्रतिदिन हमारे देश की आर्थिक स्थिति अगर बिगड़ी तो फिर हम प्रगति कैसे कर सकेंगे यह एक बड़ी शंका का विषय है। जबकि देश पर कर्जा बढ़ गया है और

[श्री यशवन्त सिंह कुशवाह]

आर्थिक दशा सुधारने की आवश्यकता है तब टैक्स लगाने के स्थान पर और आर्थिक स्थिति को और भी अधिक कमजोर कर देने के बजाय मेरा सुझाव यह है कि देश में आय के जो नये स्रोत हैं, जो भूगर्भ में और समुद्र तल में हैं, उस सम्पत्ति को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। इनका अधिक से अधिक उपयोग किया जाना चाहिए।

उद्योगों के सम्बन्ध में बहुत सी बातें कही गई हैं लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि हमें फिलहाल राष्ट्रीयकरण की बात छोड़ देनी चाहिए क्योंकि अनुभव से सिद्ध हुआ कि सरकारी क्षेत्र में चलने वाले जितने उद्योग हैं, वह या तो घाटे में चल रहे हैं या नाममात्र का लाभ देकर चल रहे हैं। देश में उद्योग अगर बढ़ाने हैं, देश के बेकारों को अगर धंधा दिलाना है, तो यह अत्यन्त जरूरी है कि हर क्षेत्र के चाहे वह प्राइवेट सैक्टर हो, चाहे कोआपरेटिव सैक्टर हो, हर क्षेत्र को उद्योग विस्तार के लिए पूरी सुविधाएं दें।

इस सिलसिले में एक बात और करनी चाहिए, श्रम नीति में सुधार करने के लिए। अभी हर जगह के कारखानों में 'इंटकी यूनियन' को मान्यता देने की नीति कांग्रेसी सरकार की है, और हर जगह उसने इंटकी यूनियन को मान्यता दी हुई है। यह एक गलत नीति है। नई नीति उसके स्थान पर अपनाई जानी चाहिए। हर क्षेत्र में जो भी कारखाने हों उनकी यूनियंस का चुनाव श्रमिकों के गुप्त मतदान से होना चाहिए, ताकि मजदूरों के सही प्रतिनिधि उन यूनियंस में आ सकें। अभी ऐसी व्यवस्था न होने के कारण मौजूदा उद्योगों में काम कर रहे मजदूरों में असन्तोष पैदा होता है और जिसकी वजह से यह उद्योग धंधे ठीक तरीके से नहीं चल पाते हैं। नई नीति से उसमें सुधार हो सकता है।

मेरा निवेदन है कि राजनीति किसी बनिये की दुकान नहीं है कि जहां बांटों के हिसाब से माल तौल-तौल कर बेचा जाता है। यह तो असल में ताकत और हिम्मत का खेल है। इसमें शक्ति की आवश्यकता होती है। जब तक शक्ति नहीं है तब तक शासन का काम सफलता के साथ नहीं चल सकता है। इस शक्ति संग्रह के लिए ध्यान नहीं दिया गया है। न तो अणु अस्त्र बनाये गये हैं और न ही देश की सैनिक शक्ति को जितनी मात्रा में बढ़ाना चाहिए उतनी मात्रा में बढ़ाया गया है। इस वर्ष के बजट में मैं मानता हूं कि कुछ ध्यान दिया गया है लेकिन पर्याप्त नहीं है क्योंकि जो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी नये समुद्री बेड़े को बढ़ाने की हमारे सिर पर आई है उसकी तरफ़ ध्यान नहीं दिया गया है। वह जिम्मेदारी यह है कि हमारा समुद्री बेड़ा अत्यन्त मजबूत होना चाहिए नहीं तो हिन्द महासागर में चीन और जापान आ जायेंगे और हमारी स्थिति बहुत कमजोर हो जायगी और हम असमर्थ हो जायेंगे।

इस बात की बहुत बड़ी आवश्यकता है कि देश के जिन हिस्सों को हमने खो दिया है उन्हें हम पुनः पाने का प्रयत्न करें। कश्मीर का तथाकथित आजाद कश्मीर कहा जाने वाला इलाक़ा पुनः हमारे हाथ में आना चाहिए। इसी तरह चीन द्वारा हथियाये गये प्रदेश भी हमारे हाथ में पुनः वापिस आने चाहिएं। कच्छ पर हम दबाये जा रहे हैं और वह इसलिए दबाये जा रहे हैं कि हमें कमजोर समझा जा रहा है। जाहिर है कि जब तक हम ताक़त नहीं बढ़ायेंगे तब तक हमारा काम नहीं चल सकता है।

बस मैं एक मिनट में समाप्त किये दे रहा हूं। शासन की सफलता के लिए दो बातें अत्यन्त आवश्यक होती हैं। एक है शाख और दूसरी है धाक। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि हमारी गवर्नमेंट इन दोनों ही बातों में सफल नहीं हो रही है और उसकी शाख भी नहीं है और धाक भी नहीं है। हालत यहां तक हो गई है कि उसके कहने में मातहत आई० सी० एस० अफसर भी नहीं हैं। आई० सी० एस० अफसरों में अनुशासन गिरा है। सर्विसेज में अनुशासन व कार्यक्षमता का रहना

किसी भी शासन की सफलता के लिए नितान्त आवश्यक होता है। इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। मुझे आशा है कि सरकार इन चीजों की ओर अवश्य ध्यान देगी।

माननीय वित्त मंत्री को मैं इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने शराब पर टैक्स लगाया है। उसके लिए वह बधाई के पात्र हैं लेकिन मैं उनसे यह अवश्य चाहूंगा कि पोस्टकार्ड पर कीमत उन्हें नहीं बढ़ानी चाहिए और मैं आशा करता हूं कि वह पुनः इस पर विचार करेंगे और पोस्टकार्ड की कीमत केवल 5 पैसे कर देने की कृपा करेंगे।

DR. MELKOTE (Hyderabad) : I congratulate the hon. Finance Minister for the excellent budget which he has presented before the House and for having created confidence in the country.

MR. DEPUTY-SPEAKER : He may resume his speech tomorrow.

18.29 Hrs.

CORRECTION OF ANSWER TO S. Q. No. 111 RE-STUDY OF HINDI IN SCHOOLS IN MADRAS

THE MINISTER OF EDUCATION (DR. TRIGUNA SEN) : In reply to a Starred Question No. 111 by Sarvashri K. N. Pandey, Rabi Ray, Kanwarlal Gupta, R. S. Vidyarthi, Ram Gopal Shalwala, N. S. Sharma, Jugal Mondal, C. K. Bhattacharyya, Mohsin and Deo Rao Patil, answered in this Sabha on 16th February, 1968, my colleague Shri Bhagwat Jha Azad had stated that no official intimation regarding the Resolution on three-language formula passed by the Madras Legislative Assembly had been received in the Government of India. It has later been found that a copy of such a Resolution had been received. The matter is under consideration of the Government. I regret the inconvenience to the Honourable House.

Sir, I give my sincere apologies for the incorrect reply given to the question earlier.

18.30 Hrs.

*STUDY OF HINDI IN SCHOOLS IN MADRAS

श्री शिव कुमार शास्त्री (अलीगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा अभी माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा प्रश्न 16 फरवरी को यहां पर मद्रास में जो अनिवार्य हिन्दी शिक्षा के सम्बन्ध में घोषणा की गई थी उसके विषय में पूछा गया था, और उसका जो उत्तर दिया गया था वह वस्तुतः बहुत ही असन्तोषजनक था। अब उन्होंने स्पष्टीकरण कर दिया है, इससे थोड़ी-सी शान्ति प्राप्त हुई है। वास्तव में यह घोषणा इस प्रकार की थी जिसने सारे देश में एक खलबली मचा दी थी, और केन्द्र का अनुशासन और नियन्त्रण कितना शिथिल है कि उस की भावना के विपरीत एक प्रान्त ने अपना सर उठा कर इस प्रकार की घोषणा कर दी है, यह प्रश्न उसकी प्रतिक्रिया थी।

स्वराज्य आन्दोलन के समय में ही राज्य भाषा का यह प्रश्न लगभग निर्णीत हो चुका था और उस समय पर महात्मा गांधी ने दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा की स्थापना की थी, और उस समय पर प्रसिद्ध नेता, जो आज भी संसार में हैं, श्री राजगोपालाचार्य ने अपने भाषण में इस सभा की स्थापना के समय हिन्दी का नाम स्वराज्य भाषा रखने का प्रस्ताव किया था और कहा था कि यही एक भाषा है जिसके आधार पर हम अपने स्वराज्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो यह दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा स्थापित हुई थी उसने वहां पर हिन्दी प्रचार में बहुत ही उपयोगी कार्य किया, जिसकी थोड़ी सी जानकारी मैं इस सभा को देना चाहता हूं, और वह इस प्रकार से है :

इस सभा द्वारा परिचालित परीक्षाओं में गत पांच वर्षों में 32 हजार से लेकर 35 हजार तक छात्र सम्मिलित होते रहे हैं। सन् 1967 में 25,509 छात्र, मद्रास शहर के अतिरिक्त, इन परीक्षाओं में सम्मिलित हुए, और अकेले मद्रास शहर से 7,273 छात्र इस की परीक्षा में सम्मिलित हुए। और इसमें भी यह बात उल्लेखनीय है कि महिलाओं की संख्या इन

*Half-An-Hour Discussion.